हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 अगस्त, 1972

खण्ड 2, अंक 6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 22 अगस्त, 1972

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)1
कार्य मंत्रणा समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन	(6)7

बिल –	
हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 3) – 1972	(6)8
चौ. अब्दुर रजाक खां द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	(6)53
बिल –	
पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्सेशन आफ सेल्ज) हरियाणा अमैण्डमैंट – 1972	(6)55
हरियाणा वित्त निगम के 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे पर चर्चा	(6)59
सदन की बैठक के समय में वृद्धि	(6)62
हरियाणा वित्त निगम के 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे पर चर्चा (पुनः आरम्भ)	(6)62
हरियाणा भाण्डागार निगम के वर्ष 1967–68 तथा 1968–69 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा	(6)65
सरकारी संकल्प	(6)69

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 22 अगस्त, 1972

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विभान भवन, सैक्टर–1 चंडीगढ़, में प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्त) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Medical, M.A., M.Ed. and B.Ed. Classes

***70. Sh. K.N. Gulati**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any Scheme before the Government to make arrangements in the near future for starting Medical, M.A., M.Ed. and B.Ed Classes for Faridabad and Ballabgarh area?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): No. Sir.

श्री के.एन. गुलाटी: क्या मुख्यमंत्री साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद मे जो गुरू गोबिन्द सिंह मैडिकल कालेज प्राइवेट खुला है, उसमें एक–एक स्टूडैन्ट के बीस–बीस हजार रूपये लिए जाते हैं हालांकि वहां पर न कोई लैबोरेट्री हे, न किसी और चीज का प्रबन्ध है, क्या वह कालेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटिड है?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, किसी कालेज को चालू करना या किसी कालेज को इजाजत देना या एफिलिएट करने का काम यूनिवर्सिटी का है। यह सरकार का काम नहीं है।

श्री के.एन. गुलाटी: मैंने जो चीजें बतायी हैं, क्या सरकार उनकी इन्कवायरी करेगी?

चौ. बंसी लाल: इन्क्वायरी करने की कोई जरूरत नहीं।

चौ. फूल चन्द: क्या मुख्यमंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि हास्पिटल्ज में या मैडिकल कालेज में जो ऐक्सरे की मशीन खराब हो जाती है उसकी रिपेयर कराने की मंजूरी हासिल करने के लिए सैक्रेट्रीयेट में दो–अढ़ाई महीने लग जाते हैं? क्या उन मशीनों को ठीक कराने के इख्तियारात डाक्अर इन्चार्ज को देंगे?

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब यह सवाल इससे कैसे पैदा हो गया। यहां मूल प्रश्न में तो मैडिकल कालेज खोले की बात पूछी जा रही है कि फरीदाबाद में खुलेगा या नहीं।

श्री निहाल सिंह: चीफ मिनिस्टर साहब ने गुलाटी साहब के सवाल के जवाब में बताया कि फरीदाबाद में कोई कालेज खोलने का विचार नहीं है। क्या किसी और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एम.एड. क्लासिज खोलने का विचार है, और खास कर नारनौल में?

चौ. बंसी लाल: इस साल कोई इरादा नहीं है।

चौ. चाँद राम: क्या सरकार के नौलेज में यह है कि वहां पर दाखिला हो रहा है?

चौ. बंसी लाल: हमारे नौलेज में नहीं है।

चौ. फूल चन्द (मुलाना): क्या अम्बाला में कोई मैडिकल कालेज खोलने का सरकार ने विचार किया है?

चौ. बंसी लाल: जी नहीं।

श्री अमर सिंह: क्या फरीदाबाद में कोई ऐसा प्राइवेट कालेज है जिसमें स्टूडैन्टस से पांच–पांच सौ रूपये लेकर दाखिले हुए हैं?

चौ. बंसी लाल: मेरी समझ में तो नहीं आता, एक पांच सौ रूपये बता रहा है और एक कई हजार बता रहे हैं। इन्ही को ही पता होगा।

Evasion of Sales Tax

***80. Sh. K.N. Gulati**: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the total number of cases of evasion of sales tax detected together with the number of cases wherein the goods were seized and penalties imposed at the Sales Tax Check Barriers in the State during the year 1971-72;

(b) whether there are any cases where the goods seized as referred to in part (a) above were released without payment, if so, the reasons thereof; and

(c) the number of appeals preferred in the cases referred to in part (a) above together with the number of such appeals accepted by the first appellate authority and the second appellate authority?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) during 1971-72] 169 case of evasion of sales tax were detected at the Sales Tax Check Barriers in the State. Out of these, in 17286 cases, goods were seized and penalties imposed.

(b) Yes, there were 18 cases. In 3 cases goods were seized but were released without the imposition of tax/fine for the reasons that in one of them the goods pertained to a dealer in Punjab and in the other 2, the Officer-in-Charge had satisfied himself form the documentary evidence adduced before him that the provisions of law had not been violated. in the remaining 15 cases the goods, were released pending disposal of references made to the Deputy Excise and Taxation Commissioner concerned under section 23 of the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

(c) a total number of 109 appeals were filled the parties. Out of these, 80 appeals were accepted by the first appellate authority and one by the second appellate authority.

श्री के.एन. गुलाटी: क्या मुख्यमंत्री साहब बतायेंगे कि उनके पास कोढ 1970 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है जिसके

अनुसार सरकार बैरियज्र पर गुडज सीज भी नहीं कर सकती और पैनलटी भी नहीं लगा सकती?

चौ. बसीं लाल: मेरे नोटिस में ऐसी कोई रूलिंग नहीं है।

श्री अमर सिंह: जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया है कि सन् 1971–72 में 79169 केसिज टैक्स इवैजन के पकड़े गये और उनमें से 17286 पर पेनेलटी लगायी गई तो बाकी केसिज की क्या पोजीशन है?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब मैंने यह बताया है कि 79169 केसिज में से 17286 केसिज में गुडज सीज लिये गये और पैनलटी इम्पोज की गयी, बाकी केजिस में डीलर से टैक्स या फाइन वसूल किया गया।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the Honourable Chief Minister as to whether the Government will try to go into the reasons for such a large number of cases of sales tax evasion if so, what measures the Government proposes to adopt to put an end to the evasion of sales tax?

Ch. Bansi Lal: This is because of the measures that the Government has adopted that such a large number of cases have been detected. Sir, 19 sales tax check barriers have been established at various places in the State and it is due to the working of these barriers that we have been able to get about Rs. 90 lakhs and that is what we can do.

श्री अमर सिंह: क्या चीफ मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि जो इतनी बड़ी तादाद में टैक्स इवेजन हुआ है और फिर गवर्नमैंट ने उनमें काफी केसिज को डिटैक्ट किया है और उन पर पैनलटी लगायी है, उनसे सन् 1971–72 में कुल कितनी रकम कौलैक्ट हुई है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौ. फूल चन्द: टैक्स इवेजन से सन् 1971–72 में कुल कितनी रकम कौलैक्ट हुई?

चौ. बंसी लाल: ये अलग–अलग तीन मदें होती हैं एक होती है गुडस सीजड जिससे 51 लाख 50 हजार रूपये, पैसेन्जर टैक्स से 10 लाख 75 हजार और सैल्ज टैक्स से 21 लाख 64 हजार आये। एक ही बैरीयन पर तीन किस्म के अधिकारी बैठते हैं। तीनों चैक करते हैं। इस प्रकार से यह रकम 83 लाख 89 हजार के करीब बनती है।

श्री के.एन. गुलाटी: क्या मुख्यमंत्री साहब बताएंगे कि जो 23 नवम्बर की रूलिंग है क्या उस पर वे अमल करेंगे?

चौ. बंसी लाल: हम कोई रूलिंग इस तरह की मांगने वाले नहीं है और न अमल ही करेंगे।

श्री अमर सिंह: जिस–जिस बैरीयर पर टैक्स इवेजन हुई है, क्या उन एम्पलाइज के खिलाफ सरकार कोई ऐक्शन लेगी?

चौ. बंसी लाल: उनके खिलाफ सरकार क्यों ऐक्शन लेगी? उन्होंने तो शाबाशी का काम किया है जो गवर्नमैंट को केसिज पकड़ कर फायदा पहुंचाया है?

चौ. रिजक राम: क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि व्यापारी लोग किसानों के नाम से अनाज लोड करके भेजते हैं और बिल्टीज भी उनके नाम होती है? वे सब फर्जी होती है, किराया खुद देते हैं, उनके एकाउन्टस से जाता है लेकिन टैक्स से बचने के लिए ऐसा करते हैं।

चौ. बंसी लाल: लार्ज स्केल पर ऐसी कोई कम्पलेन्अस हमारे पास नहीं आयीं। ग्रोयर अनाज हमेशा अपने नजदीकी मंडी में ही ले जाता है और चौ. रिजक राम जी के इलाके के लोग दिल्ली स्टेट की मंडियों में ले जाते हों तो मुझे पता नहीं।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, मैंने सवाल यह नहीं किया था कि ग्रोयर ले जाते हैं। मैंने तो सवाल यह किया था कि व्यापारी ग्रोयर के नाम से फर्जी बिल्टी बनवा कर अपना खुद का माल ले जाते हैं। क्या इस किस्म की कोई शिकायत उनके नोटिस में आयी है?

चौ. बंसी लाल: ये बैरियर्ज इन्हीं चीजों को चैक करने के लिए बने हुए हैं।

श्री हरि सिंह: टैक्स इवेजन को रोकने के लिए जो कुरप्शन होती है उसको चैक करने के लिए क्या गवर्नमैंट कोई नान–आफिशियल मैम्बर्ज की कमेटी बनाने पर विचार कर रही है?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, टैक्स इवेजन को खत्म करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है पर नान–आफिशियल मैम्बर्ज की कोई कमेटी बनाने का सरकार का इरादा नहीं है।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the Honourable Chief Minister if any complaints were received by the State Government that traders in the grab of growers exported some foodgrains to mandis which are adjacent to the areas of Haryana and Delhi?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, हमारे नोटिस में तो ऐसी कोई कम्पलेन्ट नहीं आयी लेकिन अगर आनरेबल मैम्बर कोई स्पैसीफिक केसिज इस किस्म के हमारे नोटिस में लायेंगे तो जरूर ऐक्शन लेंगे।

चौ. राम लाल वधवा: करनाल दिल्ली रोड़ पर जो बैरियर है उस पर हर ट्रक से पांच रूपये लिये जाते हैं और बगैर पैसे लिए गुजरते नहीं देते हैं। क्या यह सरकार के नोटिस में है और सरकार इस बात को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है?

चौ. बंसी लाल: जनरल कम्पलेन्टस तो हमारे पास बहुत आती है कि हर बैरियर पर पैसे लिए जाते हैं पर जब तक कोई

स्पैसिफिक इल्जाम हमारे नोटिस में न लायें, एफिडेविट न दे, शहादत न दे तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, दिल्ली में फूड–ग्रेन्ज पर कोई सेल्ज टैक्स नहीं है और पंजाब में केवल एक फीसदी सेल्ज टैक्स है। पंजाब से या दिल्ली से लगते हुए इलाकों के लोग सेल्ज टैक्स से बचने के लिये, अपना अनाज हरियाणा की मण्डियों में बेचने की बजायें, पंजाब या दिल्ली की मण्डियों में ले जाते हैं जिससे हमारी स्टेट को कम आमदनी होती है और व्यापारियों के कारोबार पर भी असर पड़ता है। क्या यह बात चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में है? अगर यह बात उनके नोटिस में है तो चीफ मिनिस्टर साहब क्या इस और गौर फरमायेंगे कि जो सेल्ज टैक्स हरियाणा में फूड–ग्रेन्ज पर है, वह पंजाब और दिल्ली के बराबर हो?

चौ. बंसी लाल: यह बात मेरे नोटिस में है और बजाये इसके कि हम खुद अपना सेल्ज टैक्स छोड़ें, हमने यह केस गवर्नमैंट आफ इंडिया के साथ टेक–अप किया हुआ है कि हमारे नौर्दरन जोन में सेल्ज टैक्स की एक सी दरें हों और अलग–अलग न हों।

चौ. मनफूल सिंह: क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बतायेंगे कि हरियाणा में कौन सा ऐसा सेल्ज टैक्स का बैरियर है, जहां से

सेल्ज टैक्स की ज्यादा चोरी होती है और उसके लिये क्या प्री–काशन्ज ली गयी है?

चौ. हरद्वारी लाल: सोनीपत का ही होगा।

चौ. बंसी लाल: जी हां, और मोस्ट लाईकली राई वाला, चौ. रिजक राम के हल्के का होगा। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. रिजक राम: मुख्यमंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि सेल्ज टैक्स पंजाब, दिल्ली और राजस्थान वगैरह के ऐट पार लाया जाये। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कौन–कौन सी ऐसी आईटम्ज हैं जिन पर हरियाणा में दिल्ली और पंजाब की निस्बल सेल्ज टैक्स थोड़ा है या ज्यादा है?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, मेरे पास उन आईटम्ज के नाम यहां पर लिखे हुए नहीं है। वैसे भी यह सप्लीमैंट्री मेन क्वैश्चन से अराईज नहीं होता।

श्री के.एन. गुलाटी: स्पीकर साहब, बहादुरगढ़ के बैरियर पर सन् 1971 में एक ही समय पर दो पाटियां आयीं। एक थी जिन्दल पाईप्स और दूसरी थी हांसी की वैजिटेबल आयल्ज। हांसी वाली पार्टी के केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आयी हुई थी लेकिन दूसरी पार्टी के केस मैं कोई रूलिंग नहीं थी। इसलिये दूसरी पार्टी को 5000 रूपया जुर्माना हुआ। क्या मुख्यमंत्री महोदय इस केस की इंक्वायरी करेंगे?

चौ. हरद्वारी लाल: वह भी सोनीपत की है।

श्री निहाल सिंह: पहले यह फैसला हुआ था कि गवर्नमैंट ट्रेडर्ज की दुकानों पर रेड नहीं करेंगी। फिर यह फैसला बदल लिया गया। मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पहले जयादा टैक्स–इवेजन होती थी या फैसला बदलने के बाद अब होती है?

चौ. बंसी लाल: उस वक्त ज्यादा होती थी।

चौ. रिजक राम: क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिस साल आपने रेडज या इन्सपैक्शन बन्द रखीं और उससे पहले साल में, सेल्ज टैक्स की जो आमदनी हुई, उसमें घाटा हुआ या फायदा हुआ है?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, मेरे पास इस समय फिगर्ज तो नहीं हैं लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने दो साल तक व्यापारियों को छोड़े रखा और जब नतीजा सैटिसफैक्ट्री नहीं निकला तो हमें पुराने तरीके पर आना पड़ा।

चौ. मनफूल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर .....

.

श्री अध्यक्ष: प्रश्नोत्तर काल में प्वायंट आफ आर्डर नहीं होता।

Allotment of Plots at Faridabad

***81. Sh. K.N. Gulati, M.L.A.**: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that 55 per cent of plots in Sector 21 of Faridabad were allotted by lottery system; and

(b) if so, the manner in which and the time by which the remaining 45 per cent of the plots are proposed to be allotted to the applicants?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): (a) Yes.

(b) The matter is under consideration of the Government.

श्री के.एन. गुलाटी: स्पीकर साहब, फरीदाबाद में 55 प्रतिशत प्लाटस की अलाटमैंट कर दी गयी है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसके बाद एप्लीकेशन्ज खत्म हो गयी हैं या बाकी हैं?

चौ. बंसी लाल: बहुत बाकी है।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the Honourable Chief Minister if legislators are given some preference in allotment of plots in Faridabad?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, इस बारे में अभी पालिसी तय नहीं कर पाये है, यह अभी तक किया जा रहा है कि किन–किन आदमियों को डिसक्रिशनरी कोटे में से प्लाट दिये

जायें। ये प्लाट उन आदमियों को दिये जायेंगे, जिनको वाकई जरूरत है और जिनके पास किसी दूसरी जगह प्लाट नहीं है।

श्री फूल सिंह कटारिया: क्या इन प्लाटों में हरिजनों के लिये भी कोई कोटा फिक्स किया हुआ है?

चौ. बंसी लाल: जी नहीं, इसमें कोई कोटा फिक्सड नहीं है।

श्री के.एन. गुलाटी: स्पीकर साहब, आजाद भारत के अन्दर सब को बराबर का हक दिया गया है, क्या बाकी के 45 प्रतिशत प्लाट भी सीनियारटी से देने का कष्ट करेंगे? (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि जो बाकी प्लाट अभी पड़े हैं, क्या उनको भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड के बेसिज पर देने की कृपा करेंगे?

चौ. बंसी लाल: जी नहीं। (व्यवधान) .....

कार्य मन्त्रणा समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various Business.

The Committee met in the Chamber of the Speaker on Monday, the 21st August, 1972, at 7.05 P.M.

The Committee, after some discussion, recommended that the business on Tuesday, the 22nd August, 1972, be transacted as follows:-

1. Question Hour.

2. Report of the Business Advisory Committee.

3. Legislative Business.

(1) The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1972.

(2) The Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Bill, 1972.

4. Discussion on the Annual Report and Accounts of the Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March, 1972.

5. Discussion on the Annual Report of the Warehousing Corporation for the years 1967-68 and 1968-69.

6. Official Resolution regarding enhancing of borrowing limit for the Haryana State Electricity Board.

7. Discussion on the Annual Administration Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1970-71.

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move –

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक

हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 3) बिल, 1972

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1972 (हरियाणा विनियोग (सं. 3) विधेयक, 1972)

Sir, I also beg to move –

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill (हरियाणा विनियोग (सं. 3) विधेयक) be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 3) बिल (हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जायें।

चौ. हरद्वारी लाल (बहादुरगढ़): स्पीकर साहब, मेरा इन मदों पर बोलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इस बिल में 12 मदें हैं। इनमें से कोई भी ऐसी मद नहीं है जिस पर हम माकूलियत के साथ कोई नुक्ता–चीनी कर सकें। इसमें कुछ तो स्कीमें, ऐसी हैं, जिनका तमाम खर्चा केन्द्रीय सरकार देती है और हमें उनकी हिदायत के मुताबिक इन स्कीमों पर सारा काम करना पड़ता है। हम इसमें रूपया न घटा सकते हैं और न ही बढ़ा सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि हम इन डिमांडज के ऊपर क्या नुक्ताचीनी करें? गवर्नमैंट ने कुछ रूपया ऐसा रखा है जो उसने प्राइवेट पार्टीज को देना है। यह रूपया उन्होंने अदालतों के हुक्म के तहत देना है। इसके अलावा, एक निहायत जरूरी और अहम सड़क की तामीर होनी है जिससे हरियाणा और यू.पी. व राजस्थान के बीच आमदों–रफ्त में बड़ी आसानी हो जायेगी। वह रूपया भी तमाम का तमाम, केन्द्रीय सरकार से कर्जे की शक्ल में मिलता है। इसलिये इसमें भी एतराज की कोई गुंजाइश नहीं है। इन डिमान्डज में जो सबसे बड़ी रकम है, वह 8 करोड़ के करीब की है। वह एक मल्टीपरपज रिवर–स्कीम के लिये है। उसके लिये प्रोवीजन करना भी निहायत जरूरी है और लाजमी तौर से यह प्रोवीजन करना पड़ेगा। बाकी की छोटी–छोटी रकमें हैं, उनको भी पास करना बहुत जरूरी है। मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं

दिखाई देती जिस पर कोई किसी किस्म का एतराज कर सके। इसी वास्ते, मैं तो चुप रहना चाहता था लेकिन एक दो ऐसी बातें हो गयी जिनकी वजह से मुझे लाजमी तौर पर आपके द्वारा सदन का कुछ समय लेना पड़ा। कुछ आनरेबल मैम्बर्ज, इस वजारत की नरमी का नाजायज फायदा उठा कर ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल बे–मोके हैं, बिल्कुल बे–माहौल हैं, और कम्पलीटली इर–रैलेवेंट हैं। मेरे एक मोहतरिम दोस्त पंडित चिरन्जी लाल को उनमें कुछ ठोस बातें नजर आयीं। चूंकि वह एक पुराने लैजिस्लेटर हैं, इसलिये उनको बड़ी ठोस बातें नजर आयीं। मैं उन ठोस बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और आपका ध्यान दिलवाना इसलिए जरूरी है कि अगर यह चीज शुरू में रोकी नहीं गई तो अभी तो यह कई साल का मामला है ओर आगे चल कर वह खराब होगी। एक साहब उठे हैं इन डिमांडस के ऊपर और फरमाते हैं पटवारी, कानूनगों की जो यह एजेन्सी है यह खत्म कर दी जाए। यह 1965 का जिक्र है बात ऐसी थी कि उनके सिकी भाई–बन्धु ने एक सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया था। पटवारी ईमानदार था। उसने रिपोर्ट कर दी। उसकी इस बात से उनका गुस्सा सारी जमात पर बिखर उठा। पटवारी, गिरदावर, कानूनगों को खत्म करो, यह खत्म करो, वह खत्म करो और यह दिखाने के लिए कि वह कुछ पढे लिखे हैं परमानैन्ट सैटलमेंट का जिक्र किया। यह परमानैन्ट सैटलमैन्ट इनको पता नहीं कौन से साल में हुआ था। इस बारे में फरमाने लगे कि यह 1873 में हुआ था। स्पीकर साहब, 1873 को तो थोड़ा ही अर्सा हुआ है यह 1793

में हुआ था। यह लार्ड कार्निवालिस ने किया था। उस वक्त जैसे हालात थे उन्हें देखकर अंग्रेजों ने हय परमानैन्ट सैटलमैंट कर दिया था। बिहार और बंगाल में उन्होंने यह किया था। फिर उन्होंने सोचा कि यह गल्त है तो उन्होंने यह पालिसी तर्क कर दी। क्या मतलब था इस चीज का इस वक्त कहने का कि किस तरह किया। इन सारी बातों की कहने की कोई रेलिवेन्सी नहीं थी और न डिमान्डज में इस तरह की कोई बात थी। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यह तकरीर को आराम से सुने। स्पीकर साहब, देहात में कट्टा–कट्टी की एक कहावत हे कि जब कट्टी शरारत करती है तो कट्टा कहता है कि जब मैं करूंगा तो फिर ..... (हंसी) स्पीकर साहब, मैं इसकी बात को बड़े आराम से सुनता रहा हूँ अगर यह भी सुनें तो अच्छा रहे।

चौ. चाँद राम: मिसाल तो ठीक दे देते।

चौ. हरद्वारी लाल: स्पीकर साहब, यह किसी और मिसाल से समझते ही नहीं हैं। उस डिमान्ड में कहीं पटवी औ कानूनगो का जिक्र नहीं था और न उस चीज का डिमान्डज से कोई वास्ता था। आज एग्रीकल्चर सैन्सिज सारी दुनियां में हो रही है। कोई यह नहीं कि हमारे मुल्क में ही हो रही है और उसी सिलसिले में हम भी कर रहे हैं। स्पीकर साहब एक तरफ यह कहते हैं कि बेरोजगारी है और दूसरी तरफ कहते है कि पटवारी, कानूनगों को हटा दो तो कया उन हजारों की तादाद में जो

पटवारी और कानूनगों हैं उनको सड़कौं पर बैठा दें। जो लोग यहां सुनने आते हैं उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए यह भाषण देते हैं कि बेरोजगारी बहुत है। सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ करे और दूसरी तरफ पटवारी और कानूनगों को हटाकर सड़कों पर बैठा देने की बात करते हैं। इसके साथ ही स्पीकर साहब, पंडित जी को जो दूसरी ठोस चीज नजर आई वह प्रैस के बारे में थी। हिन्दुस्तान की प्रैस का कसूर क्या है? मैं एक रोज सुन रहा था, वह कह रहे थे कि मेरी तकरीर को आप अच्छी तरह से छापते नहीं हैं। कसूर प्रैस का यह हे कि इनके नाम को, इनकी तकरीर को प्रैस के अन्दर फेयरली डिस्पले नहीं करते। नाम तो जैसा है, वह तो है ही लेकिन तकरीर भी माशैअल्ला है। जिस तकरीर का कोई सिर हो न पैर हो, जो तकरीर माशैअल्ला हो उसे प्रैस वाले क्या छापें। प्रैस वाले तो अच्छी चीज जो होती हैं उसको ही छापते है। कोई गल्त चीज नहीं छापते। ये फिर नैशनल प्रैस पर बिखरे .....

चौ. बंसी लाल: इतनी जिम्मेदारी प्रैस कब से हो गई? (व्यवधान)

चौ. हरद्वारी लाल: जिम्मेदार इस हद तक जरूर है कि डिस्क्रिमिनेट करे कि कौन सी चीज छापी जाए और कौन सी न छापी जाए।

डा. ओम प्रकाश: जो यह चीज कही, नाम तो इनका बड़ा है 'रिजक' बगैर रिजक के कुछ नहीं होता। अगर यह कहा जाए कि नाम बड़े और दर्शन छोटे तो ठीक रहे। (हंसी)

चौ. हरद्वारी लाल: यह जो बात बड़ी है अक्लमंदाना है और मुफीद तरमीम है। स्पीकर साहब, दूसरी बात यह प्रैस की थी जो मैंने बताई। स्पीकर साहब, असल बात तो यह है कि जैसे कहा करते हैं सहमी हुई डूमनी गाय आल पताल। किसी बात का पता नहीं। यह कभी लीडर आफ दी अपोजीशन को ले आते हैं कभी किसी और चीज को लेते हैं जिनका कि इन मदों से कोई ताल्लुक ही नहीं है।

चौ. चाँद राम: स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। हमारे जो रूल्ज आफ स्पीच हैं उनमें यह है कि जो मैम्बर हाउस में मौजूद हो उसके बारे में कोई आनरेबल मैम्बर कुछ कह नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष: अगर कोई बात स्पीच में आई हो तो उसके रैफ्रेंस में बोला जा सकता है।

चौ. चाँद राम: रूल्ज आफ स्पीच में यह चीज इसलिए रखी गई है कि अगर एक मैम्बर कुछ कहता है तो दूसरा प्रोवोक हो जाएगा और फिर वह बोलेगा।

चौ. बंसी लाल: कल कहां गए थे जब वह कह रहे थे तब क्यों नहीं बोले। यह रूल उस वक्त क्यों नहीं बताया?

चौ. चाँद राम: कल मैं नहीं था।

चौ. रिजक राम: इनको बोलने का पूरा मौका देना चाहिए जो तरमीम होगी हम कर देंगे। सरकारी डूमनी कहते तो अच्छा रहता। (व्यवधान)

चौ. हरद्वारी लाल: स्पीकर साहब, सोनीपत पहुंचने से पहले हम इनकी तसल्ली कर देंगे .....

श्री अध्यक्ष: मैम्बर अगर एक दूसरे पर ऐलीगेशन और कांउटर एलीगेशन लगाने से बचें तो अच्छा हो।

चौ. हरद्वारी लाल: यह मैं मानता हूं कि इससे बचना चाहिए यह तो .....

चौ. रिजक राम: इन जैसे आदमी को तनख्वाह ही इस बात की दे रखी है। वे तो बोलेंगे ही (व्यवधान)।

चौ. हरद्वारी लाल: यह बात भी आएगी। स्पीकर साहब, यह ठीक है कि हमें प्रोसीजर के हिसाब से बोलना चाहिए। हमें रेलेवन्ट बोलना चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब, हम इनकी थोड़ी तसल्ली कर देना चाहते हैं। स्पीकर साहब, तीसरी एक ओर ठोस बात कही वह यह कही कि आप पर कुछ गुस्सा था। ये इस बात को भूल गए कि जब तक नो–कांफीडैन्स मोशन न लाया जाए स्पीकर के खिलाफ, उसके कंडक्ट का बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सकते। वह एक बड़ी गम्भीर बात थी। वह नहीं होनी चाहिए थी।

यह गल्त चीज है। इस तरह से एक गल्त प्रथा पड़ जाएगी। इन डिमांडज में कहीं कुछ आपके बाहर जाने के मुताल्लिक एक मद है। ठीक है जाना ही चाहिए। सब जाते हैं। सब ठीक है। यह सब बातें इन्होंने कहीं। स्पीकर साहब, आप तो उस वक्त कुर्सी पर नहीं थे, डिप्टी स्पीकर साहिबा थीं। यह कहते हैं कि वे तो सुन नहीं रहे हैं आप सुन लें। बाहर जरूर जा रहे हैं लेकिन पहली दफा जा रहे हैं अच्छा है और सारी चीज ठीक है लेकिन फिर अपना रोना शुरू कर दिया कि लीडर आफ दी अपोजीशन की रिकग्नीशन के सिलसिले में बड़ा गल्त काम हुआ है। स्पीकर साहब, चुनाव के पहले कुछ बहुत बेमायनी और गलत किस्म की बातें की गई थीं। हमारे कुछ सादा लोग, हरिजन भाई हैं उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करा लिए गए कि जो चीज है, हमने चुनाव के बाद माननी है और ये उन दस्तखतों का आजकल नाजायज फायदा उइा रहे हैं। उसका भी मैं जिक्र करूंगा कि क्या फायदा उठा रहे हैं। दस्तखत करा के चुनाव के बाद फिर यह सिलसिला आया तो उन्होंने कहा कि हम यह चीज नहीं मानेंगे। वह सिलसिला खराब हो गया। स्पीकर साहब आप भी क्या करते, आपने तो किसी नियम के नीचे यह चीज करनी है। ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप एप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोलें तो अच्छा है।

चौ. हरद्वारी लाल: स्पीकर साहब, जिस मद पर ये बोल रहे थे, उसी मद पर मैं बोल रहा हूं।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, इनके तो यही मद हैं।

चौ. हरद्वारी लाल: बात यह है कि सिर्फ वही हरिजन भाई थे वह बाहर नहीं आए। चौ. फूल सिंह जी ने व और दोस्तों ने सोचा कि पोलिटिकल ठगों के टोले से बाहर निकलना चाहिये। पंडित चिरंजी लाल जी अगर नाराज न हों तो मैं आपको बताऊं वह तो हमारे पैदा किये हुए हैं। स्पीकर साहब, उनकी पैदाइश तो वहां की हैं, जहां के चौ. चांद राम जी रहने वाले हैं। सोनीपत, जहां मिर्चे होती हैं, गन्ना भी होता है, वहां एक ओर चीज भी पैदा होती है। सोनीपत में पोलिटिकल ठग भी पैदा होते हैं।

Pandit Chiranji Lal Sharma: Sir, I take exception to these words since I was born, bred up and brought up in Sonepat Tehsil.

श्री हरद्वारी लाल: स्पीकर साहब, तो फिर मेरे से गल्ती हो गई....

चौ. बंसी लाल: पंडित जी तो सोनीपत के हैं नहीं।

चौ. हरद्वारी लाल: स्पीकर साहब, मैंने जो कुछ कहा, उसके लिये मैं पंडित जी से माफी मांगता हूं। मैं तो यह कहूंगा कि अच्छा हुआ बल्कि यह जो यहां से वहां नीचे से ऊपर का सिलसिला था, ठीक हो गया है। हमारी पीठ है जरा और आगे आ

जाएं नहीं तो हमें भी खराब करेंगे। मुझे एक शेयर याद आता है –

जो मैं सरबे सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा,

तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज से।

ये सरकारी आदमी रहे, सालों साल सरकारी टुकड़ों पर पले, अपोजीशन करके कभी देखी नहीं। अपोजीशन को ये क्या मानते हैं। स्पीकर साहब, ये खुद समझ जाए या फिर आप इनको समझाएं और आप उनको किसी तरह दूर बैठाएं। ये हमारा सिलसिला भी खराब कर रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ऐप्रोप्रिएशन बिल पर किसी नुक्ताचीनी की जरूरत नहीं है। इस पर इतनी बहस की जरूरत नहीं होनी चाहिये और इसे पास किया जाना चाहिये। इस तरह टाइम की सेविग करके इस सदन को कोई और काम करना चाहिये। इसके इलावा और भी बड़ी बातें डिस्कशन के लिये हमारे पास होंगी, जिस पर कोने वाले साहिबान बोल सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। बस मैं और कुछ न बोलता हुआ इन शब्दों के साथ अपना भाषण खत्म करता हूं और आपसे इस बात की माफी चाहता हूं कि बहुत सी इर–रैलेवेन्ट बातें यहां कही गई हैं लेकिन मैंने तो सिर्फ इनकी इर–रैलेवेन्ट बातों का ही जवाब दिया है।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। .....

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, अब आप क्या कहना चाहते हैं?

चौ. प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि यह हाउस इन दो आदमियों के लिये ही रह गया है। You have reduced this House to nothing.

श्री गुबाल सिंह जैन (हिसार): स्पीकर साहब, कल से इस सदन में सप्लीमैंन्ट्री ऐस्टीमेंटस पर दोनों ओर के सदस्यगण बोल रहे हैं। हमारे विरोधी पक्ष के भाईयों ने सरकार के ऊपर कुछ नुक्ताचीनियां की हैं। जैसा कि लीडर आफ दी अपोजीशन ने बताया कि इस इप्लीमैन्ट्री ऐस्टीमेटस में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें कि चुक्ताचीनी की कोई गुंजाइश रह गई हो। लेकिन इन दोस्तों ने तो यह फैसला कर रखा है कि चाहे सरकार तरक्की की ओर बढ़े चाहे जितना भी उत्पति का कार्य क्यों न करें, उन्होंने तो सरकार के कामों की सराहना करनी ही नहीं है। सरकार के खिलाफ ही कहते जाना है और इसी तरह से वे अपनी बे–बुनियाद बातें करते रहेंगे। अभी यहां पर चर्चा चली। मैं चौ. रिजक राम जी की दिल से इज्जत करता हूं। मैं तो उनके बारे में यह समझता था कि वह तो बड़े सुलझे हुए पार्लियामैन्टेरियन हैं और मेरा उनके बारे में यह ख्याल था कि उनके इस हाउस में आने से, इस हाउस की डिस्कशन में सुधार होगा। इस हाउस का स्तर ऊंचा होगा।

लेकिन कल जो मैंने उनकी बातें सुनी तो इस बारे में इतना ही कहूंगा कि ऐसा मालूम होता है कि उन पर चौ. हरिद्वारी लाल जी का फोबिया छाया हुआ है। मुझे खुशी हुई है कि चौ. हरिद्वारी लाल जी ने उनको जवाब देने की कोशिश की है लेकिन मैं लीडर आफ दी अपोजीशन से यह कहूंगा कि गन्द को गन्द से नहीं उछाला करते। स्पीकर साहब, आज मैं यही कहूंगा कि जो कुछ इस हाउस में कहा जाए, उसका स्तर ऊंचा होना चाहिये। आखिरकार जो कुछ हम यहां पर बोलते हैं, कहते हैं, वह प्रैस में जाता है। ऊपर गैलरी में प्रैस वाले बैठे हैं, वे लोग भी बाहर जाकर हमारा मजाक उड़ायेंगे कि वहां हाउस में इस स्तर तक की बातें होती हैं। स्पीकर साहब, आपको पता ही है कि हाउस का टाईम कीमती टाईम होता है, हमारा मुद्दा तो केवल यह होना चाहिये कि हम सरकार को कोई ठोस सुझाव दें न कि सरकार के हर अच्छे कार्य की आलोचना करें। इसके साथ–साथ मैं तो अपोजीशन के भाईयों से कहूंगा कि वे अपना कीमती समय सरार को अच्छे सुझाव देने में लगाएं ताकि कुछ हमारे प्रदेश का भला हो सके न कि सरकार की नुक्ताचीनी में फजूल में समय बरबाद करें। हमारे कुछ दोस्तों ने यहां पर बेकारी के बारे में भी डिस्कशन की और कुछेक ने कुरप्शन के बारे में भी बातैं कहीं। इन सब बातों का मुख्यमंत्री जी कल जवाब दे चुके हैं। मैं तो सदन का ध्यान कुछ ऐसी बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं जैसे कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैन्ट ने अपनी रिपोर्ट के पहले पन्ने में हरियाणा की तरक्की के कुछ आंकड़े दिये हैं। अपोजीशन के भाई

अगर रिपोर्ट को पढ़ने की तकलीफ गवारा करें तो उनको पता चल जायेगा कि हरियाणा सरकार ने कितनी तरक्की की है और बेकारी को कैसे ओर किस हद तक खत्म किया जा रहा है। 1970–71 में हरियाणा प्रदेश की पर–कैपिटा इन्कम का हिसाब आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। उनको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। जैसे पिछली दफा चौ. रिजक राम जी ने कहा था कि ये जो आंकड़े सरकार ने दिये हैं, वे गल्त दिये हैं, यह कह देना तो आसान बात है लेकिन जब तक किसी ठोस सबूल के साथ यह साबित न किया जाए कि यह कैसे गल्त हैं तब तक इस प्रकार झूठ कहना ठीक नहीं है। जब हम तरक्की की बात करते हैं तो हमें आंकड़ों को ही मानकर चलना पड़ता है। आंकड़ों से ही सब कुछ पता लग जाता है कि हरियाणा प्रान्त किस स्तर तक आगे बढ़ रहा है। उन आंकड़ों के बारे में मैं यही कहूंगा कि हमारे अकेले हरियाणा प्रदेश की तरक्की के आंकड़े 3.3 परसैन्ट हैं जबकि सारे हिन्दोस्तान की तरक्की 1 परसैन्ट है। पंजाब, जोकि आज तक हरियाणा की तरक्की की स्कीमों का सारा हिस्सा खाता रहा है, उसकी तरक्की की रफतार 2.7 परसैन्ट है। हरियाणा प्रानत जिसकी हम आज इकानोमी को डिवैल्प कर रहे हैं यह कल तक बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश था। मैं सन् 1947 का वक्त याद करता हूं जब मैं कालेज में पढ़ा करता था तो उस वक्त तमाम हरियाणा के इलाका में एक भी डिग्री कालेज नहीं था। सिर्फ एक इंटरमिडिएट कालेज अम्बाला में था और दूसरा इन्टरमिडिएट कालेज रोहतक में था। यह तो हालत थी एजूकेशन की उस वक्त। आजादी मिलने के बाद भी जब

हरियाणा पंजाब का हिस्सा था तो उस वक्त इंडस्ट्री को भी पंजाब के इलाकों में फिरोग दिया गया और जितने कोटे थे वे सब पंजाब को ही जाते थे और हमारा हरियाणा का जो इलाका था इसके साथ सौतेली मां का सलूक होता था। जिस वक्त हमारा हरियाणा प्रान्त बना तो उस वक्त जो यहां की हालत थी वह सबको मालूम है और अब इतने थोड़े से अरसे में जो यहां पर तरक्की हुई उसकी वजह से हम सब सर ऊंचा करके चलते हैं। सब जगह पर इस बात की चर्चा होती है कि हरियाणा ने बहुत तरक्की की है। मैं समझता हूं कि हरियाणा की तारीफ को सुन कर मेरे उन दोस्तों को भी फख्र होता होगा क्योंकि हरियाणा में जो डिवैल्पमैंट हुई है उसके क्रैडिट का यहां का हरेक हरियाणवी हकदार है।

जहां तक बेकारी की बात कही गई है मैं इस चीज को मानता हूं कि आज यह केवल हरियाणा के लिए ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के लिए एक गम्भीर मसला बना हुआ है ओर सरकार का इसकी तरफ ध्यान है। मैं अपने अपोजीशन के भाईयों को बताना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी का बेकारी को हटाने का केवल नारा ही नहीं है। आप को याद होगा हमारी प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी जी ने, जिस वक्त बंगला देश का मसला चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम जो कहते हैं वह करते हैं और उन्होंने जो कुछ उस वक्त कहा था वह करके दिखा दिया। इसलिए जो यह हम ने फैसला किया है गरीबी हआने का, आप

देखेंगे कि गरीबी भी हटेगी और बेकारी भी हटेगी। सन् 1947 से पहले के वक्त को आप याद करें उस वक्त जब कांग्रेस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी तो लोग यह कहते थे कि यह नुकीली टोपी वाले, यह खर्चा चलाने वाले अंग्रेजों को कैसे निकाल सकेंगे लेकिन हम उस वक्त मजबूती के साथ कहा करते थे कि अंग्रेज जाएगा ओर हम आजाद होंगे और आप जानते हैं कि अंग्रेज को यहां से जाना पड़ा और हमने देश को आजाद करवाया। (विघ्न) हमने जो प्रोग्राम रखा था वह पूरा हुआ।

चौ. चांद राम: आज के कांग्रेसी क्या उस तरह कुर्बानी करने वाले हैं।

श्री गुलाल सिंह जैन: चौधरी साहब, यह आदमियों की बात नहीं होती, मेन बात पार्टी के प्रोग्राम की होती है। मैं वर्मा साहब से और अपने दूसरे दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूं कि आज हम ने जो प्रोग्राम रखा है कि बेकारी और गरीबी हटाएंगे जैसे 1947 से पहले लोग यह बिलीव नहीं करते थे कि आजादी आएगी लेकिन हमाने आजादी लेकर दिखाई उसी तरीके से यह जो गरीबी हटाने का मसला है जिसके बारे में यह सोचा जाता है कि कैसे दूर होगा मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वह जरूर दूर होगी। आप देखेंगे कि गरीबी और बेकारी यहां से दूर होंगी।

श्री के.एन. गुलाटी: शराब बंदी भी की जाएगी, इसके बारे में भी बताएं।

श्री गुलाब सिंह जैन: वह भी बन्द होगी। आज जो हमारे सामने ऐस्टीमेटस हैं, जैसा कि लीडर आफ दी अपोजीशन ने फरमाया था, उसमें मेन मद जो है वह इरीगेशन की है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रान्त है जिस में हमारी सारी इकानोमी एग्रीकल्चर पर बेसड है। हमारे यहां बहुत सारी तादाद में न ही कारखाने हैं और न ही इंडस्ट्री के लिए रा–मैटिरियल है। इस लिए अगर हमने इन्डस्ट्री को फिरोग देना है तो उसे हमें एग्रीकल्चर बेसड करना पड़ेगा। इन सब चीजों को करने के एिल पानी की बहुत जरूरत है। मगर सैंटर से हमें जो इमदाद मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। इसलिए मैं चाहता हूं कि सैंटर से मदद लेने के एिल सब मैंबर साहिबान सरकार के हाथ मजबूत करें ताकि हरियाणा सरकार सैंटर को मजबूर करे कि वे चाहे जिस तरह हो सके ''बैग, बारो और स्टील'' वे हमें मदद दें ताकि जो हमारी मल्टीपरपज रिवर स्कीमज हैं उनको हम पूरा कर सकें। इस वक्त हरियाणा का आधा हिस्सा महेन्द्रगढ, गुडगांवा और हिसार का काफी भाग ड्राट अफैक्टिड एरिया है। हमें वह जमाना यहा है कि जबकि हरियाणा का दूसरा नाम 'कहत' लिया जाता था। मगर आज हमें फख्र है कि हरियणा ने काफी तरक्की की है और हम अनाज पैदा करके बहार भेजते हैं। यह सब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की समझ और हिम्मत का नतीजा है। स्पीकर साहब जिस वक्त जूई कैनाल बनाने की बात चल रही थी तो कई साहिबान की तरफ से मजाक किया जाता था कि यह कैसे होगा लेकिन जिस वक्त हमारे डिफैंस

मिनिस्टर श्री जगजीवन राम उस नहर का उदघाटन करने आए तो मैंने उन दोस्तों को बताया कि जिस चीज को वे कह रहे थे मुमकिन नहीं है वह बात मुमकिन हो रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि लिफ्ट स्कीम जो है वह बहुत एक्सपैंसिव है लेकिन जब हम ने लोगों की भलाई करनी है, जनता को ऊंचा उठाना है और गरीबी को दूर करना है तो हमें एक्सपैंडीचर की तरफ नहीं देखना चाहिए क्योंकि पानी के बगैर उस इलाके का भला नहीं हो सकता। पानी हमारे लिए आज बहुत अहम चीज है। इसलिए यह सरकार का फर्ज अव्वलीन बन जाता है कि वह पानी का प्रबन्ध करे और स्पीकर साहब मैं अपनी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वह आज हरियाणा के चप्पे–चप्पे को इरीगेट करने के लिए सोच रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई जो आपोजीशन में हैं वे नुक्ताचीनी करने की बजाए सब मिल कर अच्छे कामों मे ंसरकार की मदद करें क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर सहाब यहां पर कह चुके हैं कि हर वह सुझाव जो अच्छा होगा, जो सुझाव जनता और प्रदेश के भले के लिए दिया जाएगा उसको सरकार मानेगी। इसलिए आज अगर अपोजीशन के किसी मैबर से ऐसा सुझाव आया हो कि फलां काम करने से जनता का भला होगा और उसे माना न गया हेा वे बतला दें लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस किस्म का कोई सुझाव अपोजीशन की तरफ से नहीं आया, जो कुछ कहा गया है वह सब नुक्ताचीनी के लिए ही कहा गया है। स्पीकर सहाब, आपको तो मालूम ही है कि इरीगेशन और एग्रीकल्चर का आपस में बहुत ताल्लुक है। हरियाणा

बनने के बाद एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हरियाणा ने बहुत तरक्की की है। हमारे एग्रीकल्चार प्रोडक्शन में 75 परसैंट इन्क्रीज हुआ है ओर 1966–67 के मुकाबले में हमारी एवरेज फूड प्रोडक्शन 55 फीसदी ऊपर गई है। यह सब चीजें कैसे हुई? यह सब चीजें इसलिए हुई कि सरकार का इस तरफ ध्यान था, किसान का इस तरफ ध्यान था कि किसानों को कैसे पानी दें। हम, जैसा कि आप जानते हैं ब्यास इर्रीगेशन स्कीम के जरिए किसानों को कैसे पानी देरे की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारी मल्टीपरपज स्कीम है, हमें रावी और ब्यास का पानी मिलता है। मगर जब तक हम अपनी चैनलज और जो प्रौजक्टस हैं वे सब तैयार नहीं करेंगे तब तक हम उस रावी और ब्यास के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि सरकार को जो इस वक्त स्टैप्स ले रही है, जगह–जगह नहरें खोदने की प्रोपोजल है उन सबको पायाए तकमील पहुंचाया जाए। आज जैसा कि सुना गया है कि सरकार को कुछ माली संकट पेश आ रहा है क्योंकि सैंटर ने ओवरड्राफटिंग पर पाबंदी लगा दी है। इसको दूर करने के लिए हमें जल्दी कोशिश करनी चाहिए।

मैं स्पीकर साहब, आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं और सारे मैंबर साहिबान से अर्ज करना चाहता हूं कि हमें चाहिये कि हम सब एक जबान होकर इस सरकार के और चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ मजबूत करें ताकि हमारी जो इरीगेशन की स्कीमें और प्रदेश के किसानों को पानी देने की स्कीमें हैं उनके

लिये वे सैंटर को कम्पैल कर सकें कि इनके लिये हमैं स्पैशल ग्रांटस दे। हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश था और हमारी इकानोमी अब भी इतनी मजबूत नहीं की हम अपने तौर पर इन सारे प्राजैक्टस का खर्च बरदाश्त कर सकें। अगर किसी वजह से देहली की सरकार हमें रूपया नहीं देती तो मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि हम सबको अपनी सरकार के हाथ मजबूत करके किसी तरीके से अपनी ही स्टेट में जराये पैदा करने चाहियें लेकिन यह काम सिरे चढ़ने चाहियें। स्पीकर साहब, आपको मालूम है इस लड़ाई के बाद अमरीका ने हमें आंखें दिखाई औरह में एड देने से इन्कार किया लेकिन हमारी प्रधानमंत्री साहिबा इस बात से घबराई नहीं ओर उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम अपने जराये से देश को आगे ले जायेगे। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी वजह से देहली की सरकार हमें पैसा नहीं देती है, अव्वल तो हमारा फर्ज बनाता है कि हम उनको बतायें, इम्प्रैस केरं कि हमारी रिक्वायरमैंटस जायज हैं ओर हमें जनरल तरीके से न देखा जाये क्योंकि हमारे स्पैशल हालात हैं इसलिये हमें स्पैशल ट्रीटमैंट दिया जाये लेकिन अगर वे नहीं मानते तो हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिये। वैसे हमें उनको इम्प्रैस करना चाहिये कि हरियाणा एक लैबोरेटरी की तरह, जिस तरह कोई इनवैस्टीगेशन करते वक्त लैबोरेटरी में काम होता है, एक्सपैरीमैंट होता है और जब वह कामयाब हो जाता है तो फिर कमर्शियल तौर पर एक्सप्लायट किया जाता है, उसी तरह हमारी स्टेट एक लैबोरेटरी की तरह काम करके, इन पायलट प्रोजैक्टस को चला कर एक्सपैरीमैंट कर

रही है ओर अगर यह हमारा एकसपैरोमैंट कामयाब हो गया तो फिर यह सारे देश के लिये एक बैकन लाइट की तरह काम देगा और सारे देश को इसका फायदा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो हम कर रहे हैं इससे ने केवल हरियाणा को फायदा होने वाला है बल्कि सारे देश को ही फायदा होगा और इसी दृष्टि से भारत सरकार को देखना चाहिये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह लैबोरैटरी में किसी चीज की इनवैरटीगेशन के लिये एक्सपैरीमैंट होता है तो उस वक्त उसकी कास्ट कांउट नहीं की जाती है कि इस पर कितना खर्च आ रहा है बल्कि यह देखा जाताहै कि इसकी कामयाबी से फायदा कितना होने वाला है। तो यह बात हमें गवर्नमैंट से कहनी चाहिये कि यह जो प्रोजैक्टस जो हमने सोचे हैं और हमने चलाये हैं उनके कामयाब हो जाने से सारे देश का ही फायदा होने वाला है।

कल हमारे कुछ दोस्तों ने अफसरों पर नुक्ताचीनी की और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके बारे में ठीक ही कहा कि – we are proud of our officers. Day and night, they are working for the betterment and uplift of the State. यह जो यहां इतनी काबिल लीडरशिप चीफ मिनिस्टर साहब की है उसकी वजह से उनको काम करने की इन्सपिरेशन मिल रही है और इस काबिल लीडरशिप के अंडर काम करते हुये हमारे इंजीनियर्ज ने इरीगेशन के बारे में जो प्रोजैक्टस दिये हैं वे जब देहली में डिस्कस किये गये तो उनको इम्पासीबल कहा गया। चीफ मिनिस्टर सहाब ने ही

हमें यह किस्सा सुनाया था कि जब देहली में मीटिंग में प्रोजैक्ट को रखा गया तो कहा गया कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है लेकिन जब वे प्रोजेक्ट कामयाब हुआ ओर उन्हें लाकर दिखाया गया तो कहा गया कि आप ने तो करिश्मा करके दिखा दिया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि और में सिकी का नाम नहीं लेना चाहता हू कि हमारे जो इन्जीनियर्ज हैं, पानी के बारे में और इन प्रौजैक्अस के बारे में बहुत लगन के साथ सोचते है कि किसी तरह से हरियाणा के लोगों को फायदा हो सकता है बावजूद इसके कि वे हरियाणवी नहीं हैं और कई दफा यहां यह कहा भी जाता है कि कि हरियाणा में हरियाणा के अफसर होने चाहियें लेकिन इसके बावजूद कि बहुत सारे सीनियर अफसर हरियाणा के नहीं हैं उसके दिल में हरियाणा की तरक्की की बात समाई हुई है। They are wedded with the upliftemnt of Haryana. I am saying this with my experience. उनको जब लीडरशिप काबिल मिली है तो फिर काम नहीं होगा तो ओर क्या होगा। मैं अर्ज करता हूं कि हमारे प्रौजेक्ट जो हैं वे थोड़े खर्च के हैं ओर छोटै हैं कही 20 मील और कहीं 40 मील नहर बनती है और कही 10 करोड़ का और कहीं 20 करोउ़ रूपये का खर्च है कोई बहुत बड़ा खर्च वाला प्रौजैक्ट नहीं है। यह देश बहुत बड़ा देश है ओर यह एक द्वीप की तरह से है। इसमें जो एक्सपैरीमैंट हमने किया है और जो करिश्मा हमने किया है उसका फायदा हरियाणा को तो होगा ही साथ ही सारे देश को भी फायदा होगा क्योंकि जिस चीज को इम्पौसीबल कहा जाता था हमने वह करके दिखा दी है

और अब इसका फायदा बाकी भी उठा सकते हैं। हमें गवर्नमैंट आफ इंडिया को यह कहना है कि यह न देखों कि हम क्या खर्च कर रहे हैं बल्कि यह देखों कि कहां खर्च कर रहे हैं। मुमकिन है हमारी कास्ट उनके ख्याल के मुताबिक उनको ज्यादा नजर आती हो और वे समझते हों कि यह बात नहीं होनी चाहिये। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पायोनियर होता है जब शुरू में कोई वह कदम उठाता है तो उसकी नुक्ताचीनी होती है और उसका मजाक भी किया जा सकता है जैसा कि आप जानते हैं कि जिस अंग्रेज ने हिन्दुस्तान को तलाश करने का कदम उठाया था तो लोगों ने उसे बेवकूफ कहा था कि कैसे वह किश्ती में जाकर तलाश करेगा। जो पायोनियर्ज होते हैं उनको जनता बेवकूफ भी कह देती है क्योंकि लोग उस बात को समझ नहीं सकते और जो बात किसी की समझ से बाहर हो और दूसरा उसे कह रहा हो तो वह उसे बेवकूफ समझता है। हरियाणा में इस वक्त पायोनियर वर्क हो रहा है। इसलिये देहली सरकार की तरफ से हरियाणा के लिये स्पैशल सैंक्शन फायनैस की होनी चाहिये क्योंकि हरियाणा जो नमूना पेश कर रहा है उससे तमाम देश को फायदा हो सकता है। स्पीकर साहब, कई बार अपोजीशन के भाई एक और एतराज करते हैं और कहते हैं कि फलां चीज हो तो अच्छी रही है लेकिन उस पर खर्च बहुत हो रहा है और उसमें कुछ पैसा जाया जा रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ तो दूसरे देशों से हम सौ साल पीछे थे और हरियाणा हिन्दुतान से पचास साल पीछे था। तो आगे बढ़ने के लिये तरक्की के काम करने

जरूरी है और अगर हम चाहते हैं कि हम तेजी से आगे बढ़ें तो लाजमी है कि हमारी सरकार तेजी से काम करें। अगर स्पीड से काम नहीं होगा तो जैसे कहा जाता है कि Justice delayed is justice denied तो उसी तरह यह कहा जा सकता है कि Development delayed is no development. आज जनता इन्तजार नहीं कर सकती। जनता जल्दी काम चाहती है ओर जैसा कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री साहिबा ने भी फरमाया है कि अगर हमने बेकारी का मसाल जल्दी से हल नहीं यिका तो जनता हमारा इन्तजार नहीं करेगी और हमें इस डिले के लिये माफ नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर हमने जल्दी से तरक्की के काम नहीं किये तो हरियाणा की जनता हमें माफ नहीं करेगी। यह ठीक है औ मुमकिन है कि तेजी से चलने में गल्ती भी हो जाती है लेकिन गलतियों को सुधार हो सकता है। एक चीज अगर बन जाये और उसमें अगर कोई कमी रह जाये तो वह दूर की जा सकती है लेकिन अगर कोई चीज बन ही न तो सुधार किस बात में किया जा सकता है। मैं अर्ज करता हूं कि आपको पता है कि पिछली बड़ी लड़ाई के बाद जर्मनी बिल्कुल नेस्तोनाबूद हो गया था, जापान तबाह हो गया था लेकिन उन्होंने थोड़े समय मैं ही अपने देशें को अपने पांव पर खड़ कर दिया। इसकी वजह यह है कि वहां के रहने वालों के दिल में एक ही बात थी कि तरक्की करनी है। वहां यहां की तरह नहीं होता कि सदन में 19 ओर 12 का ही चर्चा रहता है हम सबके सामने एक ही बात होनी चाहिये कि किस तरह तेजी के साथ चल कर हम अपने हरियाणा को ऊंचा उठा

सकते हैं। जहां तक अपोजीशन का ताल्लुक है तो जब हम तेजी से चलते हुये कहीं गल्ती कर दें तो जैसे घोड़े की लगाम खींच कर गल्त रास्ते पर जाने से रोकते हैं उसी तरह से अपोजीशन भी सरकार की लगाम है जिसे वह गल्ती करते वक्त खींच सकती है और रोक सकती है लेकिन यह तरक्की का घोड़ा आगे चलता ही रहना चाहिये और तेजी के साथ चलना चाहिये। एक बात की तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। हरियाणा देहली के नजदीक है। योरूप में दुनिया के अतीरतरीन देश स्कैंडेनेवियन कंट्रीज नारवे, हालैंड और डेनमार्क हैं। वे बड़े इन्डस्टरियलाइजड देश अनाज और सब्जियां फल आदि चीजें सप्लाई करते हैं और सी वजह से वे अमीर हैं। इसी तरह से देहली के तीन तरफ हरियाणा फैला हुआ है। स्पीकर साहब अगर हम यहां पानी का पूरा इन्तजाम कर देते हैं तो हमारे किसान जो बहुत मेहनती हैं इसी तरह सारे देहली को एग्रीकल्चरल प्रौडक्टस, मिल्क और मिल्क प्रौडक्टस, सब्जियां, फल आदि सारी चीजें सप्लाई करके फायदा उठा सकते हैं। हमारे जो भाई पश्चिमी पंजाब से आकर बसे हैं उनको एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा ज्ञान है। आज वे हरियाणा के उतने ही अच्दे बाशिंदे हैं जितने कि 1947 से पहले के रहने वाले लोग वहां पर हैं। वे हरियाणा को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हम देखते हैं। आजकल सीलिंग का चर्चा चल रहा है। इस पर जब बिल आयेगा तो मैं बात करूंगा लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि हर आदमी जानता है कि लैंड पर सींलिग आयेगी और इस तरह से होल्डिंग्ज कम होगी। इसके बाद

जब अगली जनरेशन आयेगी तो और होल्डिंग्ज छोटी हो जायेगी। इस हालात में सरकार को इसी नजरियें के साथ सोचना चाहिये और स्माल होल्डिंग्ज के बेसिज पर हमें अपनी इकानोमी को ढालना चाहिये और इसके लिये जरूरी है कि इनटैंसिव कल्टीवेशन हो। अगर हम इनटैंसिव कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जायेंगे और हमारा प्रदेश खुशहाल नहीं होगा। इसके लिए पानी की जरूरत है। तो हम किसी भी पहलू से देंखे पानी हमारी जरूरत है। मैं जरायत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि मरेी जमीन नहीं है और मैंन कभी एग्रीकल्चर का काम किया नहीं है लेकिन मेरे हल्का के जमींदार भाई मुझे मिलते हैं और मेरे साथ बातें करते हैं और वे मुझे बताते हैं कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी तब तक नहीं हो सकता जब तक पूरा पानी न हो और सफीशैंट क्वांटिटी में आबपाशी के साधन न हों। अगर फसल को थोड़ा पानी लगे और ऊपर से फर्टिलाईजर डाल दी जाए तो फसल को नुक्सान हो जाता है। इसलिए पानी हरियाणा के किसानों की रीढ़ की हड्डी है। इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए और किसानों को पानी मुहैया करने के लिए सरकार मुनासिब कदम उठाए। जो ऐप्रोप्रिएशन बिल सदन के सामने प्रस्तुत है इसको मेरा पूरा–पूरा समर्थन है और मैं समझता हूं कि तमाम हाउस का इसको समर्थन है। आज हमारी इकानोमी स्माल होल्डिंग पर है, इसको तरजीह देने के लिए हमें इन–अडवांस सोचना चाहिए। अगर वक्त से पहले नहीं सोचेंगे और इसी तरह वक्त निकलने के बाद साचैंगे तेा हम पीछे रह जायेंगे। हमारी

जितनी भी पानी की स्कीमें हैं उन सब को तेजी के साथ पूरा करना है। जो काम सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं, जितनी मल्टीपर्पज स्कीमज हैं जिन का चीफ मिनिस्टर साहब ने अने भाषण में जिक्र किया है उन सबको पूर जोर के साथ, पूरी स्पीड के साथ चलाएं। जितनी स्पीड के साथ आज काम चल रहा है, मैं समझता हूं वह भी कम है। पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहब कहा करते थे कि जो स्कीमें शुरू कर रखी हैं उनको इन चार सालों में पूरा कर देंगे। लेकिन अब पांच साल और मिल गए हैं। हम यह पांच साल का अर्सा पूरा नहीं करना चाहते बल्कि यह काम पहले करना चाहते हैं। हमने पानी वगैरह का तरक्की की स्कीमों को दो सालों में पूरा करना है। इन कामों को करने के लिए अवश्य दिल्ली की सरकार को हमें पर्याप्त धन देना चाहिए और हमें इसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे धन इकट्ठा करने के लिए हमें टैक्स क्यों न लगाना पड़े, हम लगाएंगे। कुछ भी करना पड़े, हमें जल्दी से जल्दी इन स्कीमों की पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हाउस में सेल्ज टैक्स पर चर्चा चल रही थी। मैं इस पर कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। अगर इस महकमें की प्रोपर स्ट्रीम लाइनिंग कर दें तो अकेले इसी महकमें से 10 करोड़ रूपया ज्यादा वसूल हो सकता है। हमें धन पैदा करना चाहिए, इसके लिए हमें कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े, अपनायेंगे और शुरू की हुई स्कीमों को कामयाब करेंगे। बहरहाल प्रदेश में जो तरक्की की स्कीमें हैं, खासतौर पर इरीगेशन की जितनी स्कीमें हें, उनको पूरा करने के लिए सबसे पहले रूपया मिलना चाहिए।

यह जायज डिमांड है इस पर नुक्ताचीनी करने की कोई बात नहीं।

जहां मैं एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं वहां आखिर में आपकी मारफत नम्र निवेदन करूंगा कि अपोजिशन के भाई बिना वजह क्रिटिसीजम न करें। कोई ठोस सुझाव दें ताकि हमारे प्रदेश का भला हो और प्रदेश की तरक्की के साथ–साथ उनका भी भला हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

चौ. चाँद राम (बबैन): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे सामने जो एप्रोप्रिएशन बिल जेरे गौर है, इस पर विचार रखने की ज्यादा गुजाईश नहीं है। लेनिक कुछ बातों की तरफ में जरूरी सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सप्लीमैंटरी डिमांडज के सफा 2 पर 'पार्ट टाईम स्वीपर' की एक आईटम आती है। मैं समझता हूं, जिस वातावरण में आज हम काम कर रहे है और जो हमारा निशाना है उसको मदेनजर रखते हुए इन शब्दों की डिमांडज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। 'पार्ट टाईम स्वीपर' की आईटम यह जाहिर करती है कि हमारा मनोविज्ञान, हमारा दृष्टिकोण कितना संकुचित है। कितनी छोटी सी बात है, अगर इस बात को लेकर हमारे बड़े आदमी दबे हुए इन्सानों को, अछूतों को, नीचे के लैवल के आदमियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे तो ठीक नहीं है। बड़े आदमी वे हैं जो देने के लायक हैं, जो देने के काबिल हैं वही देते हैं और अछूतों पर खर्च करते हैं। अब आप देखें, स्पीपर की बात एक छोटी सी चीज है। आप जरा सोचे,

स्वीपर को महत स्वीपर क्यों लगाते हैं, चपडासी का नाम क्यों नहीं दे सकते। स्वीपर तो ऐसा है जो चपड़ासी का काम भी देगा और स्वीपर का काम भी देगा। लेकिन उसको चपड़ासी नहीं लगाया जाता। मैं ऐसी मिसालें बताऊंगा जहां स्वीपरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। किसी दफतर में एक चपडासी था। इत्तफाक से एक ऐसा अफसर आ गया जिस के घर में वह चपड़ासी रोटी नहीं पका सकता था। उस अफसर ने उसकी बदली कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उस स्वीपर को पार्ट टाईम रखा है तो बाकी टाईम में वह कौन सा काम करेगा? हमारे देश की सरकार आज फुल एम्पलायमैंट की बात करती है, हाफ की नहीं। लेकिन हमारे दिमाग ऐसी छोटी–छोटी बातों में फंसे हैं जिससे देश में ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और अफसरशाही फैलती है। एक आदमी कहता है कि मैं दो रोटी खाऊंगा लेकिन दूसरे के लिए वह कहता हे कि वह आधी रोटी भी न खाये। ऐसा नहीं होना चाहिए, परमात्मा सबका भला चाहता है और करता है। लेकिन इन्सान क्यों नहीं दूसरे का भला चाहता। अपने लिए पूरा रोजगार लेते हैं और दूसरों के लिए कहते हैं कि पार्ट टाईम काम करेगा। पार्ट टाईम में 20 या 25 रूपये मिलते होंगे, यह चीज ठीक नहीं। मैं यह नहीं कहता कि 'पार्ट टाईम स्वीपर' वाली बात कोई नई बात है, बेशक पुरानी है लेकिन यह बन्द होनी चाहिए। आगे के लिए बिल्कुल जारी नहीं रहना चाहिए कि हम 'पार्ट टाईम स्वीपर' रखना चाहते हैं। अगर रखना है तो उसको फुल एम्पलायमैंट दीजिए। दूसरी कैटेगरीज में पार्ट–टाईम की कोई बात

नही है। आप रैस्ट हाउसिज में देखेंगे पार्ट टाईम स्वीपर हैं लेकिन पार्ट टाईम चौकीदार नहीं होगा, कोई छोटा मोटा काम करने वाला आदमी भी पार्ट टाईम पर काम नहीं करता होगा लेकिन स्वीपर को पार्ट टाईम रखते हैं। मैं समझता हूं सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए। महात्मा गांधी के असूलों पर चलने वाली यह सरकार है। ठीक है, यह चीज हमारे वक्त में भी जारी रही होगी लेकिन यह कोई जवाब नहीं कि हमारे वक्त में जारी रही इसलिए अब भी जारी रहेगी। अछूत आज से 20 साल पहले भी थे और आज भी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि 20 साल पहले अछूत थे इसलिए आज भी जारी रहने चाहिए। मेरे कई भाईयों ने कहा कि हमें एक जबान होकर गवर्नमैंट आफ इंडिया से यह डिमांड करनी चाहिए कि हमारे अविकसित सूबे को पनपने के लिए पर्यापत ग्रांट दे। इस हाउस का कोई भी सदस्य ऐसा नही जो गवर्नमैंट आफ इंडिया से यह मांग नहीं करेगा। चौ. भजन लाल ने डिमांड की कि हरियाणा को रिलीफ देने के लिए 50 करोड़ रूपया लेना चाहिए। मेरग इस प्रदेश में जो तरक्की हुई है वह कुदरती तौर पर होनी चाहिए थी, इसलिए तो यह सूबा बना था। हमारी पोटैशिएलिटी थी तरक्की करने की तभी तो हुई है। और ज्यादा तरक्की करने के लिए जो रूपया ग्रांट के तौर पर मिलता उसके लिए आज जरूरत इस बात की है कि जो रूपया गवर्नमैंट आफ इंडिया से हासिल किया जाए उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से किया जाए। ठीक है तरक्की के कामों में गति लाना अच्छी चीज है, तेजी से, रफ्तार से काम करें लेकिन इसके साथ–साथ

यह भी कहावत है – ''हेस्ट मेक्स वेस्ट'। यानी जल्दी से खराबियां होती हैं। जो आदमी तजुर्बेकार होगा वह इस बात को पहले देखेगा कि अगर फलां काम करने में जल्दी करूंगा तो उसमें खराबी तो नहीं हो जाएगी? लेकिन सरकार ने जो काम किए हैं उनमें बहुत खराबियां हुई हैं। आज जो मल्टीपर्पज प्रौजक्टस चल रहे हैं उनमें बहुत सी खराबियां रह चुकी है। आप देखें, हमने आगमैंटेशन कैनाल खोदी है। इससे जुई और दूसरी कैनाल्ज निकलेगी। अगर इन कैनाल्ज को जमुना के किनारे–किनारे खोदते तो काबलेकाश्त एरिया सैराब होता और इसके साथ ही साथ हमारी बाउंडरी बन जाती। यमुनानगर, राडौर और इंदरी के एरिए से नहर गुजरती है। तीन–चार मील लम्बी बीच में खोद दी है। इनके बचने से सारा एरिया फलड इफैक्टिड हो गया है। इनके बनने से सारा एरिया फल्ड इफैक्टिड हो गया है। इनकी पहले जो तजवीज थी वह यह थी कि पुरानी नहर के साथ–साथ दूसरी नहर खादेंगे और वह खोद सकते हैं। एक करोड़ रूपया और खर्चे हो जाता और दूसरे मुआवजा भी जमींदारों को नहीं देना पड़ता। आज लोगों को मुआवजा उतना नहीं मिला जितनी उनकी पैदावार होती है लेकिन कुछ को मिला है। कुछ को जिनकी कलर जमीन थी उनको अच्छा मिल गया। कईयों को लाभ हो गया लेकिन कुछ जमींदारों को बहुत घाटा हुआ। कुछ जमींदारों की जमीन 25 हजार रूपये एकड़ से कम की नहीं थी। वे उसें तीन–तीन, चार–चार फसलें पैदा करते थे लेकिन आज वे उससे महरूम हो गए। उस आसपैक्ट को इन्होंने नहीं देखा। उनको 8 हजार और

10 हजार रूपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे दिया। यही नहीं किसी की जमीन इधर रह गई और किसी की जमीन उधर चली गई। अब पुल नहर के ऊपर दो मील के फासले पर होता है और आप जानते हैं कि नहर को बिना पुल के क्रास नहीं किया जा सकता। वह खादर का ऐरिया कहलाता है। यदि पानी गांव मैं रूक जाए तो दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं रहता सिवाय इसके कि वह गांव नरक बन जाए। इस आगमैंटशन नहर के बनने से पहले भी हमने सुझाव दिया था कि हरियाणा के अन्दर यह जो नहर खुद रही है या अब मौजूद है इससे नुक्सान होगा। अगर इस जमुना दरिया के किनारे–किनारे खोदते तो मैं समझता हूं कि यह फ्लड को रोकने में को रोकने में मददगार साबित होती।

अब स्पीकर साहब, देखने वाली बात यह है कि जो पैसा सरकार ने प्रयोग किया है उसका प्रयोग कैसे हुआ है। आप जानते हैं कि जल्दी मतें वेस्टेज होती है। अगर आज हम सड़कों और किसी और मामले के अन्दर देखें, उसका जायजा ले तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें बहुत गड़बड़ है। यदि मौके पर जाकर देखा जाए और उसकी इंक्वायरी की जाए तो आपको पता लगेगा कि लगा तो 100 मजदूर लेकिन दो सौ की हाजरी भर दी गई। मुझे मालूम नहीं कि पी.डब्ल्यू.डी के बारे में कहां तक सच है लेकिन हमें ऐसा बताया गया है और इस तरह की बड़ी अफवाह है। एक मजदूर के हिसाब से 17 क्यूसिक फीट मिट्टी पड़ी। अगर यह गल्त है तो ठीक बात है लेकिन अगर यह सरकारी या

अर्द्ध–सरकारी रिपोर्ट है तो इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि इसमें सरकार का कसूर है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो रूपया हम लेते हैं उनका इस्तेमाल भी ठीक होना चाहिए। यह कहां की अक्लमंदी है कि rob peter to pay paul एक इलाके को नुक्सान पहुंचाएं और दूसरे को फायदा पहुंचा दें। मेरी हमदर्दी भिवानी तहसील से, महेन्द्रगढ़ तहसील से और दूसरी तहसीलों से है और मैं चाहता हूं कि सभी जगह डिवैल्पमैंट के काम हों। कौन नहीं जानता कि हिसार जिला हमेशा अकाल के मुंह में रहता था और वहां इससे छुटकारा दिलाने के लिए कोई काम होना चाहिए था लेकिन मैं फिर भी यह कहता हूं कि यदि हम एक इलाके को तो रोटी दें और दूसरे की छीनने की कोशिश करें, यह कोई तरक्की नहीं है। कोई इस बात को पसन्द नहीं करेगा। फिर आप देखें टयूबवैल्ज लगाए जाएंगे, राडौर के एरिया में टयूबवैल ये खोद रहे हैं क्यों नहर का पानी इस वक्त वहां नहीं लगता। एक नहर भी इन्होंने खोदी है। किसी वकत वह फ्लड अफैक्टिड ऐरिया था। लोगों ने कहा कि पानी ज्यादा है इसलिए इसे निकाल करके दिल्ली में दे दीजिए। तो दिल्ली में वह पानी दिया जाता था। तो इस पानी को आगमैंटेशन टयूबवैल लगा करके दिया जाए। लेकिन अब क्या हालत है? जो कुंए 18 फुट पर पानी देते थे वे आज 60 फुट पर पानी देते हैं। इस नहर के खुदने से पहले, नए टयूबवैल खुदने से पहले हकीकत किसी वक्त यह थी कि 18 फुट पर पानी टयूबवैल दे देता था। लेकिन आज जमींदारों के खेत में या जमीन में जो मोटरें लगीं वे ऊपर की

ऊपर धरी रह गई हैं क्योंकि पानी 60 फुट नीचे चला गया। जब यह नहर खुद जाएगी तो और तो कोई डैम क्योंकि बना नहीं इसलिए पानी कहां से आएगा? लेकिन ये कहते हैं कि पानी मिलना है। (विघ्न)

गृह मंत्री: (श्री के.एल. पोसवाल) ग्राउन्ड वाटर का सर्वे हो चुका है।

चौ. चाँद राम: वही मैं कह रहा हूं। यह भी देख लीजिए कि यह भी हकीकत है क्या? आपने जब यह सर्वे कराया है तो इस सर्वे को भी कराने में क्या हर्ज है?

श्री के.एल. पोसवाल: यह भी करवा रखा है।

चौ. चाँद राम: भिवानी के जमींदार आपको जितने प्रिय हैं उतने ही प्रिय करनाल के भी होने चाहिएं। आज से दस साल पहले की बात है कि 18 फीट पर पानी मिल जाता था लेकिन आज 60 फीट पर पानी चला गया है, मोटरें टंग गई और जमींदारों को फिर बोर कराने पड़े। बगैर एक नहर खुदे अगर 60 फीट नीचे पानी जा सकता है तो जब यह खुद जाएगी तो क्या होगा? ठीक है इनकी साईस कहती है कि बहुत नीचे का पानी लेंगे, ऊंचाई का नहीं। (विघ्न) ..... तो आज नहीं, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में उस एरिया को तो पानी से सोतेंगे, नहीं सोतेंगे तो कहां जाएगा वह पानी? यह थोड़ बहुत पानी नहीं है। हजारों क्यूसिक है। कोई पांच–दस क्यूसिक नहीं है। (विघ्न) .....

इस चीज को जो जमींदारों की चीज है जिसे वे बार–बार कहते हैं, उसे समझो। वे कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में आएं, तब भी बार–बार कह रहे हैं। क्या उनको तसल्ली देने की आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि आज की साईस की ईजाद यह कहती है और पुराने जमाने की ईजाद बदल गई है। क्या आपका यह फर्ज है कि आप जबरदस्ती मुआवजा देकर या पुलिस को भेजकर जमीन पर कब्जा करके नहर को खोद लें? आज वैलफेयर स्टेट है, जब वजीर या मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वे किसी एक एरिया के नहीं रहते बल्कि सारी स्टेट के और सभी वर्गों के हो जाते है।

कृषि मंत्री (चौ. भजन लाल): नहर जमीन में से ही जाएगी आकाश से तो जाएगी नहीं।

चौ. चांद राम: आपका तो कृषि के वजीर के तौर पर पर और भी फर्ज है। मैं कब कह रहा हूं कि आसमान से जाएगी। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इसे आप नदी के किनारे–किनारे से निकालते तो पानी ज्यादा मिलता और लोगों को नुक्सान भी नहीं उठाना पड़ता 50 लाख रूपया, 60 लाख रूपया या एक करोड़ रूपया और खर्च हो जाता। यह हमारे वक्त की स्कीम थी। हम भी कहते थे कि खुदनी चाहिए लेकिन हमने उस वक्त इसे नामंजूर कर दिया था। हमने कहा था कि इसको ऐग्जामिन कर लिया जाए। हमने यह कैबिनेट में नामंजूर की थी। हम तो चाहते थे कि टौंस, गिरि और जमुना पर बांध बनाए जाएं। जमुना के बांध का मुझे, अफसोस है, चाहे हम थे या ये हैं, 6 साल के बाद भी उस

स्कीम को हम एक इंच आगे नहीं बढ़ा सके। कुछ कौरसपौडैन्स तो हुई होगी। सारा पानी वेस्ट जाता है। मल्टीपरपज प्रौजेक्ट से बिजली भी पैदा हो सकती है। उसके बारे में कदम उठ जाता तो इस स्कीम से और अच्छा होता।

मैं थर्मल प्लांट की भी बात करता हूं। थर्मल प्लांट अभी तक केवल एक लगा पाए, हमारे प्लांटस दूसरे नहीं लग पाए। आप दूसरे देशों में देखें। यूगोस्लाविया में देखिए। हम तो पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने थर्मल प्लांटस लगा–लगा करके बिजली की मिकदार जो है वह ज्यादा की है। किसी देश में बिजली नहीं है तो चाहे कितनी रियायतें दें, जमीन दें, कितने कर्जे दें, इंडस्ट्रीलाईजेशन नहीं हो सकती। औद्योगिकरण के लिए, उद्योगपति के लिए, उद्योग सरकार भी लगाए तो उसके लिए भी, शक्ति बहुत जरूरी है, बिजली उसके लिए जरूरी है। अगर बिजली किसी प्रदेश में नहीं होगी तेा बेशक कर्जे दे दिए जाएं। जब बिजली नहीं होगी तो कोई उद्योगपति आपके प्रदेश में नहीं आएगा। परन्तु बिजली के मामले में पिछले दो–चार महीनों में क्या हुआ, यह सबके सामने है। कुदरत की बात तो किसने जानी परन्तु इसको सप्लीमेंट करते थर्मल प्लांट से।

स्पीकर साहब अब मैं ऐम्पलायमैंट आसपैक्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। आज तो बहुत सा विकास का काम मन्दा पड़ गया है। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) आज फाईनैन्शल क्राइसिज हैं। फाईन्नैशल जहाज को इवन कील पर लाने के लिए

सरकार कोशिश कर रही है। में सराहना करता हूं कि कुछ कदम ऐडमिनिस्ट्रेशन में बचत के लिए सरकार से उठाए भी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में बचत हम कहां कर रहें हैं? यह लोअर लेवल पर हो रही है, कोई क्लर्क निकाल दिया, कोई चपडासी निकाल दिया, कोई स्वीपर निकाल दिया। तो उस तरह से बड़ी भारी बचत होने वाली नहीं है। हम टोप हैवी ऐडमिनिस्ट्रैशन कर लें। कौन से अफसर को उनमें से निकाला गया? सरकार बतला सकती है क्या, कि फलां निकाला? इन्होंने निकाला क्या, निकाले टीचर्ज। आज कई स्कूल बगैर मास्टरों के हैं। हमारे यहां स्कूलों में टीचर्ज नहीं हैं। जहां पर आठ टीचर्ज की जरूरत है वहां पर चार लगाये हुए हैं। यह कौन सी एकोनोमी हैं। दुनियां का कोई भी ऐसा फाइनैन्शल एक्सपर्ट यह नहीं कहेगा कि स्कूलों को बिना टीचर्ज के रखा जाये और कोर्ठ भी क्रूर स क्रूर व्यक्ति यह नहीं कहेगा। यह तो बैड एकानोमी है। सरकार अन–प्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर तो कर रही है लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप देख रहे हैं कि रैस्ट हाउसिज में कितना काम हुआ है। कोई भी ऐसा रैस्ट हाउस नहीं है जो एयरकन्डीशन्ड न हो। हर रैस्टाहाउस में एयरकन्डीशनर लगे हुए हैं। आज की सरकार के मंत्री बगैर एयरकन्डीशनिंग के आराम नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। हम तो गर्म मुल्क में पैदा हुए हैं, हम गर्मी बरदाश्त कर सकते हैं। हमारे यहां तो खजूर का पंखा झोला करते हैं, हमें एयरकन्डीशनिंग को क्या आवश्यकता है? पहले एयरकन्डीशनिंग जरूरी है या टीचर्ज जरूरी हैं।

विकास मंत्री (श्री श्याम चन्द): जब आप मिनिस्टर थे तब भी तो एयरकन्डीशन्ड कमरे होते थे।

चौ. चाँद राम: हमारे टाईम में हमने कोठियों में नहीं लगवाये थे। हमारे टाईम में केवल दफ्तरों में ही लगे हुए थे। कोठियों में तो आपके टाईम में ही लगे हैं। आप इस बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपने लगवाये हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। आपकी हकूमत है, आपको मजोरेटी है आप लगायें। हम किसी को कया दोष दे सकते हैं। सवाल तो यह है कि क्या जनता इसको पसन्द करती है? क्या यह वक्त की जरूरत है? यह वक्त के मुताबिक नहीं है। हमारा अन–प्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर बढ़ा है। हम एक–एक, दो–दो लाख रूपया अन–प्रोडेक्टिव एक्सपेंडीचर कर रहे हैं। लेक बना रहे हैं। आज मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। यह हमारे बाप–दादा का पैसा नहीं है, यह पब्लिक का पैसा है। श्री चन्द्रशेखर जैसे मैंम्बरों ने कहा है कि हम अन–अवेयरली चले जा रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिये क्योंकि किसी ने कहा है:–

Ceaser's wife should be above board.

श्री के.एल. पोसवाल: चौ. साहब हमने तो बढ़ौतरी की है, फजूलखर्ची नहीं की।

चौ. चाँद राम: बड़ी अच्छी बात की है। आपने तो अक्लमंदी की है। अक्लमंद बढ़ाते ही हैं। अच्छा है एक लाख से

दो लाख बनाने चाहिएं। मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाता चाहे उसने किसी भी तरह से बढ़ौतरी की है चाहे तन्खाह से की है, चाहे किसी और तरीके से की है। अच्छी तरह अपने–अपने पैसे को सुरक्षित रखा है। अपने बच्चों के लिए बढ़ोतरी की है उनके काम आयेगा। जब किसी दिन देश में डीमोनेटाइजेशन होगी तो उस पर कब्जा कर लिया जायेगा। मैं इनकी बातों को कोई बुरा नहीं मानता।

श्री के.एल. पोसवाल: आप इसी भरोसे पर रहना।

चौ. चाँद राम: मैं सदन का ध्यान सरकार के आंकड़ों की ओर दिलाऊंगा, यह सरकार की रिपोर्ट कहती है, वजीर कहते हैं कि 22 करोड़ लोग हिन्दुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 20 रूपये महीने की है। हम यहां पर 35 रूपये रोजाना लेते हैं। मैं औरों के बारे में नहीं कह रहा, मैं भी लेता हूं। मैं इस बात का कायल हूं कि इस 20–25 साल के अन्दर कोई आदमी बिना रोजगार के नहीं रहना चाहिए था। मैं तो यह चाहता हूं कि जैसे कांस्टीच्यूशन में राइट टू प्रोपर्टी है, इसी प्राकर से कांस्टीच्यूशन में राइट टू वर्क भी होना चाहिए। हरेक आदमी का हक होना चाहिए कि उसे काम मिले। ऐसे मुल्क हैं जिनमें यह हक हे कि हर आदमी को सात घन्टे का मिलेगा। उस सात घन्टे में उसको 1500 रूपये तनख्वाह मिलेगी। पहले हमारे मुल्क में दूध दही का खाना था। आज दूध तो क्या मिलेगा दाल भी खाने को नहीं मिलती। महंगाई दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है। एक काफी

पुरानी हिस्टरी की बात आपको बताऊं जब यहां पर नादिरशाह आये थे, तो उनके सामने खाने के साथ दाल भी परोस दी गई। उन्होंने दाल के बारे में पूछा कि यह क्या चीज है? उन्हें बताया गया कि यह दाल है और यह भी अनाज में ही शामिल है। वे बड़े हैरान हुए और उन्होंने काह जिस देश के लोग अनाज के साथ अनाज मिला कर खाते हों वह देश कैसे आजाद रह सकता है। यह तो पुराने इतिहास की बात है। आज हमारे यहां चीनी इतनी मंहगी होती जा रही है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पहले डेढ़ रूपये किलो मिलती थी अब चार रूपये किलो मिलती है।

एक मैम्बर: आपके टाईम में तो जो भी नहीं मिलते थे।

चौ. चाँद राम: हां उस वक्त सब भूखे मरते थे? आप तो अब सब खुश हो, आप तो एम.एल.एए. बनकर आ गये हो। आपका पेट तो भरा है और चाहे दुनियां भूखी मरे। अगर उस टाईम पर जौ नहीं मिलता था तो गेहूं खूब मिलता था जो पहले बटेऊ को दिया करते थे। हमारे टाईम में 65 रूपये क्वींटल गेहूं का भाव था जौ और मक्की का चाहे कुछ भी भाव हो। आज गेहूं का भाव 110 रूपये क्वींटल है ओर चने का भाव तो 140 रूपये क्वींटल है मुझे पता नहीं कि यह महकता पोसवाल साहब का है या चौ. भजन लाल जी का है लेकिन मैं आपके जरिए यह अर्ज करूंगा कि 76 रूपये क्वींटल के भाव गेहूं खरीदा हुआ आज इतना मंहगा बेचा जा रहा है।

चौ. भजन लाल: 82 रूपये क्वींटल के हिसाब से दे रहे हैं।

चौ. चाँद राम: फिर तो अच्छी बात है, अगर इस भाव से दे रहे हैं। अगर गवर्नमैंट प्रोफिट नहीं ले रही है तो ठीक किया है लेकिन सबको 82 रूपये क्वींटल नहीं मिलता है। गांव में सब जगह दूकानें खोली हुई हैं तो ठीक है, अगर हर गांव में डिपो नहीं तो वे कैसे इस भाव से खरीद सकते हैं।

चौ. भजन लाल: तीन हजार डिपो गांवों में खोले हुए हैं।

चौ. चाँद राम: गांव तो हरियाणा में छः हजार हैं।

चौ. भजन लाल: तीन हजार गांव में खोले हुए हैं और शहर इन से अलग हैं। जिस गांव से डिमांड आती है उसी गांव में खोल देते हैं।

चौ. चाँद राम: मैं तो यह चाहता हूं कि अगर सरकार इस क्रय और विक्रय को अपने हाथ में ले तेा ही यह मंहगाई दूर हो सकती है। जो ब्लैक–मार्किटिंग होती है यह सब दूर हो सकती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो चार–पांच रूपये के भाव से चीनी बिक रही है यह डेढ रूपये किलो के हिसाब से बिक सकती है। आज किसी मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी, किसी की तन्खाह नहीं बढ़ी। किसान से गन्ना साढ़े–सात और 8 रूपये क्विंटल के हिसाब लिया गया था। हम जब यह कहते थे कि किसानों को गन्ने की

कीमत ज्यादा दो तो कोई भाव नहीं बढ़ाया गया। मिल–मालिक ने इतने सस्ते भाव से गन्ना खरीदा और आज इतने मंहगे भाव पर चीनी बेच रहा है। वैसे चीनी और अनाज की कमी नहीं है। इस मंहगे भाव से कितनी ही चीनी मार्किट से ली जा सकती है।

उपाध्यक्षा: आप चेयर को ही एड्रैस करें।

चौ. चाँद राम: मैं देख तो उनकी तरफ रहा हूं और एड्रैस आपको कर रहा हूं। मैं केवल उनका रूझान देख रहा हूं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आज डेढ़ रूपये से साढ़े चार रूपये किलो चीनी का भाव हो गया है। ग्रोअर और काश्तकार को भाव बढ़ने से कुछ नहीं मिला। जो मुनाफा ये ले रहे हैं या काश्तकार को मिलना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बम्बई में सन् 1970 मैं एक रेजोल्यूशन पास हुआ था लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। हमारे यहां दो कोआपरेटिव मिलें हैं और एक प्राइवेट मिल है। अब इस मंहगाई के टाईम में उस प्राइवेट मिल का मुनाफा लि रहा है। अगर सरकार के मिलों को मिलता तो भी देखा जाता परन्तु यह तो प्राइवेट को ही मिल रहा है। उस मिल को मुनाफा जाने से न हमारे किसी किसान को ही फायदा है और न ही किसी मजदूर को फायदा है। वह सारे का सारा एक आदमी की जेब में जा रहा है। हमारे यहां जो यमुनानगर में शूगर मिल है इसको

नेशनलाइज करना चाहिए और जो कांग्रेस की पालिसी है उसको इम्पलीमैंट करना चाहिए।

मेरी समझ में नहीं आता सरकार क्यों नहीं उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहती और जान–बूझ कर टाल–मटोल करती जा रही है। अगर इस मिल का राष्ट्रीयकरण कर दियसा जाये तो यह पहले नम्बर पर होगा।

उपाध्यक्षा: आप कितना टाईम और लेंगे।

चौ. चाँद राम: मैंने तो कोई दस मिनट ही लेने हैं।

उपाध्यक्षा: आप दो–तीन मिनट ओर ले लें।

चौ. चाँद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं रोजगार के बारे में बोल रहा हूं इन डिमांडज में एक जगह पर क्रैश स्कीम के तहत रूरल एम्पलायमैंट के लिए दस लाख रूपया रखा गया है और दूसरी स्कीम के तहत बेरोजगार पढ़े–लिखे लोगों के लिए 22 लाख रूपया रखा गया है। इससे कोई बहुत बडद्या फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसमें इन्होंने यह लिखा है कि यह खर्च विद–इन सेविंग्ज होगा। ये रूपया, हम जो बचत करते हैं, उसका होगा। इसका मतलब यह है कि एम्पलायमैंट के लिये कोई और खर्चा नहीं होगा बल्कि जैसा ये कहते हैं उसी ग्रान्ट में से होगा, जो पहले दी हुई है। ये कहते हैं कि दी हुई ग्रान्ट में से बचत करनी है। मैं समझता हूं कि यदि ये किसी अनप्रोडिक्टिव आईटम्ज में से बचत करते और फिर कहते कि हमने इसे रोजगार के लिये रखा

दिया, तो अच्छी बात होती। आज रोजगार की ब्या हालत है? बड़े रोजगार की तो बात ही क्या, आज लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल रही। मेरा ख्याल है इस वक्त सरकार के पास हजार–डेढ़ हजार मजदूर काम कर रहे होंगे। आज सरकार कितने आदमियों को सड़कों पर काम के लिये लगा रही है? कितने ऐसे आदमी हैं, जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, चाहे वे हरियाणा के हैं या राजस्थान के है? सरकार कहेगी कि ये राजस्थान के हैं क्योंकि हमारे प्रदेश में तो फुल एम्पलायमैंट है। यहां पर तो मजदूर मिलते नहीं हैं, इसलिये हमने बाहर से मजदूर बुलाये हैं। यह बड़ा श्रेयस्कर काम है। लेकिन अगर आप गांव–गांव में जाकर देखें, लोग मजदूरी तक के लिये घूमते फिर रहे हैं। आप सभी ने इलैक्शन लड़ा है। यह भी देखा होगा कि दरख्वास्तें लिये फिरते हैं कि हमें मिट्टी का काम दे दो। मिट्टी खोदने का काम मांगते हैं और कोई कलम वगैरह का काम नहीं मांगते क्योंकि कलम के काम के काबिल तो हमने उन्हें बनाया हो नहीं। इमने एजुकेशन को कम्पलसरी नहीं किया। इसमें हम सब गुनाहगार हैं और मैं भी इसमें शामिल हूं। एक नागरिक का जो सबसे पहला हक है वह है: राईट टू एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकर। अगर हमने सब लोगों को पढ़ा–लिखा नहीं बनाया तो हमें यह चाहिए भी और हम कहते भी हैं कि बगैर–पढ़े–लिखे लोगों को भी काम का हक होना चाहिए। हमने एजुकेशन को कम्पलसरी न करके एक बहुत बड़ी नैगलीजैन्सी की है, क्राईम किया है और हम सबने जुर्म किया है। उन लोगों का कहना था कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं

हैं तो मिट्टी का काम करने के तो काबिल हैं। अभी हमारे देश में मशीनरी नही आयी। मैं तो रूस से होकर आया हूं। वहां पर मिट्टी खोदने का काम मजदूर नहीं करते, मशीनें करती हैं। लेकिन हमारे यहां पर मिट्टी खोदने का काम मजदूर नहीं करते, मशीनें करती हैं। लेकिन हमारे हां पर छोटी–छोटी लड़कियां, 14–14, 18–18 वर्ष की, और औरतें मिट्टी ढ़ोती हैं। 10 दिन का बच्चा होता है ओर उसको सड़क के पास पेड़ के नीचे डाल कर काम करती हैं। अगर वे राजस्थान से भी आती हैं तो भी मैं कहता हूं कि हैं तो वे भी हमारे देश की ही। किसी दूसरे देश की नहीं हैं। हमने उनके लिये कया अच्छा इन्तजाम किया है, अगर उन्हें एम्पलायमैंट भी दी है? मजदूरी के तीन रूपये या कहीं ज्यादा से ज्यादा चार रूपये देते होंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि पिछले चार महीने में मजदूरी घटी है, बढ़ी नहीं। मैं खुश हूं कि हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। अगर सरकार उनका महंगाई अलाउन्स नहीं बढ़ायेगी तो वे क्या करेंगे? वे आर्गेनाईज्ड हैं, संगठित हैं, वे मांग करेंगे और सरकार नहीं सुनेंगी तो गवर्नमैंट को पैरेलाईज कर सकते हैं। लेकिन इस देश के लाखों आदमी ऐसे हैं जो असंगठित हैं, वे कया करैंगे। वे मजदूरी की तरफ जायेंगे। लेकिन आपके पास तो अब उनके लिये मजदूरी का भी प्रोवीजन नहीं है। इस बारे में मैं समझता हूं कि आप गांव–गांव में सर्वे कराइये और देखिए कि कितने मजदूर हैं जेा बेाकर हैं। कुछ समय पहले यहां पर गवर्नमैंट आफ इंडिया की एक अन–एम्पलायमैंट कमेटी आयी, पता नहीं अखबारों में जो

निकला है वह सही है या गलत, हरियाणा सरकार उसे कहती है कि हमारे यहां तो कोई बेरोजगहार ही नहीं है। अगर आपने उन्हें ऐसी रिपोर्ट दी है कि हमारे यहां अन–एम्पलायमैंट नहीं है तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं किया है। गवर्नमैंट आफ इंडिया से अनएम्पलायमैंट के नाम से कितना रूपया मिलना है, उसका हमें अन्दाजा नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप उनसे इस चीज के लिये रूपया मांग सकते थे। लेकिन आपने उस कमेटी के सामने थोड़ी शाबाशी लेने के लिये यह कह दिया कि हमारे यहां बेरोजगारी नहीं है और हमने अपने यहां से बेरोजगारी को हटा दिया है। जब आपका सड़कों का क्रैश प्रोग्राम चल रहा था, उस वक्त 50–60 हजार या एक लाख के करीब मजदूर काम पर लग रहे होंगे लेकिन अब, मेरे ख्याल में, सारे हरियाणा में 5000 से ज्यादा मजदूर ऐसे नहीं हैं जो काम पर लगे हुए हों। अब जो सड़कों का काम नहीं करते, क्या वे अब बेकार नहीं हैं? हमें उनकी दाद देनी चाहिए कि वे चुप हैं और शान्त हैं। लेकिन अब लोग भूखे मरने लगेंगे तो कोई अपने हदय को रोक नहीं सकेंगा। यहां पर औद्योगिक और एजुकेटिड अन–एम्पलायमैंट की बात कही गयी। उन्होंने स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की बात कही। क्या इस देश के लोगों को यह मालूम नहीं कि जो लोग पहले जूते बनाते थे, आज उनके जूते नहीं बिकते। आज रबड़ की और प्लास्टिक की चप्पलें, दो–दो, ढ़ाई–ढ़ाई और तीन–तीन रूपये में आसानी से मिल जाती हैं। आज हर गांव के लोग, ये रबड़ और

प्लास्टिक की चपलें पहने फिरते हैं। ऐसे औद्योगिकरण की पालिसी, सरकार के लिये एक शर्म की बात होनी चाहिए।

कुछ दिन हुए मैं एक किताब पढ़ रहा था। उसमें नीति–सार का जिक्र आया। उसमें शूगर नीति का भी कुछ जिक्र किया गया था।

श्री श्याम चन्द: कौन सी किताब थी?

चौ. चाँद राम: इसे तो आप भी पढ़ लेना। ऐसे दिन तो आने–जाने बाने हुए हैं। उन नीति–सार में यह लिखा है कि अगर किसी आफिसर या सरकी कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत आये, तो जो राजा होगा, वह प्रजा का पक्ष लेना। उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर सरकारी आफिसर के खिलाफ शिकायत आये तो राजा प्रजा का पक्ष लेना। क्योंकि किसी ने कहा है कि:–

Ceaser's wife should be above board.

उनके हाथ में बहुत हथियार है! मैं यह कहता हूं कि हम इस बात में नहीं जाते कि वे हरियणा के नहीं हैं, आखिर वे इस देश के और इस वतन के हैं, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो अफसर ऐसे हों कि जिनके खिलाफ पावर की ऐरोगैन्स ककी और फंडज के मिसयूज की शिकातयें आयें, दरख्वास्तें आयें, मैं यह नहीं समझता कि उनकी जांच क्यों न हो? धामड़ गांव के लोग हमसे मिले। उन्होंने कहा कि हम छः महीने से दरख्वास्तें दे रहे हैं कि हमारे स्कूल का एक

मास्टर है जो फंडज का मिसयूज कर रहा है, खा रहा है, लेकिन सरकार हमारी दरखास्तों पर गौर ही नहीं करती। छः सात महीने हो गये हैं। इस बारे में कुछ नहीं हो रहा। एक गांव और है, कैलाव्ड़, वहां पर भी ऐसे ही है। मैंने वहां पर इस किस्म के इश्तहार भी देखे हैं। दौलता साहब ने मुझे अभी बतलाया है कि एक गांव है, चिमनी, वहां पर एक साल हो गया, अभी तक भी हैड–मास्टर नहीं बदला गया। हमें इन्हें इतनी खुली छूट नहीं देनी चाहिये कि वे राज करते चले जायें। मैं यह कभी नहीं कहता कि हमारी सरकार के अफसर ठीक नहीं हैं। मैंने कभी आई.ए.एस. अफसरों को क्रिटिसाईज नहीं किया। मैंने कभी भी गलत तौर पर अधिकारियों की नुक्ताचीनी नहीं की। (चौ. प्रताप सिंह दौलता की ओर से दूसरी सीट पर बैठे हुए विघ्न)

Deputy Speaker: I would request the Honourable Member, Ch. Partap Singh Daulta, that he should sit properly in the House and to speak from his seat.

चौ. चाँद राम: लेकिन अगर कोई एरिंग आफिसर्ज हैं, चाहे आई.ए.एस. हैं या एच.सी.एस. या पी.सी.एस. हैं या हरियाणा सरकार के किसी दूसरे लेवल के अफसर हैं, मैं कहूंगा कि उन्हें और भी ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। ये अफसर लोग भी उतने देशभक्त बन सकते हैं, जितना एक पोलिटीशियन होता है। पोलिटीशियन्ज इसलिये काम का क्रैडिट लेते हैं क्योंकि अफसर उनके बताए कामों को एम्पलीमैंट करते हैं। चाहे बिजली का काम हो या दूसरा, मैं समझता हूं कि अफसरों ने बड़ी अच्छी

तरह से काम किया है, तभी तो सरकार को बिजली के बारे में क्रैडिट मिला। मैं इस बात को कभी पसन्द नहीं करता कि हमारे अफसरों को डिसकरेज किया जाये।

टीचर्ज के मामले में मेरे दिल में बहत सी बातें हैं। मुझे कुछ दिन हुए बस स्टैंड पर कुछ टीचर्ज मिले। उन्होंने कहा नमस्ते जी। बड़े अच्छे–अच्छे चेहरे थे। कहने लगे कि हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं। मैंने पूछा, टीचजर हो ना? क्योंकि मुझे पता है दो–दो, चार–चार के गुप्स में टीचर मिलेंगे, कोई सड़कों पर रहता हे, कोई बस–स्टैंड पर रहता है तो कोई कहीं और रहता है। वे बेचारे अपने घरों में बीस–बीस, तीस–तीन मील दूरी पर लगे हुए हैं। मेरा कहना यह है कि ये हमारे देश की प्रेरणा हैं और आने वाली पीढ़ी को बताना, उनके हाथ में हैं .....

चौ. भजन लाल: उनको कौन पसन्द करेगा, अगर वह अपना कोई फर्ज न समझें? वह भी तो अपना कुछ फर्ज समझें!

चौ. चाँद राम: आप याद रखिये, डिस–कन्टैंटिड माइन्ड, असंतुष्ट दिल, कभी पूरा काम नहीं करता। आप उनमें कंटैंटमैंट लाइये। बहुत देर से यह मामला हैंगओवर होता चला आ रहा है। टीचर्ज में अगर कन्टैंटमेंट होगी तो ही अच्छा काम करेंगे। इसलिये आप उनका एक डैपुटेशन बुलाइये और इस मसले को हमेशा के लिये खत्म कर दें। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि लोग हमारे मुंह पर ही कहते हैं कि अब चौ. चांद राम का बयान

आ गया, अब हमारा बनता काम भी टल जायेगा। इसलिये मेरी एक गुजारिश यह है कि आप उनका डैपुटेशन बुलाकर उनसे पूछ लीजिये और उनके मसले को तय कर लीजिये। मैं यह समझता हूं कि मैंने आपके सामने काफी कुछ कहा है, इस हिसाब से नहीं कहता कि यह अकेली गवर्नमैंट का सवाल है। इसलिये कहता हूं कि यह मामला काफी देर से हैंग ओवर कर रहा है और जो जरूरतैं पहले पूरी नहीं हुई, वे आज पूरी हो सकती हैं। अगर पहले गलती हो भी गयी है, तो आज उसकी दुरूस्त किया जा सकता है।

हमारे यहां जो अन–एम्पलायमैंट है वह सिर्फ एजुकेटिड लोगों में ही नहीं है बल्कि अन–एजुकेटिउ तब्के में भी बहुत है। वे लोग जो आज की सरकार का आधार हैं, उनमें अन–एमपलायमैंट बहुत है। मेरा विचार है कि अगर यह आधार ही हिल गया तो बहुत मुश्किल हो जायेगी। प्लानिग कमीशन जिसके पहले प्रधान पंडित जवाहर लाल नेहरू थे, के पेज 51 पर 'लैंडलैस' के ऊपर एक चैपटर है। उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर देश के भूमिहिनों के असंतोष रहेगा, बेचैनी रहेगी तो इस देश का आधार हिल जाएगा। देश में इनस्टेबिलिटी रहेगी। अगर आप यह सोचने हैं कि हमारे पास पुलिस हैं, हमारे पास फौज है तो मैं कहना चाहता हूं कि फौज और पुलिस में भी तो गरीब आदमी हैं। वहां भी ज्यादा सिपाही ही होते हैं अफसर तो कम ही होते हैं। यह बात दूसरी है कि डिस्पिलिन के आधार पर आप उनको न बोलने

दें लेकिन असंतोष तो उनके अन्दर रहेगा ही। कल ही मैंने देखा शाहदरा की बात थी। मैं दूसरी स्टेट के मामले में दखल तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कहना, चाहता हूं कि वह एक छोटी सी शिकायत थी। जो अफसर था उसको गिरफतार कर लिया जाता। लेकिन इस देश में आप देखें जो मजिस्ट्रेट हैं, आई.पी.एस. अफसर हैं, वे दिन में शराब पीते हैं, शराब पीकर कचहरी में बैठते हैं। यह कोई शिकातय करने की बात नहीं। आप कचहरी में अचानक जाकर देखें, आप भेष बदल जाएं। आप आज के राजा हैं, वजीर जो होता है वह इस वक्त का राजा है। पांच–चार साल के लिए तो आप भी राजा हैं। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा बस मैं खत्म करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री रामधारी गौड़ (गोहाना): डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल से सप्लीमेंटरी डिमांन्डज के ऊपर बहस हो रही है और आज वही डिमांडज जिनको हमने कल पास किया था, एप्रोप्रिएशन बिल के रूप में यहां हाउस के सामने आई हैं। कल हमारे कुछ साथियों ने बड़ी लम्बी–चौड़ी बातें की और वह यह भूल गए कि आज जो हरियाणा में तरक्की हुई है उस पर हर हरियाणावासी को फख्र है। दूसरे प्रदेशों के निवासी आज हरियाणा वालों को अच्छी निगाह से देखते हैं, इनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हरियाणा मैं बड़ी तरक्की हुई है। मुझे मैसूर जाने का अवसर मिला। उन्हें जब मालूम हुआ तो लोग बधाई देने के लिये आए। कोटाकमंड में भी

लोग बधाई देने के लिए आए। लेकिन हमारे इन भाइयों का तो काम ही सिर्फ नुक्ताचीनी करना है। वे छोटी–छोटी बातें सामने लाते हैं जिनका कि तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। हरियाणा जब नहीं बना था उस टाईम का और आज की तरक्की का आप मुकाबला करके देखें कि हमारे प्रदेश में कितनी तरक्की हुई है। मैं इस बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हरियाणा बनने के पहले यहां 34 लाख एकड़ में सिंचाई होती थी लेकिन आज हरियाणा की 90 लाख एकड़ भूमि काबिले काश्त है। इसके अलावा टयूबवैल से छह लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी लेकिन आज इक्कीस लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती है। टैंकों के जरिए कोई पांच हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी लेकिन आज पचास हजार एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें कि टैंकों के द्वारा सिंचाई होती है। हरियाणा बनने से पहले चालीस प्रतिशत भूमि में सिचाई होती थी लेकिन आज तकरीबन 61 प्रतिशत की संख्या पहुंच चुकी है। अभी कल बताया गया था कि हरियाणा बनने के पहले हमको एक लाख टन अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था लेकिन आज बीस लाख टन अनाज हम दूसरी स्टेटस को भेजते हैं। अनाज की पैदावार में इतनी तरक्की हुई हैं कि कहां तो एक लाख टन अनाज बाहर से मंगवाते थे और कहां हम बीस लाख टन अनाज बाहर भेजते हैं। यह ठीक है कि वही जमीन है, वही किसान है लेकिन उन्हें पहले वे सुविधाएं नहीं मिलती थी। अब किसानों ने हिम्मत से काम लिया और सरकार ने सिंचाई की सुविधाएं दीं, पानी, बिजली और अच्छा खाद दिया और इसी कारण से पैदावार में बढ़ौतरी हुई है।

आपको पता होगा कि हरियाणा में जिन हालात में तरक्की हुई है वह एक काबिले दाद बात है। एडवर्स हालात में तरक्की होना मुमकीन नहीं है। जहां अच्छे हालात हों, अच्छे साधन हों, वहीं तरक्की होती है। जब हरियाणा बना, उस वक्त क्या हालत थी। 1967 की बात मुझे याद है। जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें जो आंकड़े पेश किए गए धन के बारे में, उस वक्त यह अन्दाजा था कि हरियाणा में सिवाए सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के, तनख्वाह देने के, कोई पैसा नहीं है, डिवेलपमैंट के काम के लिए। लेकिन धन्यवाद है चौ. बंसी लाल की सरकार का, जब 1968 में यह सरकार आई तो वही प्रान्त जहां साधन नहीं थे, वहां सिंचाई का प्रबन्ध किया गया, तरक्की हुई, अनाज ज्यादा पैदा हुआ, ज्यादा कारखाने लगे, रेवेन्यू ज्यादा आया और उससे डिवेलपमैंअ बढ़ती गई। मैं आपकी विसातत से बताना चाहता हूं कि यहां पर मोघों की बात की गई। वे भाई यह तो मानते हैं कि पैदावार में इजाफा हुआ है, पानी ज्यादा हुआ, लेकिन फिर भी कहते हैं मोघे कम हो गए। मैं बताना चाहता हूं कि मोघे वहीं कम हुए जो कुछ भाईयों ने जो उधर बैठे हैं, जब पहले सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने कुछ लोगों के साथ रूरियायत की। कुछ बड़े आदमियों को बड़े मौघे दे दिए, ज्यादा पानी दे दिया। जब पानी का बंटवारा बराबर का हुआ तो मौघे कम होने लाजमी थे। मोघे केवल उन लोगों के कम हुए हैं जिनको पहले ज्यादा पानी मिलता था या जिनको बड़े मोघे मिले हुए थे। जब नहर पूरी चलती है, पानी पूरा आता है तो फिर पानी कहां चला जाता है यह तो है नहीं कि

पानी वापिस जमुना में चला जाता हो क्योंकि जमुना की सतह की ऊंचाई तीन सौ फुट ज्यादा है, पानी तो वापिस जा ही नहीं सकता और ऐसा भी नहीं है कि टेल पर ज्यादा पानी दिया जाता हो। यह दोनों मुतजात बातें हैं। जिन लोगों को पहले ज्यादा पानी मिलता था वही आज मीटिंगों में, इस सदन में कहते हैं कि पानी कम मिलता है। पहले कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनको ज्यादा पानी मिलता था लेकिन कुछ बेचारे जो बेजवान थे उनको पानी नहीं मिलता था। अब उन लोगों को भी पानी मिलने लगा है। वह गूंगे वाला गुड़ खाए बैठे हैं। जैसे कि एक गूंगे आदमी को गुड़ खाने का मजा तो आता है लेकिन वह उस मजे के बारे में बता नहीं सकता। वही बात पानी के बारे में है उनको मजा तो आया है लेकिन बोलते नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों का अब दूसरे लोगों के बराबर पानी मिलने लगा है तो वे अब चिल्लाते हैं। मैं यह कहता हूं कि अगर मोघे कम हो गए, पानी नहीं मिलता तो फिर यह बीस लाख टन अनाज जो हम दूसरे प्रदेशों को भेजते हैं वह कहां से आ गया। चौ. चांद राम ने कहा कि यह तरक्की तो होनी ही थी। मैं कहना हूं कि यह तरक्की हरियाणा बनने के पहले क्यों नहीं हो गई। हमारी जो आगमेंन्टेशन कैनाल है, इसके पीछे एक टैक्नीकल बात है और हमारे इंजीनियर बहुत ही सूझबूझ के आदमी है। उनको पता है कि कहां नहर निकालती चाहिए। पहले जो नहरें बनती थीं वह बहुत नीचे में जाती थीं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमने तो नहरों को इस ढंग से निकाला है जिस से हरेक आदमी को पानी मिल सके, हरेक खेत में पानी जा सके। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि लोगों का सरकार द्वारा जो मुआवजा दिया गया उससे लोग बहुत खुश हैं। बहुत से भाई मुझे मिले भी हैं और उन्होंने कहा कि हमें तो इस मुआवजें से बड़ा फायदा हुआ है और ये अपोजीशन वाले यहां पर कहते हैं कि पानी कम हो गया है। सब–सायल वाटर में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पानी कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो। हामरे टयूबवैल 9 सौ फुट से लेकर 1300 फुअ तक गहरे बनाये जाते हैं, जिसके ऊपर की सतह वाले पानी पर कोई असर नहीं पड़ता। हमने यह सर्वे भी करवा के दखे लिया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमने वेस्टर्न यमुना कैनाल को रिमाडल करवाया है। जब बरसात के मौसम में यमुना में पानी अधिक होता है तो हम इस नहर द्वारा लोगों को अढाई हजार क्यूसिक पानी अधिक देते हैं अगर यह नहर रि–माडल न होती तो इस अढ़ाई हजार क्यूसिक पीन का लोगों को लाभ न पहुंचता। यह दिखावे की बात नहीं है। असलियम में लोगों को फायदा पहुंचा है। अढाई हजार क्यूसिक पानी से बहुत पैडी की उपज होती है। मैंने बताया था कि हरियाणा में किन–किन हालात में तरक्की हुई है, हालांकि यहां कोई इतने साधन नहीं हैं और पंजाब में बहुत साधन थे। यहां हरियाणा में तीन चार किस्म की जमीन है एक ऐसी जमीन है जो बाढ़ में आ जाती है कुछ ऐसी जमीनें हैं जो नहर के बीच में आने से सोर हो गई हैं। एक ऐसी जमीन होती है जहां पानी

पहुंचता ही नहीं है। हम ने इस सबका प्रबन्ध किया है। जो जमीन कल्लर हो गई है, उसको ठीक किया है और जहां पर फल्ड से तबाही होती थी, उसको भी ठीक किया गया है। इस साल सिर्फ मेवात के इलाके में कुछ पानी आया है। सफीदों, गोहाना और सोपीपत का इलाका जहां आये साल बाढ़ आती थी, अब वहां बाढ़ वगैरह नहीं है ओर इसलिये वहां पर अब अच्छी फसलें होती हैं। इस प्रकार ऐसी जमीनों को भी बचाया गया है, जहां कोई पैदावार नहीं होती थी। कुछ ऐसी जमीनों हैं, जो उपजाऊ हैं, उनको पानी नहीं मिलता था, अब उनको भी पानी देने का प्रबन्ध किया जा रहा है। देखिये कुदरत के आगे किसी की भी पेश नहीं चलती। कुदरत के साथ लड़ना इन्साफ के बस की बात नहीं है, लेकिन हमने आगमेन्टेशन कैनालज में इतना पानी मुहैया करने का प्रबन्ध किया है यमुना में लीन सीजन तकरीबन दो हजार क्यूसिक पानी होता है लेकिन सोलह सौ क्यूसिक पानी रह जाता है। इस कैनाल में 15 सौ क्यूसिक पानी देने का और प्रबन्ध यिका गया है। हमने दादूपुर से लेकर खुबरू तक तकरीबन सारी कैनाल को लाइन्ड कर दिया है ओर हम बी–एस–बी व देहली ब्रांच को भी अब पक्का करने जा रहे हैं व सब–ब्रांच बावल कैनाल को पानी दिया जाएगा, पक्का भी किया जाएगा और इसका नाम जवाहर लाल नेहरू कैनाल रखा गया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती ही हैं कि जितना तरक्की का काम यहां हुआ है, इतना 100 साल में भी कभी नहीं हुआ होगा, मैं यह दावे के साथ कहा सकता हूं। यहां पर बैठे यह अपोजीशन के मैम्बर बजाये इसके कि इन कामों के लिये सरकार

की दाद दें, कभी पटवारी वाली बात को लेकर, कभी किसी बिजली वाली बात को लेकर हमेशा सरकार की निन्दा ही करेंगे, कभी उन्होंने यह तो कहना ही नहीं कि सरकार ने कोई अच्छा काम किया है। आज इसी वजह से हरियाणा का नाम ऊंचा है और ये लोग इन बातों को तो भूल जाते हैं और छोटी–छोटी बातों को लेकर यूं ही यहां हाउस का टाईम बरबाद कर रह हैं।

उपाध्यक्षा: गौड़ साहब आप कुछ थोड़ा सा शार्ट करिए।

श्री रामधारी गौंड़: डिप्टी स्पीकर साहिबा, तो मैं कैनालज के बारे में बता रहा था। पहले वैस्टर्न यमुना कैनाल की कैपिसिटी 6 हजार क्यूसिक फीट थी अब रि–माडलिंग होने के कारण अब उसकी कैपिसिटी साढ़े 8 हजार हो गई है। यह अपोजीशन के मैम्बर हरियणा में तरक्की की तो बात ही नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले इस हरियाणा में 21 हजार के करीब टयूबवैल थे और अब 1 लाख के करीब चल रहे हैं। अगर तरक्की का कोई काम नहीं हुआ, तो यह कैसे हो गया। लेकिन हमारे भाई यहां पर कहते हैं कि यहां तो भ्रष्टाचार है और अब भ्रष्टाचार करने पर किसी एम्पलाई को पकड़ते हैं तो यह लोग चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि बचाओ। यह हमारे ही भाई–बन्धु हैं। आप अगर ऐसे हालात में सुधार लाना चाहते हैं तो कह कि हम किसी को, जो भ्रष्टाचारी हो, बचाना नहीं चाहते, तभी तो ऐसी बातों में सुधार होगा और फिर जब हम इन हाउस में उन्नति की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि यह हो गया, वह हो

गया। लेकिन जब भ्रष्टाचारी को पकड़ते हैं तो कहते हैं कि नया आदमी था, छोड़ दो। मैं समझता हूं कि इस समय इस तरह से इस किस्म की बातें एप्रोप्रिएशन बिल के समय करके यूं ही इस हाउस का टाइम जाया करने वाली बात है। यही समय हमको किसी डिवैल्पमैंट के कामों में लगाना चाहिये जिससे कि हमें कुछ लाभ हो सके। मल्टीपरपज स्कीम जो है जिस में ब्यास स्कीम का पैसा लगाकर हरियाणा को इससे फायदा होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई फजूल पैसा जाया हो रहा है बल्कि यह तो डिवैल्पमैंट की बात है। इन्होंने यहां डाक बंगलों में एयर कंडीशनिंग के बारे में कहा है। इस हाउस में किसी ऐसी बात का मतलब ही नहीं है। डिवैल्पमैंट के कामों में पैसा लगेगा तभी हरियाणा में तरक्की होगी और यह कहना कि इन छोटी–छोटी बातों में लगकर कुछ नहीं हो रहा है, यूं ही पैसा जाया हो रहा है, यह बातें करना इन लोगों को शोभा नहीं देता। इन अपोजीशन के भाईयों के वक्त में सरकार के पास पैसा था ही नहीं। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि यहां हरियाणा में तरक्की का ऐसा काम हुआ है, जो कि किसी भी प्रदेश मैं नहीं हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक जगह पर जलसा हो रहा था तो वहां पर एक अपोजीशन के मैम्बर ने खड़े होकर कहा कि इन कांग्रेस वालों ने लूट मचा रखी है तो उसी समय एक दूसरे व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि तुम्हारी ईमानदा का हमैं कोइ फायदा नहीं था क्योंकि आपने कोई डिवेल्पमेंट का काम किया ही नहीं था और लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया था। हमें तो यही बेईमान सरकार

अच्छी है क्योंकि उन्होंने बहुत डिवैल्पमैंट कर दी है और इससे हमें बहुत फायदा पहुंचा है अब हमें किसी भी बात की तंगी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात मैं आपको और बता हूं कि हमने अपनी नहरों को रि–माडल करके इतनी गुंजाइश पैदा कर दी है कि अगर रावी, ब्यास का पानी अभी मिल जाए तो हम इस पानी को अपनी मौजूदा नहरों में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

चौ. फूल चन्द (मुलाना एस.सी.): आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले दो दिन से सप्लीमैंट्री डिमांडज पर और आज एप्रोप्रिएशन बिल न. 3 पर बहस हो रही है। लेकिन में समझता हूं कि बहुत पुराने विधायक का जो हर तरह स प्रोसीजर से वाकिफ हैं आऊट आफ दी वे जाकर बातें करते हैं, बल्कि इर–रेलेवेन्ट बातें उन्होंने कहीं, जिनका कि बिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इसलिए आप सोच सकती हैं कि हम उनसे क्या सीख पाएंगे और अगर वह ऐसे ही करते रहे तो हाउस का समय वेस्ट करने के सिवाए और कफद नहीं होगा। हमारे सामने अभी–अभी चौ. चांद राम जी ने लम्बा चौड़ा भाषण दिया और हाउस को काफी मिसलीड करने की कोशिश की। मुझे तो ऐसा लगा कि कई दिनों से उनको बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपने भाषण में सब कुछ कह दिया।

चौ. चाँद राम: आप तो वकील हैं, यह क्या नकल करने लग एग।

चौ. फूल चन्द: डिप्टी स्पीकर साहिबा उन्होंने वह बातें कहीं, जिनकी कि रैलेवेन्सी कोई नहीं थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वे खुद गद्दी पर विराजमान थे, तो उस वक्त कया इस तरह के लम्बे–चौड़े भाषण किया करते थे। क्रिटिसिजम तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, सब कर सकते हैं लेकिन पोजीशन पर होते हुए सारे मसलों का सम्भालना मायने रखता है।

चौ. चाँद राम: चौधरी साहब, मैं भी तो पार्ट हूं इस देश का, मैं भी अपनी जिम्मेदारी को मानता हूं।

चौ. फूल चन्द: डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे सामने इन 12 मदों पर बहस चल रही है। जो लैंड रैविन्यू की 9 नम्बर की मद है इस पर बोलते हुए बहुत से मैम्बरों ने पटवारियों और महकमा माल को क्रिटिसाईज किया है और कई मैम्बर साहिबान ने तो कहा है कि पटवारी खत्म ही कर देने चाहिए। लेनिक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पटवीर एक ऐसी ऐजंसी है जिसको कि खत्म करना गवारा नहीं किया जा सकता। दूसरी मेन आईटम जो इरीगेशन की मल्टीपरपज प्रौजैक्टस के लिए है उस पर सात करोड़ से भी अधिक का खर्चा है। इसके ऊपर बहुत डिटेल में बहस भी हो चुकी है ओर अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह प्रौजैक्टस जिस मतलब के एिल बनाए गए हैं वह यह है कि जो ब्यास का पानी हमारे हिस्से में आता है वह हमने लेना है और वह हम तभी इस्तेमाल कर सकेंगे अगर हम अपनी चैनल्ज वगैरह तैयार कर लें। अगर डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम उस पानी

को न ले सके तो आने वाली पीढ़ियां इस हाउस के लैजिसलेटर्ज को मुआफ नहीं करेंगी और उस पानी से जिन इलाकों को फायदा होना है वह इस वकत पानी से तरस रहे हैं ओर वे अकालग्रस्त इलाके हैं। इसलिए यह बिल पास होना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस पर दो राय नहीं हो सकतीं। हम सब जानते है कि पंजाब हरियाणा के साथ अच्छा सलूक नहीं करता रहा और उन्हौंने हमेशा हमें पीछे रखने की कोशिश की। लेकिन अब चूंकि हरियाणा बन गया है इसलिए मैं समझता हूं कि सब जिलों की डिवैल्पमैंट एक जैसी की जानी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि और जिलों की डिवैल्पमैंट एक जैसी की जानी चाहिए। इसलिऐ मैं निवेदन करूंगा कि और जिलों की तरह अम्बाला के जिला में नहर तो नहीं आ सकती लेकिन वहां पर पानी की कमी को दूर करने के लिए टयूबवैल लगाए जा सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी–अभी श्री गुलाब सिंह जैन जी ने फिगर्ज बताए थे कि हमाररे हरियाणा में जिस हिसाब से तरक्की हुई है उसकी परसेंटेज 3.2 है और हमें फख्र होता है कि तरक्की की इतनी परसैंटेज सारे भारत में किसी और स्टेट में नहीं है। इस बात की मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं और मैं समझता हूं कि सरकार इसकी मुस्तहिक भी है। इसके इलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा, आऊट आफ दी वे जाकर यहां पर बहस हुई जिस में गरीबी हटाने का और हरिजनों का मसला डिसकम किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि गरीबी हटाने की और हरिजनों की हालत सुधारने की जरूरत है और यह कैसे

हो सकता है इस बात पर विचार करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके दिन में एक भावना होनी चाहिए कि मैं ने ऊपर उठना है। जब तक उनके दिलों में ऐसी भावना नहीं होगी तब तक कुछ बन नहीं सकता और हमारी सरकार की भावना तो उनको ऊपर उठाने की है ही, इसलिए जब दोनों की भावना हो तो मसला आसान हो जाता है और जो कमजोर वर्ग है वह जल्दी ऊपर उठ सकता है। मुझे एक शेर याद आ गयाः—

खुदा ने कभी उस गांव की हालत नहीं बदली

जिसे खुद फिक्र न हो अपनी हालत बदलने का

हमारे देश में और यहां पर भी कई बार राम राज्य की बड़ी चर्चा होती है और कहा जाता है कि राम राज्य में सब लोग खुश थे लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम जो पिछड़े हुए वर्गों के लोग हैं हमें तो उस राम राज्य में भी कुछ नहीं मिला था और मुझे यह कहते हुए फख्र महसूस होता है कि जो चीज हमें राम राज्य में भी नहीं दी गई, वह हमें इस कांग्रेस ने दी जिसके लिए हम इनके आभारी हैं। हमारा अगर किसी ने भला किया है तो वह कांग्रेस है। जहां तक हमारी सरकार का ताल्लुक है इसने काफी मदद देने की चेष्टा की है और बजट में काफी रकमें रखी जाती है लेकिन जहां तक अस्पर्शता का ताल्लुक है उसमें कमी नहीं हुई है। इसको हटाने के लिए कानून तो बने हैं लेकिन उनकी इम्पलीमैंटेशन पूरी

तरह नहीं हुई। इसलिए यह लानत अभी तक चल रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उन कानूनों को पूरी तरह से लागू किया जाए ताकि अनटचेबिलिटी जो है वह दूर हो सके।

अब मैं औगमैंटेशन कैनाल की तरफ आता हूं, चौ. रिजक राम जी फरमाते थे कि वह जमुना की तरफ से आ सकती थी। मैंने उस इलाके को देखा हुआ है। इस बीच की बैकग्राऊंड जो है उसको शायद आनरेबल मैंबर भूल गए हैं। वह सेमजदा इलाका है और पानी का लैवल ऊंचा होने की वजह से वहां पानी ज्यादा हो जाता है और वहां फसलें खराब होती हैं। इसलिए वहां से सेम को कम करने के लिए उसके साथ–साथ औगमैंटेशन टयूबवैल लगाए गए हैं। मैं और ज्यादा न कहता हुआ इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि यह पास होना चाहिए।

चौ. ईश्वर सिंह (पुण्डरी): डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा हो रही है। इसमें जो बड़ी आईटम है वह मल्टीपरपज प्रौजैक्टस इरीगेशन की है। जहां तक इरीगेशन का ताल्लुक है इसमें दो चीजें होती हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी प्रोडक्शन। इसमें मेन झगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का होता है और इसके बारे में आम चर्चा है कि मोघे कम कर दिए गए हैं। इसको देखने के लिए सरकार ने फ्लाइंग स्कवैड भी छोड़े हुए हैं और हैडक्वार्टर से कुछ अफसरों की भी डियूटी लगाई गई है। जहां से भी शिकायत आती है कि मोघे कम कर दिए गए हैं वहां पर वे

जाकर खुद चैक करते हैं और शिकायतों को रफा करते हैं। मगर पहले कुछ ऐसी बात भी थी कि कुछ दे लेकर कुछ लोगों ने जहां पर मोघे खुले बनवाए हुए थे वहां पर अब चैकिंग के डर से जो ओवरसियर थे उन्होंने उनको ठीक कर दिया है। लेकिन इसके साथ–साथ जो हमारा फ्लाईग स्कवैड है उनको यह भी देखना चाहिए कि अगर किसी जगर पर मोघा कम किया गया है तो उसके लिए जो जिम्मेवार आदमी है उसको सजा मिलनी चाहिए। बाज दफा ओवरसियर ऐसा करते हैं कि अपने ढंग से सीमेंट लगाते रहते हैं और कुछ ले देकर उसको फिर ठीक कर देते हैं। जहां तक पानी का सवाल है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक नहर में या माइनर में जब हैड से पानी दाखिल होता है, तो यह बात ठीक है जैसा कि गौड़ साहब ने कहा कि वह पानी कहीं न कहीं तो जाता ही है वापिस तो वह चढ़ नहीं सकता। पहले यह बात थी कि पानी टेल पर कम पहुंचता था लेकिन अब पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। इस सरकार ने पानी के मसले के बारे में जो कदम उठाये हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। सबसे पहली चीज जो खेती के लिये जरूरी है वह पानी है और पानी के बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। हरियाणा में प्रोडक्शन बढ़ी है और यह बात जाहिर करती है कि पानी मिला है और सरकार ने कोई कसर पानी के बारे में नहीं छोड़ी, बिजली देकर, टयूबवैल लगाकर और नहरों से भी पानी दिया है और अब पीन के लिये ही व्यास नदी का पानी सतलुज में डाले जाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। जरूरत अब इस बात की है कि जब वह पानी हमें मिलेगा तो

उस पानी को खेतों तक ले जाने के लिये हम साधन पैदा करें ताकि हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। इसके लिये पैसे की जरूरत है। मैं अर्ज करना चाहता हूं जैसा कि जैन साहब ने भी फरमाया कि हमें सैंट्रल गवर्नमैंट से कहना चाहिये कि वह हमें इस पानी को इस्तेमाल करने के लिये ज्यादा से ज्यादा इमदाद दे और इसके साथ हमें अपने अन्दर से भी साधन सोचने होंगे। यह हमें सोचने होंगे इसमें कोई झिझक की बात नहीं है। यह बात सही है कि जब तक हम इस पानी का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। नहरें पक्की भी की हैं ताकि पानी बचे और आगमैंटेशन कैनाल की बात भी की है। कहने को कहा जाता है कि आगमैंटेशन कैनाल में बहुत जमीन चली गई है। मैं कहना चाहता हं कि अगर हम हिसाब लगायें कि किस गांव की कितनी जमीन गई है तो पता लगता है किसी गांव की 48 किसी की 5. और किसी की 100 किल्ले जमीन गई है इससे ज्यादा नहीं गई है। इसका मुआवजा भी सरकार से ठीक ही दिया है और अगर उस मुआवजा की रकम को सही ढंग से ब्याज पर लगाया जाये तो मैं कह सकता हूं कि एक किल्ले में से सारा खर्च काट कर जितनी आमदनी होगी उससे जयादा एक किल्ले के मुआवजे की रकम का ब्याज आ सकता है। तो मैं अर्ज करता हूं कि नहरों का काम हुआ है, आगमैंटेशन कैनाल का काम हुआ है और इसके साथ–साथ जुई सिवानी, लुहारू कैनालज का काम हुआ है। इसके साथ–साथ महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव जिलो के लिये स्कीमें बनाई जा रही हैं। लिफ्ट स्कीमज के बारे में मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा

काम किया है। ड्रेनज की जो प्रोबल्म थी उसे भी टैकल किया गया है। करनाल जिला में यह ड्रेनें खोदी हैं और वहां जहां पहले पानी खड़ा रहता था पम्पिग सैटस लगा दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि ड्रेन्ज के महकमें ने जो काम किया है उससे लोगों को काफी रिलीफ मिला है। यह दोनों कम्बाइण्ड चीजे हैं कि एक तरफ से फ्लड के पानी को निकाल कर लोगों को रिलीफ देना और दूसरी तरफ उसी पानी को जहां इस की जरूरत है, लोगों को देना यह एक बड़ी सूझबूझ की बात की गई है। सरकार ने बिजली का भी बहुत शानदार काम किया है। हर गांव में बिजली गई है और टयूबवैल लगे हैं। इससे लोगों को एम्पलायमैंट भी मिली है और प्रोडक्शन तो इतनी बढ़ी है कि जिसका कोई अन्दाजा नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ने से जहां लोगों की आमदनी बढ़ी हैं, वहां सरकार को भी आमदनी आई है, सेल्ज टैक्स आया है, मार्किट फी वगैरह आये है। मंडियों में तो यह हाल हुआ है कि अनाज रखने के लिये जगह नहीं रही। यह सारा कुछ बिजली से हुआ है और दूसरी जो स्कीमें पानी की सरकार ने चलाई हैं उनसे हुआ है। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वह इस बात को नहीं देखते कि हरियाणा बनने से पहले पंजाब में जितने आई.पी.एस. रहे वह सभी हरियाणा के रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हरियाणा में पूरी बिजली दी जाये। हिसार से अगर देखा जाये तो हरियाणा को 54 फीसदी बिजली मिलनी चाहिये लेकिन हमें केवल 39 फीसदी हिस्सा मिल रहा है। इसकी वजह यही है कि पहले हरियाणा में बिजली की कंजम्पशन ज्यादा नहीं

की गई और री–आर्गेनाइजेशन के वक्त जितनी कंजम्पशन हमारी थी उसी ढंग से और हिसाब से लेना मान लिया, क्योंकि महा गया जिस हिसाब की कंजम्पशन उस वक्त थी उसी हिसाब से हिस्सा मिलेगा। अगर हम पहले अपना हिस्सा लेते और गांव में बिजली दे दी जाती और अपने पूरे हिस्से को इस्तेमाल में ले आते तो हमें आज 54 फीसदी बिजली मिल सकती थी और हम इतनी क्लेम कर सकते थे। पानी के वजीर भी हमारे ही रहे हैं ओर इसमें भी हमें 32 फीसदी हिस्सा मिल रहा है और पंजाब को 64 फीसदी पानी मिल रहा है। अपना पूरा हिस्सा लड़ कर लेना और उसे क्लेम करना उनका फर्ज था। उस वक्त यह चीज थोड़ी थी, लेकिन अब बिजली और पानी की कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और की भी है। दूसरी स्टेटस भी कोशिश कर रही है और प्रोग्राम बना रही हैं लेकिन उनको हमारे मुकाबले में कास्ट ज्यादा देनी पड़ेगी और उनका खर्च ऐसा करने के लिए हमारे से दुगना और चार गुणा आयेगा क्योंकि वहां उतनी प्रोडक्शन ट्रांसफारमर्ज और मीटर्ज की नहीं होती है जितनी कि जरूरत है और बनाने वाले देखते हैं कि चारों तरफ से डिमांड आ रही और डिमांड ज्यादा है और बनाने वाले देखते हैं कि चारों तरफ से डिमांड आ रही है और डिमांड ज्यादा है और पैदावार कम है, तो कीमतों में बढ़ौतरी कर देते हैं। लेकिन हमने एकदम से क्रैश प्रोग्राम बना कर यह काम कर इसके कास्ट को कम किया है। इस तरह से हमें दूसरों के मुकाबले में बिजली बहुत सस्ती पड़ी है। इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आजकल विजीलैंस डिपार्टमैंट

ने बिजली बोर्ड की चारों तरफ से देखभाल शुरू की है। इन चीजों की जरूरत है और चैकिंग होनी चाहिये। चैकिंग जितनी होगी उतना ही अच्छा होगा इससे एफीशेंसी बढ़ती है। लेकिन इसमें डरने की बात यह है कि कहीं होशियार लोग बच न जायें क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि गरीब आदमी तो पकड़े जाते हैं लेकिन जो तगड़े आदमी हैं वह किसी न किसी तरह से बच जाते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा गड़बड़ और चोरी तो यही लोग करते है, सारा गांव इतनी चोरी नहीं करता, जितनी अकेला एक बड़ा आदमी, बड़ा जमींदर कर लेता है। इसलिये इस बात का ध्यान रखा जाये। इस सरकार ने बिली और नहरों से प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत कोशिश की है और इतना बड़ा काम किया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह से सड़कों की हिसाब है, हजारों साल से यहां पर कई राज आये और कई राज गये लेकिन आज तक कोई ऐसा राज नहीं आया, जिसने हर गांव को पक्की सड़क से मिलाया हो और मिलाने का प्लान बनाया हो। शेर शाह सूरी के बारे में सुनते और पढ़ते हैं कि उसका चार साल राज रहा और चा साल के दौरान वह लड़ाई भी लड़ता रहा और डिवल्पमैंट के काम भी करता रहा, उसके बाद कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसने इस ढंग के प्रौजैक्ट हाथ में लिये हों। इस देश की 55 करोड़ की आबादी है लेकिन सिर्फ इसी प्रदेश की एक करोड़ की आबादी को सारे देश में यह गौरव हासिल है कि चार साल में इतनी तेजी के साथ काम हुआ है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे काम तभी हो सकते हैं जब किसी देश अथवा प्रदेश

को प्रोपर लीडरशिप मिले और वह लीडरशिप ठीक ढंग से स्कीमें बनाये और उनको बना कर ठीक ढंग से एग्जीक्यूट करे। मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि उसने बेमिसाल काम करके हरियाणा का नाम ऊंचा किया है और लोगों को खुशहाल बनाया है। यहां एम्पलायमैंट भी बहुत ज्यादा मिली है और सेचूऐशन प्वांयट तक, सौ फीसदी कभी यह काम नहीं हो सकता है क्योंकि आबादी भी बढ़ती जा रही है और एजुकेशन भी ज्यादा बढ़ती हा रही है। एजुकेशन के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ऐजुकेशन सिस्टम को ओवरहाल करे। एजुकेशन जो है वह थ्यूरी आफ लाइफ का प्रैक्टीकल साईड है। जो कुछ भी हम समझते हैं कि हमने करना है उसे क्रियात्मक ढंग सें करना ही सही ऐजुकेशन है। यह जो हम आर्टस कालिजिज खोलते जा रहे है इनसे तो ऐजुकेटिड अनएमपलायमैंट ही ज्यादा बढ़ती जा रही है इसलिये ऐजुकेशन मैं प्रोपर प्लानिंग की जरूरत है। पहले तो हम अपने नौजवानों के दिल दिमाग और शरीर 14 साल तक इन बेरोजगारी की फैक्टरियों में रख कर नर्म बना देते हैं लेकिन फिर उनको वैसा काम दे नहीं पाते हैं और न ही कोई दे सकता है। वे हिसाब नहीं लगाते कि दुनियां में सिर्फ आइडियलिजम से ही काम नहीं चलता है प्रैक्टीकल बात करने से ही मसले हल होते हैं। इसके लिये जरूरी है कि यह जो सिस्टम आफ ऐजुकेशन है इसे हालात के मुताबिक बदला जाये। जहां तक जमीन का ताल्लुक है वह पूरे प्वांयट तक पहुंच चुकी है और अब आगे जाने की गुंजाईश नहीं है और अब थोड़ी–थोड़ी जमीन लोगों के पास रह गई है और

फिर यह ऐसे पढ़े–लिखे लोग खेती कर भी नहीं सकते हैं। हमें जापान की तरह इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत है हम इंडस्ट्रीज इस ढंग से लगाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। जहां तक बिजली में कट का सवाल है, मैं समझता हूं यह हमारी बैड इकौनौमी है। इसको भी सुधारा जाना चाहिए।

स्कूलों में टीचर्ज की कमी होना बुरी बात है। जब तक टीचर्ज पूरे नहीं होंगे तब तक देहात के गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। हर एक आदमी चाहता हे कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। जितने बड़े–बड़े आदमी हैं, अगर ये अपने आपको उस पोजीशन में रख कर देखें जिस पोजीशन में देहात के बच्चे स्कूलों में तालिम हासिल करते हैं यानी बड़े–बड़े आदमियों के बच्चों की शिक्षा उन स्कूलों में हों जहां टीचर्ज नहीं है तो सही पोजीशन का अपने आप पता चल जाएगा कि देहातों में पढ़ाई की कितनी दिक्कत है। इसलिए स्कूलों में पूरा स्टाफ होना चाहिए, स्कूल अंडर स्टाफ नहीं होने चाहिए। जहां तक स्कूलों में यानी एजूकेशन में कट का सवाल है वहां कट की कोई जरूरत नहीं है। जब तक पूरा स्टाफ नहीं होगा तब तक एजूकेशन का निशाना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि स्टाफ पूरा हो। इन शब्दों के साथ में अपनी स्पीच खत्म करता हूं।

चौ. प्रताप सिंह दौलता (बेरी): मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इनके बारे में माफी चाहता हूं अगर मैं यह कहूं कि

हरियाणा में पिछले चार सालों में जो तरक्की हुई वह 15 सालों में नहीं हुई। कारण साफ है, क्योंकि पहले पंजाब हमारे साथ था। उस वक्त सारे का सारा बजट पंजाब साईड पर खच्र होता था। कभी किसी की गवर्नमैंट रही कभी किसी की। तीन–चार गवर्नमैंटस बनी और थोड़े–थोड़े टाईम के बाद बदलती रहीं। मैं यह नहीं कहता कि फलां गवर्नमैंट तीन चार महीने रही क्योंकि मैं गवर्नमैंटस में डिवीजन नहीं करना चाहता। कहने का मतलब यह है कि कोई स्टेबल गवर्नमैंट नहीं रही।

उपाध्यक्षा: चौ. साहब, आप टाईम का ख्याल रख कर बोलें, क्योंकि मैंने एक दो और मैम्बरों को बोलने का मौका देना है।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मैं कह रा था कि कोई स्टेबल गवर्नमैंट नहीं रही। जो मैम्बर यह कहते हैं कि पिछले चार सालों में बहुत कुछ हुआ, यह कहना ठीक नहीं है। किसी चीफ मिनिस्टर की जाती बुराई हाउस में करना या तारीफ करना बुरी बात है। गवर्नमैंट की पालिसी होती है। पालिसी पर जो कुछ कहना चाहें कहें, सुझाव दें, सुझाव देना सबका फर्ज है। मैं आपनी मारफत सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि एक ऐसा इलाका है जिसमें पिछले चार सालों के कुछ काम नहीं हुआ। इस इलाके को चीफ मिनिस्टर साहब भी जानते हैं, उनको मालूम हैं कि पिछले चार सालों से वहां तरक्की का कोई काम नहीं हुआ। वह बेरी का हल्का है जहां से मैं मेम्बर

बन कर आया हूं। पहले जो आनरेबल मेम्बर इस इलाके को रिप्रेजैंट करते थे उनके बोर में शिकायत यह है कि उन्होंने उस इलाके में यह कह दिया कि यहां जो कुछ हुआ वह उसकी अपनी जेब से हुआ। इस बात को सी.एम. साहब से महसूस किया। रिजल्ट यह हुआ कि बेरी का इलाका डिवैल्प होने से रह गया और शुरू के छः महीनों में जो कुछ हुआ था वही हुआ, उसके बाद जहां रोड़ी पड़ी थी वह वहीं की वहीं पड़ी रह गई, जहां मिट्टी पड़ी थी वह बह गई। कहने का मतलब यह है कि डिवेल्पमैंट बन्द हो गई और बेरी का इलाका वैसे का वैसा ही रह गया। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि इस इलाके पर कुछ न कुछ रूपया खर्च करके इसे डिवैल्प कर दें।

इसके इलावा, दूसरी अर्ज यह है कि खास तौर पर ट्रैजरी बैंचिज के आनरेबल मेम्बर अपोजीशन वालों को कहते हैं कि हमें यह कहना चाहिए, वह कहना चाहिए, उनको इतराज है कि अपोजीशन वो गवर्नमैंट को डाइरैक्ट करते हैं, और यह कहते हैं वह कहते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जो भाई उधर बैठे हैं उनका भी यानी गवर्नमैंट का भी टारगेट होता है, लेकिन अपोजीशन वालों के टारगेट से वे सैटिसफाईड नहीं है। आप हमें लिख कर दे दें कि हम क्या कहें और क्या करें। क्या हम यह कहना शुरू कर दें कि अपोजीशन कोआप्रेट कर रही है? जो कोआप्रेशन हरियाणा में हमने इनको दी है उसकी मिसाल सारे हिन्दुस्तान में नहीं मिलती। जब राज्य सभा का इलैक्शन हुआ था

तो जो कैंडीडेट अपोजीशन की तरफ से खड़ा हुआ था उसकी गत बनाकर हमन बैठा दिया और इनके साथ कोआप्रेट किया। आप बतायें हिन्दुस्तान में कहीं ऐसी मिसाल मिलती है?

चौ. बंसी लाल: चौ. चांद राम जी हंस रहे हैं ..... (हंसी)

चौ. प्रताप सिंह दौलता: हां, सी.एम साहब भी हंस रहे हैं। जहां तक क्रिटिसीजम का ताल्लुक है, मैं पूछता हूं अपोजीशन ने आपका क्या क्रिटिसीजम किया है? अपोजीशन तो अपने ही क्रिटिसीजम में लगी रहती है, आपका क्रिटिसीजम कब किया? (व्यवधान) अगर चौ. हरद्वारी लाल जी बोलने के लिए खड़े हों तो फर्क नहीं पड़ता, बैठे हों तो फर्क नहीं पड़ता। अपोजीशन वाले तो आपका क्रिटिसीजम करते ही नहीं लेकिन हाउस में बार–बार अपोजीशन के बारे में ही चर्चा करते हैं। हरियाणा में अपोजीशन कहां है? अगर अपोजीशन देखनी है तो सह आंध्र प्रदेश में है, जहां नैक्सेलाईटस हैं। वहां पर एक नैक्सेलाईटस लड़की निकलती है ओर अपने बाप का मरडर कर देती है। अपोजीशन आंध्र प्रदेश और बंगाल में है, हरियाणा में नहीं है। जब इलैक्शन होता है तो कुछ आदमी कांग्रेस टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन उन सबकी आइडियालौजी तो एक है। हरियाणा में अगर अपोजीशन है तो वह जनसंघ के दो मैम्बर हैं, इनके सिवाये कोई अपोजीशन नहीं। हम सब डैमोक्रेट है, (व्यवधान)। इनके लिए हर वक्त अपोजीशन को बुरा कहना ठीक नहीं। अरे, हम किसी

दूसरे मुल्क के नहीं हैं और न ही किसी दूसरे तरीके से यहां आते हैं। इसलिए स्पीच करने का यह तरीका बिल्कुल बन्द होना चाहिए। मैं कांग्रेस में 17 साल रहा। इस पार्टी में कुछ कार्ड होल्डर होते हैं, कुछ उम्मीदवार होते हैं। तुम कार्ड होल्डर हो, हम उम्मीदवार हैं लेकिन हैं तो सारे के सारे मैम्बर। जब हम सब मैम्बर है तो स्पीच करने के इस तरीके को बदलना चाहिए।

मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक डिवैल्पमैंट का ताल्लुक है, अगर ये हिसार को डिवैल्प करेंगे तो भी मुझे फायदा है क्योंकि मेरे छोटे भाइयों की बहुएं हिसार की हैं। उनको फायदा होगा। अगर महेन्द्रगढ़ को डिवैल्प करेंगे तो वहां मेरी दो बहने ब्याह रही हैं, उनको फायदा होगा (व्यवधान)

चौ. बंसी लाल: एक आध हिसार में भी ब्याह दो ....(हंसी)।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: जो डिवैल्पमैंट हुई है उससे अब जमीन में पैदावार होने लगी है, वरना हम टोटे में जाया करते थे। डिवैल्पमैंट करने के लिए हिसार डिस्ट्रिक्ट को क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया क्योंकि सियासी क्लैश हैं ये सियासत के बेसिज पर ही डिवीजन करते हैं। डिवीजन कई तरफ है, अमीर गरीबों में डिवीजन करते हैं, शहरी देहातियों में, हिन्दु मुसलमानों में, हिन्दु सिक्खों में। हर एक में कुछ न कुछ लौजिक होता है डिवीजन करने का। लेकिन डिस्ट्रिक्टवाईज डिवीजन करने मे कोई

लौजिक नहीं है। यह डिवीजन अंग्रेजों ने पैदा की थी। जो टटटू पर चढ़ कर तहसील हैडक्वार्टर पर छः छः घंटे में पहुंचा करते थे लेकिन अब तो चौ. भजन लाल जी सुबह यहां से चल कर चाय पीने के वक्त पर वहां पहुंच जाते हैं और वापिस आकर चण्डीगढ़ लंच करते है। (व्यवधान) मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी मारफत सदन से अर्ज करना चाहता हूं कि इस छोटी से स्टेट में ट्रांस्फरज की बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब तो कंसैप्ट आफ टाईम या कंसैप्ट आफ डिसटैंस चेंज हो गया हैं। अंग्रेजों के बाउंटरी खैंची थी उसमें यह खूबी है कि उस बाउंडरी के डिवैल्पमैंट के काम करने में कोई फर्क, कोई रूकावट नहीं पड़ती। डिवैल्पमैंट सब जगह हो सकती है और होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, टाईम थोड़ा है, मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं कि एक मैम्बर साहब ने सदन में एक शेर सुना दिया। यह इंटेलैक्चुअल चीज है। उन्होंने शेयर तो सुना तो सुना दिया लेकिन उस नजम को हैडिंग नहीं बताया कि वह शेर किस नजम का हिस्सा है। मैं उस नजम का नाम बताना चाहता हूं। वह नजम अलामा इकबाल की लिखी हुई नहीं है जो बड़े नैशनलिस्ट थे। यह वह नजम नहीं है तो उन्होंने पढ़ी है, यह तो कुछ और ही है। जो उन्होंने पढ़ा है उसका हैडिंग है ''दरोगे दरवेश'' जिसके मायने होते हैं। ''सन्त की ठगी''। (हंसी) (शोर) इतना कह कर मैं खत्म करता हूं। (हंसी)

चौ. अब्दुर रजाक खाँ (फिरोजपुर झिरका): मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, सदन की बहस में हिस्सा लेते हुए मेम्बर साहिबान के दो नजरिए रहे हैं। एक तो सरकार की तारीफ करने का नजरिया रहा है और कोई मश्वरा और सलाह दिये बगैर बहस में हिस्सा लिया। अपोजीशन के कुछ मैम्बरों में भी अपने ब्यान हाउस के सामने रखे। हमारी बहस को सुनने के लिए हरियाणा के चारों कोनों से लोग आये हुए हैं। हमारी बहस को, हमारे तामीरी बयान के वे देखते हैं। जिस किस्म के बयान हम हाउस में देते हैं उस पर खुद मैम्बरों को शर्म आती है। मुझे इस बात का अफसोस होता है कि मैम्बर साहिबान अपने करदार से पीछे हटकर अपना वक्त जाया करते हैं। इस किस्म के ब्यानाता से न तो सरकार को कोई असर पड़ता है और न खुद मैम्बरान के मन में तसल्ली होती है। मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, बड़े अदब से मैं गुजारिश करूंगा कि जितने स्टेट में काम हुए है, वे कहने को काबिले तारीफ हैं, बहुत हुए हैं, सारे मुल्क में रिकार्ड बीट हुआ है लेकिन जब इस हाउस से बाहर मैम्बर साहिबान, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अपोजीशन के हों बात करते हैं तो यह बात एक नजरिए के मुताबिक एक तय शुदा बात है कि सरकार की तरफ से आवाम को कोई खास भलाई नहीं मिल रही है, आवाम को यह तरक्की पसन्द नहीं है जितनी होनी चाहिए क्योंकि जितनी सड़कें इलाके में तामीर हुई हैं, नीचे के छोटे अफसरान को मर्जी से उनकी प्लानिंग हुई और उसमें आवाम को बिल्कुल नहीं पूछा गया और उनके नक्शे क्योंकि क्रैश प्रोग्राम था, जिस जल्दी में भैजे गए उसी

जल्दी में पास कर दिए। न पानी के बहाव का लिहाज, न गांव को बचाने का लिहाज न ही गांव के सरकुलर रोड़ज का ध्यान रखा गया। उसका नुक्सान यह हुआ कि बारिश शुरू होते ही सारी की सारी सड़कें टूट गई। पुलों का जहां तक ताल्लुक है उनमें गलत किस्म के मैटीरियल लगे। ठेकेदार साहिबान ने, जैसा कि सब दुनिया जानती है भले ही आन दी फलौर आफ दी हाउस कोई न कहे, 50 फीसदी मैटीरियल इधर–उधर खुर्द–बुर्द कर दिया और इसके बारे में जब सरकार के पास कंपलेंटस भेजी गई तो कोई खास इंक्वायरी सामने नहीं आई जिससे और भी नुकसान हुआ। उन सड़कों के सरकार के सामने दुबारा ऐस्टिमेट आये, दुबारा मुरम्मत के नाम से बड़ी–बड़ी रकमें खर्च हुई जिससे सरकार को नुक्सान हुआ और जिसका एक दो महीने पहले फाईनैन्शल क्राइसिंज नाम रखा गया। हमारे छोटे मुलाजिमों की खुदपरस्ती की भावना और आवाम को नजरअन्दाज करके रख देने की भावना की बिना पर यह हुआ। इसके बारे में हमारे कई मैम्बर साहिबान जब–जब फुरसत हुई अपने मुताल्लका मिनिस्टर साहब, जो कि आज इतफाक से हाउस में नहीं है, से मिले और उनसे ये बातें कहीं लेकिन उन्होंने हर मैम्बर साहब को जो–जो उन्हें सलाह देने गए एक बात के सिवाय कि हां–हां हम देख रहे हैं कोई दूसरी गारंटी नहीं दी। तो मैं अर्ज करूंगा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि सरकार इस बारे में अपनी एक स्कवैड कायम करे जो यह देखे कि पिछली सड़कें जो तामीर हुई हैं उन पर कितना रूपया खर्च हुआ, जो सड़कें पहली बार टूट गई उनकी वजह मालूम करें कि क्यों

टूटीं और जो पुल गलत मैटीरियल लगने से सारे ब्रीच हो गए उनके लिए ऐसी खुली इंक्वायरी कराई जाए और जो तामीर करने वाले ठेकेदार हैं, वहां के आफिसर्ज हैं, वहां के एम.डी.ओज. हैं, वहां के एक्स.ई.एन्ज. हैं, जिन पर सरकार भरोसा करती है, जिनके भरोसे के ऊपर सरकार हरियाणा के खजाने को दुबारा से खर्च करती है उनकी जवाबतलबी की जाए, उन पर पैनल्टी लगाई जाए, उनकी सर्विसिज खत्म की जाएं और उनके खिलाफ खुली इंक्वायरी की जाए। (घंटी) अभी तो मोहतरिमा दो ही मिनट हुए हैं।

उपाध्यक्षा: कितने मिनट और चाहिएं।

चौ. अब्दुर रजाक खां: 15–20 मिनट तो होने ही चाहिए।

उपाध्यक्ष: मैं तो सब को पांच–पांच मिनट दे रही हूं क्योंकि इसे पास भी करना है।

चौ. अब्दुर रजाक खां: दो चार बातें और कह लेता हूं, कृपया दो मिनट और दे दीजिए।

उपाध्यक्षा: इस तरह से बहुत से मैम्बरों को टाईम नहीं मिलेगा।

चौ. अब्दुर रजाक खां: मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाता

हूं कि जो खजाना, हरियाणा की जनता का रूपया, खर्च हो रहा है उसकी देखभाल जरूर हो। अगर देखभाल नहीं होती तो आवाम जो हैं वह सरकार को बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। उसका फायदा सरकार को नहीं होता। इसलिए जो पैसा सड़कों पर ....

Deputy Speaker: No repetition please.

चौ. अब्दुर रजाक खां: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसी तरह महकमा आबपाशी में जो काम हुए उनमें भी छोटे मुलाजिमों ने अपनी मर्जी से खर्च कर दिया। बगैर प्लानिंग के बांध तामीर हुए। राओली बांध जिसकी सरकार ने फिल्म भी बनाई और न सिर्फ हरियाणा के आवाम को बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लोगों को दिखाई, उससे वहां जो फसल सावनी की हो जाती थी लोग उससे महरूम हो गए और रबी की फसल के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसक सपिल–वे जो बने हैं वे गिरने लग गए हैं। जिन भाईयों को शक हो वे जाकर देख लें। 14 सपिल–वेज में से दो सपिल–वेज के दरवाजों के पत्थर गिरने लग गए हैं। पहली बारिश में ही वे सपिले–वे फेल हो गए और उनमें ब्रीच आ गया। इस तरह सरकार तवज्जह दे। अगर सरकार इन चीजों की तरफ तवज्जह देगी तभी लोगों के लिए कोई पायदार काम होगा, वरना नहीं। आयंदा शायद उनकी रिपेयर के लिए कोई बजट आए इसलिए मैं सरकार से इतना अर्ज करना चाहता था कि जो काम हो रहे हैं उनके ऊपर सरकार को आंख मूंद कर भरोसा नहीं

करना चाहिये। सरकारी मुलाजिम हमेशा एक डर से और भय से अच्छा काम किया करते हैं। उन्हें यह पता लगना चाहिए कि सरकार बुरा काम करने पर ऐक्शन भी ले सकती है। पिछले दो–तीन साल के अर्से में किसी मुलाजिम को किसी जगह पर जाकर चैक नहीं किया गया इसलिए उन्हें पता है कि हमारी रिपोर्ट फाईनल होगी, सरकार एतबार करती है, अंधा–धुध खर्च कर लो।

कामेड़ा बांध का आज यह हाल है। उसके बाहर एक बलाकपुर गांव है। उस गांव के चारों और रिंग बांध नहीं है जिसकी वजह से डैम के अन्दर तो पानी नहीं लेकन बाहर गांव पानी में डूब हुआ है। ये डी.सी. साहिब से पूछताछ कर लें, हमने भी यह बात यहां कह दी। सी.एम. साहब को भी मैंने यह बात बताई थी। ऐसी गलत प्लानिंग, जिसकी वजह से बांध मे ंतो पानी नहीं, लेकिन बाहर गांव पानी में डूबा हुआ है, के लिए यह सरकार जिम्मेदार है।

उजीना ड्रेन का कोटला लेक से लिंक है। इसके आगे राजस्थान बार्डर पर खलूका रैगुलेटर है। वह जब राजस्थान वालों ने बन्द कर दिया तो इनकी उजीना ड्रेन चलती रही जबकि इनको उजीना रैगुलेटर को बन्द कर देना चाहिए था। इससे वहां के इलाके में फलड आ गया। इन बातों पर भी सरकार को निगाह रखनी चाहिए।

चौ. बंसी लाल: मुलाजिम तो यही रहेंगे, वे पाकिस्तान से नहीं आने हैं।

चौ. अब्दुर रजाक खां: वह तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। (विघ्न)

चौ. बंसी लाल: वे जिम्मेदारी से काम करते हैं लेकिन किसी गैर–जिम्मेदार आदमी के कहने पर काम नहीं करते।

चौ. अब्दुर रजाक खां: डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जिम्मेदारी और रिकार्ड की बात है। यह बुरी नहीं लगती चाहिए। इसमें दर्द होने वाली बात नहीं होनी चाहिए।

आगरा कैनाल, जिसका बहाव हमारे हरियाणा के पलवल, हथीन और पुनहाने की तरफ है उससे एक बीधा जमीन को भी पानी नहीं मिलता जबकि लोगौं से आबियाना लिया जाता है। हमने पहले भी सरकार से प्रार्थना की थी यू.पी. वालों को उसका मुआवजा देकर ले लिया जाए। बगैर पानी दिये लोगों से आबयाना लेना न्याय की बात नहीं है।

यू.पी. सरकार यू.पी. बोर्डर पर बिछोर गांव के पास एक बांध लगाया है। उस पानी का हरियाणा की तरफ नेचुरल बहाव है लेकिन उसको उन्होंने रोक लिया है। उसके बारे में भी कोई खास प्रबन्ध नहीं किया गया।

चौ. बंसी लाल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं? ऐप्रोप्रिएशन बिल में कहां इन बातों का रैफरेन्स है? इनकी सारी स्पीच ही इर–रैलेवेन्ट है।

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब, आप ऐप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर नहीं बोल रहे हैं। आपको उन्हीं डिमांडज से ऊपर बोलना चाहिए जो डिमांडज यहां आई हैं।

चौ. अब्दुर रजाक खां: मल्टिपरपज प्रौजैक्ट के लिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमे पेसा डिमांड किया है। उससे ही यह बात ताल्लुक रखती है। (विघ्न)

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री अध्यक्ष: चौ. साहब, आप वाइंड अप कीजिए, बहुत समय हो गया है। एक मिनट से ज्यदा समय अब आपको नहीं मिल सकता।

चौ. अब्दुर रजाक खां: अगर आप नहीं बोलने देते तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री ओम प्रकाश गर्ग (थानेसर): स्पीकर साहब, डिमांडज और ऐप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर मेरे साथियों ने विचार रखे। अपोजीशन के लीडर, चौ. हरद्वारी लाल और बहुत से दूसरे साथियों ने भी अपने विचार रखते हुए फरमाया कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर हम नुक्ताचीनी कर सकें। कुछेक मेरे दोस्तों

ने एक ही नुक्ताचीनी की कि काम तो ठीक है लेकिन जल्दी में कर दिया। स्पीकर साहब, सिर्फ एक ही डर है इन भाईयों को कि यह इमदाद, सड़कों का पहुंचना, बिजली का पहुंचना, जो सहूलियात इन्होंने सदियों में देनी थीं या पिछले 25 साल ने नहीं दे सके वे चार साल में क्यों चली गई।

स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि हरियाणा में गांव–गांव में बिजली चले जाने के बाद हरियाणा का दूसरे इलाकों में जो मान बढ़ा है वह बयान नहीं किया जा सकता। केवल मान ही नहीं बढ़ा बल्कि बहुत फायदा भी हुआ है। बिजली के आने से हरियाणा में कितनी इंडस्ट्री लगी हैं यह किसी से भूली हुई बात नहीं है। गांव–गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े उत्साह के साथ और दिलचस्पी के साथ कदम उठाया है।

जो मेरै भाई यहां हाउस में यह तकरीर करते हैं कि करनाल में जो कैनाल बनायी जा रही है, यह नहीं बननी चाहिए थी। यह ठीक नहीं है। हाउस में तो ये ऐसी तकरीर करते हैं कि नहीं बननी चाहिए थी परन्तु रोहतक में जाकर यह कहते हैं कि रोहतक जिले को पानी नहीं मिल रहा है, कोई नहर नहीं बनायी जा रही है। दरअसल अपोजीशन के भाई कुछ और ही ढंग से सोचने हैं। उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। वे सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि गवर्नमैंट राज करने के काबिल नहीं है लेकिन हम यहां हाउस में ही देख रहे हैं कि एक लीडर आफ दी अपोजीशन

की सीट के लिए ही झगड़ा कर रहे हैं। एक कहता है यह क्यों बने? और दूसरे कहते हैं कि अगर ज्यादा अपोजीशन चौ. हरद्वारी लाल जी के साथ है तो उनको बने रहने देना चाहिए। अगर इनको बना रहने दें तो इनमें बुराई क्या है? इन भाइयों को गवर्नमैंट चलाने का मौका मिल जाये तो इनका लीडर पर ही झगड़ा होता रहेगा। अपने प्रान्त का ये क्या भला कर सकेंगे? हमें तो अफसोस है कि इतनी बड़ी तादाद में अपोजीशन कामयाब हो कर आयी थी, उनको यहां हाउस में बड़ा हैल्दी क्रिटिसिजम करना चाहिए। इस तरह के क्रिटिसिज्म से हरियाणा की जनता का लाभ नहीं हो सकता। लीडर आफ दी अपोजीशन पर इस तरह से कीचड़ उछालने से जनता का लाभ नहीं होगा। इधर बीच में दौलता साहब भी फंस गये (हंसी)।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: मैं दोनों को देख कर जलता हूं। (हंसी)

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब एक आनरेबल मैम्बर ने यहां पर कहा कि हरिजनों के लिए कुछ नहीं हुआ। छोटे–छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया गया है। जिस वक्त वे कुर्सी पर थे उसवक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको यह पता होना चाहिए कि हमारी सरकार कितने लोगों को धंधा देने की कोशिश कर रही है। आज केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट भी इसी फिक्र में है कि छोटे वर्ग के जो भाई दबे हुए हैं उनको कैसे उठाया जाये। सोचने की बात तो यह है कि उनको 8–9 महीने

तक हकूमत करने का मौका मिला लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सन् 1967 के इलैक्शन में जब हम गांवों में घूमा करते थे तो हमने गरीब हरिजनों को छोटी–छोटी किनकी के चावलों को पीसने हुए देखा है। इसलिए उन छोटे वर्ग के गरीब भाइयों के प्रति इनको उस समय हमदर्दी नहीं हुई, आज वे हमदर्दी दिखा रहे हैं। स्पीकर साहब आप देखें कि इन चार सालों में पहले की बजाए अब कितनी ज्यादा इन्डस्ट्रीज बढ़ रही है। इन्डस्ट्रीज के लग जाने से उन गरीब आदमियों को रोजगार मिलने लगेगा। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो पैसे की कमी के कारण अपनी इन्डस्ट्री, कायम नहीं कर सकते थे लेकिन हमारी सरकार ने एक फाइनेन्शल कारपोरेशल बनायी है उससे छोटे आदमियों को कर्जा दिया जाता है जिससे वे इन्डस्ट्री लगा सकें। फाइनेन्शल फारपोरेशन ने हरियाणा में इन्डस्ट्री लगवाने में बड़ा भारी हिस्सा लिया है। तो स्पीकर साहब इन भाइयों को यह दर्द है कि यह काम इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं। मेरे दोस्तों को किसी तरह की फिक्र नहीं करनी चाहिए उनको कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, उनको तो हमेशा के लिए साफ कर दिया गया है। अब आपको इस बारे में कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

जहां तक डिवल्पमैंट की बात है, उस बारे में मैं अर्ज कर दूं। हरियाणा में कितने स्कूल पहले थे और अब कितने ही नये खोल दिये गये हैं? कितने ही स्कूलों को सरकार ने अपग्रेड कर दिया है। यह मैं मानता हूं कि स्कूलों में टीचर्ज की कमी है,

वह जरूरत पूरी होनी चाहिए। टीचर्ज के न होने से तालीम में कुछ गड़बड़ है। दूसरे मैं बिजली के बारे में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कल जब बिजली की रिपोर्ट पर डिस्कशन होगा उस समय बिजली के बारे में कह लेना।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब, आपकी एडवाइस भी ठीक है और मैं मान लेना हूं। स्पीकर साहब हरियाणा की काफी तरक्की हुई है। मैं विरोधी दल के भाईयों से यही अर्ज करना चाहता हूं कि आप गवर्नमैंट को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने आपको भी देख लें। आप पहले अपनार फैसला करें। आपकी बातें सुनकर हमें शर्म आती है। (हंसी) मैं तो यही कहूंगा कि विरोधी दल के भाई आपस में मिल कर रहें, इकट्ठे हो जायें। अगर कोई क्रिटिसिज्म करें तो हैल्दी क्रिटिसिज्म करें जिससे हरियाणा की जनता का भला हो।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): स्पीकर साहब आज सवेरे से एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हो रही है। सदन में माननीय सदस्यगण ने कुछ बातें कहीं हैं उसमें जो ठीक बातें कहीं गयीं हैं उन पर सरकार पूरी तौर से गौर करेगी और जितनी बातें जायज होंगी उन बातों पर गौर करने के बाद सरकार अगर किसी जगह पर कोई कमी पायेगी तो उस कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करेगी।

चौ. चांद राम जी ने आगमैंन्टेशन कैनाल के बारे में बहुत कुछ कहा, मगर उनको यह पता नहीं था कि आगमैंन्टेशन कैनाल क्या है और क्यों आगमेंन्टेशन कैनाल बनी? दूसरी कैनाल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। स्पीकर साहब आप जानते हैं कि चौ. चांद राम जी से आज तक साढ़े चार साल में अच्छी बात मैंने इस सदन में नहीं सुनी। आगमेन्टेशन कैनाल जो हमने बनायी है, इसके बनने के बाद मौजूदा कैनाल में जो सीपेज है वह खत्म हो जायेगी और जिस इलाके में आगमैंटेशन कैनाल बन रही है उस इलाके की जो वार–लौगिंग प्रौबलम है वह भी दूसर हो जायेगी और उसके साथ–साथ जो डीप टयूबवैलज लगायेंगे उनसे बहुत मिकदार में पीन अवेलेवल होगा। हमने उस नहर का नाम भी आगमैंटेशन कैनाल रखा है। उसमें कम से कम हजार या दो हजार क्यूसिक पानी टयूबवैल्ज से लेकर डाल सकेंगे और वैस्ट्रन जमना कैनाल को स्ट्रैन्थन कर सकेंगे।

जहां तक जमीन का सवाल है, उसके बारे में यहां कहा गया है कि गरीब आदमियों की जमीन में से यह नहर निकाली गयी है। स्पीकर साहब जैसा कि चौ. चांद राम जी ने सुझाव दिया उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर हम उस जगह से नहर नहीं निकालते तो और कितने ज्यादा गरीब आदमियों की जमीन हमें लेनी पड़ती। आज हमने जो साढ़े ग्यारह सौ एकड़ जमीन एक्वायर की है, अगर उधर से इस नहर को निकालते तो हमें चार–पांच हजार एकड़ और जमीन एक्वायर करनी पड़ती। इसमें

ज्यादा जमीन हमें शामलात की मिल गयी, कुछ वाटर लौंगड मिल गयी और उसमें से आराम से नहर निकल गयी है। अगर चौ. चांद राम जी ने नुक्लाचीनी की नजर से कहा है तो ठीक है। उनकी नौलेज ही इतनी थी कि उनको इस बात का पता ही नहीं था इसलिए उनकी नौलेज पर मुझे रहम आता है।

स्पीकर साहब स्कूलों के बारे में यहां कहा गया कि स्कूलों में स्टाफ कम हैं, मैं मानता हूं किसी–किसी जगह कम है, सब जगह कम हो ऐसी बात नहीं है। जहां–जहां स्टाफ कम है सरकार जल्दी से जल्दी वहां स्टाफ पूरा लगाने की कोशिश करेगी। एक सदस्य, चौ. अब्दुल रजाक खां, अभी सदन में बड़ी जोशीली तकरीर कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कहीं देहात के लोगों को भड़काने के लिए तकरीर कर रहे हों। उन्होंने अफसरों को बड़ा क्रिटिसाईज किया। अफसरों के बारे में उन्होंने कहा कि तकरीबन 25 साल से उन पर कोई चैक नहीं है। चौ. अब्दुल रजाक खां को यह पता नहीं है कि इन पिछले चार सालों में मेवात में जितना रूपया खर्च हुआ है, उतना इन चार सालों से पहले के 200 सालों में भी खर्च नहीं हुआ होगा। इन्जीनियर का काम इंजीनियर ही जान सकता है, चौ. अब्दुल रजाक खां नहीं। अलबत्ता, चौ. अब्दुल रजाक कई बार अफसरों पर नाजायज रोब गांठने की कोशिश करते रहे हैं। हरियाणा सरकार का कोई भी अफसर, उनके नाजायज रोब से नहीं दबेगा। जो जायज काम होगा, वही करेगा। अगर वह यह सोचते हैं कि असैम्बली में

तकरीर करने से, अफसर दब जायेंगे तो मैं उन्हें यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार का कोई अफसर उनके इस रोब से नहीं दबेगा, सिर्फ–जायदा काम करेगा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर अच्छा मैटीरियल नहीं लगा। यह बात बिल्कुल बे–बुनियाद और हाउस को मिस–लीड करने के लिये कही गयी है। अगर मैं इस बारे में यह कहूं कि यह बात सौ–फीसदी गलत है। तो बिल्कुल सही बात होगी। यह बिल्कुल बे–बुनियाद और हाउस को मिस–लीड करने के लिये कही गयी है। अगर मैं इस बारे में यह कहूं कि यह बात सौ–फीसदी गलत है। तो बिल्कुल सही बात होगी। यह बिल्कुल गलत बात है। बड़ा अच्छा मैटीरियल लगा है और मेवात के इलाके में भी बड़ी अच्छी सड़क बनी है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये, सदन को यह बताना चाहता हूं कि चौ. अब्दुल रजाक को सड़कें चुभती हैं। क्यों चुभती है? इस बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने आज तक, पिछले सवा–चार सालों में, यह नहीं देखा कि चौ. अब्दुल रजाक किसी शरीफ आदमी की सिफारिश लेकर आये हों। एक बार मेवात के एक गांव में मैं चला गया। वहां 20 मील लम्बी सड़क बनी थी। वहां पर सबसे पहली शिकायत गांव वालों ने मुझसे यह कि की तुमने यहां सड़क क्यों बना दी? मैंने कहा कि तुम्हारे फायदे के लिये किया है। सड़क बनने से तुम्हारे लिये बसें चलेगी, सड़क से तुम शहर में जा सकते हो, आ सकते हो, सौदा बेचने के लिये शहर में जा सकते हो, सौदा लेने के लिये शहर में जा सकते हो, तो एक आदमी ने सामने से, खड़े होकर कहा कि बात यूं है कि

सड़क बनने से पहले, दो–दो साल तक यहां पुलिस आती नहीं थी अब रोज यहां पुलिस खड़ी रहती है। एक दूसरे आदमी ने कहा कि ढोर चुराते हैं, ढोर चुरोन की टाल कर दें तो पुलिस नहीं आयेगी। चौ. अब्दुल रजाक खां दूसरी किस्म के आदमियों के सिफारिशी होते हैं। इनको सड़के, इन नुक्ते–निगाह से चुभती हैं। इसलिये नहीं कि उनमें मैटिरियल कम लगा है। फिर इन्होंने काह कि जो रावली बांध बनाया गया और कामेड़ा बांध बनाया गया, यह गल्त ढंग के मैटीरियल से बनाया गया, इस बारे में मेरा कहना यह है कि यह बहुत शानदार पायेदार और बहुत अच्छे बांध बनाये गये हैं और एक रिकार्ड टाईम के अन्दर हमने तैयार किये हैं। आगे को भी जिस तरह से हमारे इंजीनियर कहेंगे, उसी तरह से बांध बनायेंगे। जिस तरह से चौ. अब्दुल रजाक खां चाहते हैं उस तरह से बांध नहीं बनायेंगे। कोई एक गरीब गांव है जिसने चौ. अब्दुल रजाक की मुखालिफत की है। ये चाहते हैं कि उसको डुबोने के लिये गांव पर पानी का एक बांध लगा दें। लेकिन सराकर ऐसा नहीं करेंगी। सरकार वह काम करेगी, जिससे मेवात के लोगों का फायदा हो। सरकार ने पहले भी वह काम किये हैं, जिससे मेवात के लोगों को फायदा हुआ है। आज मेवात के लोग इस बात की दाद देते हैं कि जितना काम इस सरकार ने उनके लिये किया है, उतना काम किसी और सरकार ने नहीं किया है। इनके कहने से सरकार का कोई फैसला नहीं बदलेगा। सरकार का कोई भी अफसर, इन के कहने से रोब में आकर, गल्त काम नहीं

करेगा, सिर्फ जायज काम करेगा और ऐसे गल्त काम हम नहीं करेंगे जो चौ. अब्दुल रजाक खां चाहते हैं।

चौ. चाँद राम: शायद उस इलाके ने बदला न दिया हो।

चौ. बंसी लाल: शादय ऐसे ही शुभचिन्तक लोग हैं, जैसे किसी के अहसान का बदला देने वाले यहां बैठे हैं। स्पीकर साहब, सबकी सब सड़कें, अंच्छे स्टैन्डर्ड की बनी हैं और किसी भी सड़क में किसी किसम की कमी नहीं है। अगर बाढ़ आये तो सड़क को तो जिक्र ही क्या है, महल के महल बह जाते हैं। पानी के सामने कोई चीज नहीं ठहरती। इन्हौंने पुलों की चर्चा की कि गल्त सीमेंट लगा, जैसे वही इंजीनियर हों, और जो हमारे इंजीनियर हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है। जैसे वही इंजीनियरिंग के मास्टर हैं और डिग्री लेकर आये हुए हैं और हमारे इंजीनियर कुछ जानते ही नहीं। आज इस किस्म की बे–बुनियाद बातें चौ. अब्दुल रजाक की तरफ से कही गयीं हैं। उन्होंने कहा कि एलाइनमैंट भी अपने ढंग से की जाती है। यह बात ठीक है। एलाइनमैंट वहीं से होगी जहां से ठीक होगी। एलाइनमैंट चौधरी अब्दुल रजाक खां के कहने से और उन गांव वालों से बदला लेने के लिये उनकी जमीन में से नहीं निकाली जायेगी। एलाइनमैंट वहीं पर होगी जहां पर गवर्नमैंट ठीक समझती है। एलाइनमैंट वहीं पर होगी, जहां से सड़क का निकलना ठीक है, इसके कहने से तबदील नहीं होगी और किसी भी हालत में तबदील नहीं होगी।

स्पीकर साहब, सीमेंट के बारे में इन्होंने बहुत बातें कहीं। इन्होंने कहा सीमेंट कम लगा, मैटीरियल अच्छा नहीं लगा, मैं इस बारे में पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि वह तो यह समझते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई इंजीनियर ही न हो। उन्होंने साथ ही यह भी कह दिया कि गवर्नमैंट इसकी जनरल इनक्वायरी कराये। स्पीकर साहब, अगर मैं जनरल इंक्वायरी कराऊं तो कहीं ऐसा न हो कि चौ. अब्दुल रजाक खां में आफिसरों में ज्याद खोट मिल जाये। मैं एक–एक आदमी को अच्छी तरह से जानता हूं और एक–एक इलाके के हालात को अच्छी तरह से समझता हूं। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि कौन कितने पानी में है और कौन क्यों बोलता है? किसी भी भाषा किस ढंग से क्यों निकलती है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा कहने का मकसद यह है कि जितनी भी ऐसी बातें चौ. अब्दुल रजाक खां ने कहीं, वे सब बे–बुनियाद हैं और सिर्फ अफसरों के ऊपर रोब गांठने के लिये कहीं हैं। मगर हरियाणा सराकर के अफसर के रोब में अपने वाले नहीं हैं। स्पीकर साहब, इसके अलावा, अगर किन्ही आनरेबल मैम्बर्ज ने अपनी स्पीच के अन्दर सुझाव दिये हैं तो सरकार उन सुझावों के ऊपर गौर करेगी और उसमें से जो अच्छे सुझाव होंगे, सरकार उनको मानेगी। जो बात जनसाधारण के हक की होगी, उसे करने के लिये हमारी सरकार हर वक्त तैयार होगी। स्पीकर साहब, इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं। दौलता साहब ने एक बात कही कि बेरी के हल्के में पहले बहुत काम हुआ, लेकिन फिर रूक गया। उनको यह गलतफहमी है, ऐसी बात

नहीं है। बेरी के हल्के में किसी भी दूसरे हल्के से कम काम नहीं हुआ है। अलबता यह हो सकता है कि दौलता साहब यह चाहते हों कि वह इलाका बहुत ही आईडियल बन जाये। हो सकता है वह इलाका अभी आईडियल न बन पाया हो। हम कोशिश करेंगे कि दौलता साहब की इस बात को मानें और उस इलाके को एक आईडियल इलाका बनाए। जब महेन्द्रगढ़ के इलाके के लिये 'जवाहर लाल नेहरू कैनाल' निकलेगी तो सबसे पहले उसका पानी, झज्जर तहसील को मिलेगा और फिर नाहड़ सब–तहसील को मिलेगा। अगले साल से ही हमारा इरादा है कि झज्जर तहसील को पीन दे दें। सिर्फ झज्जर तहसील को ही नहीं बल्कि महेन्द्रगढ़ और नाहड़ में भी इस नहर से पानी देने का हम इरादा रखते हैं। आगे तो जैसे हालात होंगे, वैसा सामने आ जायेगा। लेकिन हमारे इरादे नेक हैं और हमारे काम करने के इरादे हैं। यहां पर गल्त किस्म की नुक्लाचीनी करने से कोई बात नहीं बनती और न ही गल्त किस्म की नुक्ताचीनी करने से सरकार अपना रास्ता छोड़ सकती है।

इन शब्दों के साथ, मैं आपके जरिये सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि वह एप्रोप्रिएशन बिल को पास कर दें।

चौधरी अब्दुर रजाक खां द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

चौ. अब्दुर रजाक खां: आन एपर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर।

श्री अध्यक्ष: पर्सनल एक्सप्लेनेशन की क्या बात है, जो आप कहना चाहते हैं?

चौ. अब्दुल रजाक खां: स्पीकर साहब, मुझ पर इल्जाम लगाये गये हैं, मुझे उनका जवाब देना है। चौधरी साहब को गल्तफहमी है। मैं कोई गल्त काम करने वाला नहीं हूं। न मैं खुद गल्त काम करता हूं और न किसी दूसरे को गल्त काम करते हुए देखकर राजी होता हूं। मेरी जब भी इनसे मिल कर कोई गुजारिश हुई या किसी अफसर से बात हुई तो मेरी गुजारिश यही थी कि अवाम के साथ मिलकर काम करें, इसी में उनका भला है। जैसे चौ. साहब ने कहा, इस तरह से मनघड़न्त बात कर देना कि मैं क्या करता हूं, अच्छी बात नहीं है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने मेरे बारे में कहा है न मैंने कभी गलत काम करवाया है और न ही गलत काम के लिये किसी को कहा है। ..... (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं यह समझता हूं कि सबसे पहले स्पिल–वे डिस्कस हुई है। चौधरी साहब, वहां जाकर कभी देख लें, पता लग जायेगा ..... (व्यवधान)

चौ. बंसी लाल: मैंने कई बार देखा है, रात को दो–दो बजे भी देखाहै मैं इनको बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, आज कोई नई बात नहीं है। ..... (व्यवधान)

चौ. अब्दुर रजाक खां: समझने की क्या बात है, मुझे जनता का वर्डिक्ट हासिल हुआ है, इसलिये मैं यहां आया हूं, ऐसे ही नहीं आया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 3) (हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर क्लास–बाई–क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि क्लाज–2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि क्लाज–3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि क्लाज–1 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि शीर्षक विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill (हरियाणा विनियोग) (सं. 3) विधेयक be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 3) (हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 3) (हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्सेशन आफ सेल्ज)

हरियाणा अमेण्डमैंट बिल, 1972

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana

Amendment Bill, 1972. (पंजाब मोटर स्पिरिट (बिक्री पर कर) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1972)

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Bill. (पंजाब मोटर स्पिरिट (बिक्री पर कर) हरियाणा संशोधन विधेयक be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्सेशन आफ सेल्ज) हरियाणा अमैण्डमेंट बिल, (पंजाब मोटर स्पिरिट (बिक्री पर कर) हरियाणा संधोधन विधेयक) पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर क्लास–बाई–क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि क्लाज–2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि क्लाज–1 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि शीर्षक विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move-

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Bill, (पंजाब मोटर स्पिरिट (बिक्री पर कर) हरियाणा संशोधन विधेयक) be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्सेशन आफ सेल्ज) हरियाणा अमैण्डमेंट बिल, (पंजाब मोटर स्पिरिट (बिक्री पर कर) हरियाणा संधोधन विधेयक) पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

कि पंजाब मोटर स्पिरिट (टैक्सेशन आफ सेल्ज) हरियाणा अमैण्डमेंट बिल, (पंजाब मोटर स्पिरिट (बिक्री पर कर) हरियाणा संधोधन विधेयक) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

हरियाणा वित निगम के 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे पर चर्चा

Ch. Shiv Ram Verma (Nilokhri): Sir, I beg to move-

That the Annual Report and Accounts of the Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March, 1972, which was laid on the Table of the House on the 16th August, 1972, be discussed.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्शल कारपोरेशन की रिपोर्ट, जो इस सदन में प्रस्तुत हुई है, उसके सिलसिले में चर्चा के बारे में थोड़े से समय के अन्दर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। वैसे तो इसमें कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती जिसको कि ज्यादा चर्चा का विषय बनाया जाए परन्तु फिर भी इसके अन्दर कुछ बातें

ऐसी दिखाई देती हैं जिसकी ओर, मैं, आप की मारफत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो कर्जा लेने का तरीका, प्रोसीजन है, वह कुछ बड़ा कम्पलीकेटिड सा है। जब कोई कर्जा लेता है तो उसकी शर्तें पूरी करने में दिक्कतें पेश आती हैं और वैसे छोटी–छोटी दिक्कतें तो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को बहुत होती हैं, बड़ी–बड़ी इन्डस्ट्रीज को इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं, उनके यहां तो बड़े–बड़े अफसर होते हैं। लेकिन छोटी इन्डस्ट्रीज को कई बार मुश्किलें आती हैं और इसमें अगर सुधार न किया जाए तो इससे फाइनैंशल कारपोरेशन से जो लाभ पहुंचना है, वह छोटी इन्डस्ट्रीज को नहीं पहुंच पाता। इसके द्वारा मैं समझता हूं कि 71–72 में कोई 124 केसिज नये फाइनैन्इज हुए हैं और स्टाफ के केवल वेतन पर लगभग साढ़े तीन लाख रूपया का खर्चा हुआ है। इतना भारी खर्चा करने के बाद सिर्फ 124 केसिज फाइनेलाइज हुए हैं, यह कोई सास्ता सौदा नहीं है महंगा सौदा है। स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए और उसमें सुधार करने का प्रयत्न किया जाए ताकि आगे भी तेजी से काम चल सके। इसके इलावा, स्पीकर साहब, पेज 15 के ऊपर जो जिलेवार एक डिटेल दी गई है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि कैसे उसके अन्दर बड़ा भेदभाव दिखाया गया है। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिये अम्बाला जिले को, 8 युनिटों के लिये कोई लगभग 1184000 रूपया कर्जा दिया गया है। गुड़गांव में 40 युनिटों के लिये एक करोड़ 18 लाख 68 हजार रूपया दिया गया

है। यह मैं समझता हूं कि शायद इसमें फरीदाबाद के कारण ज्यादा रूपया दिया गया है। हिसार में 21 युनिटों का कोई 3965500 रूपया दिया गया है। जीन्द में 6 युनिटों के लिये लगभग 1085000 रूपया, करनाल को 13 युनिटों के लिये 1671000 रूपया दिया गया है। महेन्द्रगढ़ में 5 युनिटों के लिये 265000 रूपया दिया गया है। रोहतक में 19 युनिटों को 3340000 रूपया मिला है तो इस तरह से जिलों के आंकड़ों में इतना भेदभाव है, अन्तर है। इससे ऐसा जाहिर होता है कि सरकार का इन्डस्ट्रीज को एक ही जगह पर इकट्ठा करने का ध्यान रहता है। अगर सभी जिलों में हिस्से सह सहायता मिलती तो दूसरे जिलों में भी उद्योग बढ़ सकते थे, जिससे कि लोगों को रोजगार प्राप्त करने से सहायता मिलती और सभी इलाकों के कोनों तक लोगों को काम मिलता। उद्योग एक ही स्थान पर अधिक इकट्ठे किये जाते हैं तो इसके साथ–साथ लेबर की प्रोबलम भी खड़ी होती है और उद्योग के विकेन्द्रीकरण से इसकी संभावना कम होती है। स्पीकर साहब, मैं सरकार से, आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि हर जिला स्तर पर फाइनैशल कारपोरेशन की एक–एक ब्रांच की स्थापना की जाए और वह ब्रांच बड़ों की निस्बत छोटे–छोटे यूनिटों को खुले दिल से सहायता दे ताकि लोग जल्दी उनकी तरफ खिंचे और इसी तरह से जिलों में उद्योग धन्धे काफी बढ़ सकते हैं। स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लोन का काफी हिस्सा ट्रान्सपोर्ट में लगा हुआ है और वह भी अधिकतर बड़े–बड़े ट्रान्सपोर्टर्ज को ही मिला है, उन्हें ही केवल इसका फायदा रहा

है। ऐसा होना चाहिये कि बड़ों की बजाये छोटे–छोटे ट्रान्सपोर्टर्ज को भी इससे फायदा हो, कोई इस तरह की तरकीब इन्हें निकालनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि जिनके पास पहले ही बीस–बीस, तीस–तीस ट्रक हों और उन्हें ही वह कारपोरेशन लोन दिये जाए तो वह एक तरह से सरमायेदार को और बढ़ावा देने वाली बात होगी। इसलिये इस फाइनैशल कारपोरेशन को इस तरह से काम करना चाहिये कि जिस से प्रदेश के कोन–कोन में रहने वाले लोग उन द्वारा दी जाने वाली मदद से फायदा उठा सकें। स्पीकर साहब, मैंने कुछ बातें, आपके द्वारा, इस सदन के सामने रखने का प्रयत्न किया है, इसका उदेश्य यह है कि सारे प्रांत के अन्दर हर वर्ग में हर कोने में उद्योग फैलें। मैं इस सरकार से यह आशा रखूंगा कि जो कमियों इस समय रहीं हैं, वह आगे न रहेंगी। इस भेदभाव की नीति को समाप्त कर दिया जाऐगा जिससे कि सारे लोग कदम से कदम मिलाकर चल सकें। स्पीकर साहब, अन्त में मैं फिर कहता हूं और इस सरकार से यह आशा करता हूं कि मैंने इस हाउस में जो सुझाव दिये हैं, सरकार, मेरे इन सुझावों पर ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा वित्त निगम के 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे पर, जो 16 अगस्त, 1972 को सदन की मेज पर रखा गया था, चर्चा की जाए।

श्री ओम प्रकाश गर्ग (थानेसर): अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त चौ. शिवराम वर्मा साहब ने फाइनैशल कारपोरेशन के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं तो इस बारे में, मैं आपकी विसातत के कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में अगर ये फाइनैंशल कारपोरेशन इस हरियाणा में न होती तो इतने उद्योग हरियाणा में न बढ़ते। दूसरे जो इन्होंने जिलावार रिपोर्ट पढ़के सुनाई कि किसी जिले को कम रूपया दिया गया है, किसी जिले को ज्यादा रूपया दिया गया है तो इसके बारे में मैं यह कहूंगा कि यह कोई गवर्नमेंट को देने वाला लोन तो है नहीं, जो भी दरख्वास्त देगा और जो इस कारपोरेशन की शर्तें पूरी करता होगा, लोन उसे ही मिलेगा। मेरे दोस्त वर्मा साहब ने मेरे ख्याल में थानेसर, करनाल वगैरह को देखा होगा कि ये फाइनैशल कारपोरेशन के उठाने के ऊपर उठे हैं। मैं तो यह समझता हूं कि यह कारपारेरेशन ऐसी दियानतदारी और ईमानदारी से काम कर रही है जैसे कि एक बिजनेसमैन करता है। अगर इसी तरह से यह काम करती रहे तो हरियाणा में उद्योग–धन्धे और पनपैंगे और कहीं से कहीं तक पहुंच जाएंगे और तभी हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। मैं इनके काम की काफी सराहना करता हूं और जो इस कारपोरेशन ने काम किया है उसके लिए मैं इनको मुबारिकबाद देता हूं।

चौ. चांद राम: (बबैन एस.सी.): स्पीकर साहब वैसे तो यह ठीक बात है कि यह कापोरेशन अच्छा काम कर रही है। साढ़े

19 करोड़ रूपए क करीब दिया गया है जो इस में दिखाया गया है और उसकी जिलावार तफलील इस तरह है:

	परसैंट
जींद	2
महेन्द्रगढ़	5
करनाल	10
अम्बाला	12
रोहतक	13
हिसार	18

और गुड़गांव में 40 परसैंट दिया है। अब सारे मुल्क में यह आवाज है कि सब जगहों पर बैलैंस्ड डिवैल्पमैंट होनी चाहिए। ठीक है, गुड़गांव में पंजाब के वक्त से हो तरक्की हो रही है, फरीदाबाद का एरिया भी तो हमारे हरियाणा का ही है। मैं इसके कोई खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन जितनी देहली के पास डिवैल्पमैंट हो रही है, चीफ मिनिस्टर साहब भी इसको महसूस करते होंगे, उतनी किसी और जगह पर हरियाणा में नहीं हो रही मगर वहां पर जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं उन्होंने अपने सेल्ज आफिस देहली में रखे हुए हैं और फैक्ट्रीज हमारे हरियाणा में हैं।

इससे हमारी स्टेट को जो टैक्स वगैरह से इनकम होनी होती है उसका नुक्सान होता है। वे कोटा तो हरियाणा का लेते हैं, कन्सैशनल रेट पर जमीन लेते हैं, जो बड़ी फैक्ट्री हैं उनको बीस–बीस तीस–तीस एकड़ जमीन भी मिली हुई है और जो दूसरे यूनिट हैं उनको दो–दा चार–चार एकड़ तो जरूर मिल ही जाती है। तो सुविधाएं तो हमारी स्टेट की हैं और वे कोई वीकर सैक्शन भी नहीं है, खासे अमी लोग हैं, से सब रियायतें लेते हैं लेकिन फायदा हमारी स्टेट को जो होना चाहिए वह नहीं हो पाता। हमारी यह कोशिश होती है कि हमारी स्टेट में जो कारखाने हैं हम उनको मदद दें लेकिन सवाल यह है कि उनसे हमारी स्टेट को क्या फायदा है। बजट तो एक बंटवारा होता है लेकिन बजट की असैंशल कुआलीफिकेशन यह होती है कि वह इस ढंग से खर्च किय जाए जिससे कि उन लोगों की मदद मिले जिनकी आमदन कम है जो वीकर सैक्शन के हैं। बड़े–बड़े आदमियों को तो लोन मिल जाते हैं लेकिन जो छोटे पैमाने पर हाथ से काम करने वाले हैं उनको नहीं मिलता क्योंकि वे जमानत नहीं दे सकते। मुझे कैथल की एक फर्म के बारे में मालूम है, उसको डिस्क हैरोज का इम्पोर्ट लाइसैंस दिया गया और एग्रो–इंडस्ट्रीज वालो ने लिख दिया था कि उनको कोई लेना नहीं चाहता।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): साल भी रैफर कर दो कौन सा था और यह भी बता दो कि सरकासर किसकी थी उस वक्त?

चौ. चाँद राम: किसी की भी सरकार हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो असूल की बात कर रहा हूं।

सदन की बैठक के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष: काम अभ और बाकी है इसलिए अगर हाउस चाहे तो आध घंटा टाईम और बढ़ा दिया जाए।

चौ. बंसी लाल: हां जी, बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय आध घंटा और बढ़ाया जाता है।

हरियाणा वित्त निगम के 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे पर चर्चा (पुररारंभ)

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मैं अर्ज यह कर रहा था कि उसने 39 रूपए के हिसाब से डिस्क हैरो इम्पोर्ट की थी और वह ब्लैक–मारकिट में 164 रूपए में किसानों को दी गई और मेरा ख्याल है कि उस फर्म को फाइनैंशियल कारपोरेशन से भी मदद मिली हुई होगी क्योंकि वह कहते थे कि हमने बिल्डिंग बनानी है, इंडस्ट्री तो उनकी है नहीं सिर्फ डिस्ट्रिब्यूशन सा ही था। इंडस्ट्री तो उसका नाम होता है जहां पर माल बनाया जाए कोई चीज

मैन्युफैक्चर की जाए। तो स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अनबैलैंस्ड डिस्ट्रिब्यूशन है लोन की वह आपको ठीक करनी चाहिए। जब लोन देना है तो आप उनको दें जो हाथ से छोटे स्तर पर काम करते हैं। लेकिन हमने देखा है तो आप उनको दें जो हाथ से छोटे स्तर पर काम करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब लोन के लिए कोई स्माल स्केल पर धंधा करने वाला दरखास्त देता है तो वह जमानत की कण्डीशन को ही नहीं पूरा कर पाते। अव्वल तो जो फार्म हैं वह इतने कम्पलीकेडिट हैं कि उनको आम आदमी भर ही नहीं सकता। इसलिए वे बेचारे इस सुविधा से महरूम रह जाते हैं। लेकिन जो बड़े–बड़े आदमी हैं उन्होंने फार्मों वगैरह के भरने क लिए एक्सपट आदमी रखे हुए हैं और उन्हें वे कहते हैं कि हमें यह सिखा दो कि सरकार की चोरी कैसे करनी है। हमारे हरियाणा में बहुत से परम्परा से कारीगर चले आते है। जैसे, लोहार हैं, लेकिन वे अगर लोन लेना चाहें तो उनको नहीं मिलता क्योंकि उनके पास जमानत नहीं होती। आज मशीनरी का युग आ गया है इसलिए जो परम्परा के कारीगर हैं जैसे लोहार हैं या जुलाहे हैं उनके पास काम नहीं रहा, इसलिए आपको चाहिए कि उनकी मदद करें ताकि वे अपनी रोजी कमा सकें। जो जुलाहे हैं उनको तो मिलों का स्पनयार्न भी नहीं मिलता, खादी बोर्ड वाले शायद उनको कुछ थोड़ा बहुत काम देते होंगे लेकिन यह काफी नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो धानक, जुलाहे और लोहर वगैरह हैं जिनका परम्परा का काम जो वे करते थे इस मशीन के युग में बंद हो चुका है स्टेट की तरफ से ऐसे

वर्ग के लोगों को जो वे करते थे इस मशीन के युग में बंद हो चुका है स्टेट की तरफ से ऐसे वर्ग के लोगों को जो कि बिल्कुल गरीब हैं लोन दिए जाएं। अब यह सारा काम किस ढंग से होना चाहिए यह देखना सरकार का काम है। मदद ऐसे आदमियों को नहीं मिलनी चाहिए जो पहले ही अमीर हैं। सन् 1965 का एक गवर्नमैंट आफ इंडिया का फैसला है कि कोटे, लाइसैंस और जो कर्जे तकसीम होते हैं उनमें भी वीकर वर्गों के लिए वही परसैंटेज मुकर्रर हो जिस हिसाब से नौकरियों में हरिजन और बैकवर्ड लोगों के लिए रखी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक सरकार की तरफ से इस पालिसी पर अमल नहीं किया जाता और जो आप के फाइनैंशियल निगम हैं उनको हिदायतें नहीं जाती कि वे जैसे नौकरियों में रिजरवेशन है उसी हिसाब से वे कोटे और लोन वगैरह हरिजनों और जो दस्तकार हैं, आरटीजन हैं या पुराने ढंग से काम करने वाले हैं उनको दें, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक उन लोगों का भला नहीं हो सकता। सरकार का ऐसा विग होना चाहिए जो परम्परा के कारीगरों की अपने काम चलाने में सहायता करे। ज्वायंट सैक्अर अब चल पड़ा है। मेरा अचानक ध्यान इस बात की तरफ चला गया है। पार्लियामैंट में हमारे बहुत से लीडरों ने तकरीरें की हैं कि इस देश में सरकार का रूपया ज्यादा इन्डस्ट्रीज वगैरह में इनवैस्ट होता है।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, इसका इस रिपोर्ट से तो कोई सम्बन्ध है नहीं।

चौ. चांद राम: मेरे कहने का मतलब है कि जब हम ही ज्यादा रूपया लगा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं तो सरकार ही कारखाने क्यों न खुद लगाये। गवर्नमैंट आफ इंडिया के बहुत सारे अटानोमस बौडीज बने हैं आयरन ऐंड स्टील के लिये अलग है बिजली के लिये अलग है। हमारे यहां भी अलग है और यह कारपोरेशन भी बनी हुई है तो और भी बन सकती हैं। यह नहीं करो कि हैवज को रूपया देते जाओ, अपना पैसा लगाते जाओ और फिर यह कहो कि उसने देश के लिये इतना बड़ा फायदा किया है। सरकार का ही पैसा है सरकार की ही जमीन है तो फिर सरकार को ही इन्डस्ट्रीज लगानी चाहियें और ऐसे लोगों को पैसा देना चाहिये जो हैव नाटस हैं।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): स्पीकर साहब, इस वक्त हरियाणा फाइनैंशियल कारपोरेशन की पांचवीं सालाना रिपोर्ट पर बहस हो रही है। मूल रूप से चौ. चांद राम जी और चौ. शिव राम जी दोनों ही गर्ग साहब से मुत्तफिक हैं कि कारपोरेशन ने काम अच्छा किया है। चौ. शिव राम जी का कहना था कि डिस्ट्रिक्टस के हिसाब से शायद रूपये की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक न हुई हो और चौ. चांद राम जी ने भी एक बात कही कि बगैर किसी सिक्योरिटी के यह जो ट्रैडीशिनल काम करने वाले लुहार वगैरह हैं उनके लिये कोई प्रोविजन किया जाये। स्पीकर साहब, इसके लिये प्रोविजन तो है लेकिन दूसरे कानूनों के तहत है और फाइनैंशल कारपोरेशन इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। फाइनैंशल

कारपोरेशन तो अगर किसी के पा सिक्योरिटी नहीं है तो लोन नहीं देगी और कारपोरेशन तो वहां लोन देगी जहां उसे इस बात की तसल्ली हो कि जो रूपया वह देने चली है उसे खतरा तो नहीं है, जिस यूनिट को पैसा देने जा रही हे वह घाटे में तो नहीं चलेगा, कमी में तो नहीं जायेगा और वह रूपया जो वह देने जा रही है वह इन्ट्रैस्ट के साथ आराम से वापिस आ जायेगा। कारपोरेशन तो यह सारी तसल्ली करने के बाद ही पैसा देगी। चौ. शिव राम और चौ. चांद राम दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि दूसरे इलाकों को भी इन्डस्ट्री में प्रोत्साहन देना चाहिये जो कि पिछड़े हुये हैं। स्पीकर सहाब, हमने रोहतक जिला की नाहड़ सब–तहसील, झज्जर, तहसील के कुछ इलाके, पूरा महेन्द्रगए जिला और जींद, हिसार के जिले इन इलाकों के लिये हमने यह किया है कि जो आदमी इन इलाकों में इन्डस्ट्री लगायेगा तो उसे उस आदमी के मुकाबले में जो बहादुरगढ़, सोनीपत, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में लगायेगा ज्यादा रियायतें देते हैं और ज्यदा फैसिल्टीज देते हैं। लेकिन उन इलाकों से इन्डस्ट्री लगाने वाला आदमी तो कोई सामने आये। मैं माननीय सदस्यगण की एक बात मानने के लिये तैयार हूं कि प्रोत्साहन दें और वह हमने दे रखा है और उससे भी ज्यादा देने के लिये तैया हैं लेकिन मैं आपके जरिये स्पीकर साहब, इन दोनों मैम्बर साहबान से कहूंगा कि उन इलाकों से इन्डस्ट्री लगाने वाला आदमी तो हमारे पास लायें चाहे देहाती हो, गरीब हो या कोई हो, कायदा कानून तो पूरा करना पड़ेगा लेकिन जितनी रियायतें हम दे सकते हैं उतनी हम देंगे।

चौ. चांद राम जी ने एक बात यह कही कि जो बड़ी–बड़ी कम्पनियां हैं और इंडस्ट्रीज हैं उनके हैड आफिस भी और सेल आफिस भी देहली में हैं। तीन–चार साल पहले तो यह बात बहुत सही थी लेकिन अब भी यह बहुत गलत नहीं है। कुद इन्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके हैड आफिस देहली में हैं लेकिन हम धीरे–धीरे कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में कामयाब भी हो रहे हैं। बहुत सार इन्डस्ट्रीज के हैड आफिस और सेल आफिस हमारे प्रांत में आ गये हैं और जाते जा रहे हैं। इसके अलावा एम्पलायमैंट का जहां तक सवाल है हमारी यह कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी हर इन्डस्ट्री में हमारे स्टेट के लिये जायें और जहां नहीं लिये जाते हैं वहां इस बात की कोशिश भी करते हैं। उन इन्डस्टरियलिस्टस से बात करते हैं कि स्किल्ड लेबर की, स्पैशलिस्टस की जरूरत हो और इन्जीनियर्ज की जरूरत हो तो उनको बाहर से ले आओ। लेकिन आम लेबर हमारे प्रांत की लो और आम लेबर जो हमारे प्रांत की है उसे काम मिल रहा है। एक बात चौ. चांद राम ने यह कही कि अब तो नैशनेलाइज्ड बैंकस जो हैं वे भी गरीब आदमियों को कर्ज देने लग गये हैं। मैं अर्ज करता हूं कि नैशनलाइज्ड बैंकस और फाइनैंशल कारपोरेशन के माली हालात में बड़ा फर्क है। नेशनलाइज्ड बैंकस बहुत कर्ज दे सकते हैं और यह कारपोरेशन जो है यह भी नैशनलाइज्ड बैंकस से पैसा लेती है। इसलिये कारपोरेशन और बैंकस के माली हालात में बड़ा फर्क है, अंतर है। एक बात चौ. शिव राम ने यह कही थी कि इस बात को ध्यान में रखा जाये कि हर जिला में कर्ज बांटा जाये और

कर्ज की डिस्ट्रीब्यूशन रैशनल तरीके से हो। सरकार इस बात का पूरी कोशिश करेगी कि हर जिला में बांट कर पैसा दें लेकिन जैसा कि मैंने आप से अर्ज किया है हर जिला से पैसा लेने वाले आदमी भी तो आने चाहिएं। अगर हर जिला से पैसा लेने वाले आदमी आयें जो सारी शरायत पूरी करते हों तो बड़ी खुशी के साथ हर जिला को देंगे और चौ. शिव राम जी का जो जिला करनाल है वह तो हरियाणा प्रांत की रीढ़ की हड्डी है और अगर यह चाहें तेा उस जिला को उससे भी ज्यादा देने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि वहां से कोई लेने वाले सामने आयें। चौ. चांद राम जी ने यहां बजट का भी रैफ्रैंस दिया हालांकि इस रिपोर्ट का बजट से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी चौ. चांद राम, चौ. शिव राम और दूसरे माननीय सदस्यगण को विश्वास दिलाताहूं कि हम फाईनैंशल कारपोरेशन के काम में जिस तरह गर्ग साहब ने भी कहा कोई पौलिटिक्स नहीं लायेंगे और न लाते हैं। आन मैरिट हर आदमी को पैसा मिलेगा। जो ले सकता है और जिसे मिल सकता है उसी को मिलेगा किसी के रास्ते में रोड़ा नहीं अटकेगा। हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा रूपया ज्यादा से ज्यादा आदमियों के इस्तेमाल के लिये दिया जाये ताकि कारपोरेशन का काम भी अच्छा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी इसका फायदा पहुंचे। चौ. चांद राम जी ने कुछ डिस्क हैरोज का भी जिक्र कर दिया उसके बारे में भी अर्ज कर दूं कि जहां तक मेरा ख्याल है मैंने इसकी इनक्वायरी करवा रखी है और यह राव वीरेन्द्र सिंह के वक्त का काम है। मैं ने विजीलैंस डिपार्टमैंट को

इसकी इनक्वायरी दे रखी है और उस वक्त चौ. चांद राम जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे .....

चौ. चांद राम: मैं तो तीन महीने रहा था फिर निकल गया था।

चौ. बंसी लाल: क्या पता उन तीन महीने में यह हो गया हो (हंसी)।

चौ. चांद राम: इन तीन महीनों में नहीं हुआ बाद में हुआ होगा अब भी हो रहा है और अब भी वे कमा रहे हैं।

चौ. शिव राम वर्मा: मेरा निवेदन है कि यह जो लोन देने का प्रोसीजर है इसे भी और आसान कर दिया जाये।

चौ. बंसी लाल: इसका जो तरीका है उसे ज्यादा आसान करना तो शायद हमारे लिये मुमकिन न हो और मैं हाउस में कोई गलत आश्वासन नहीं देना चाहता क्योंकि रिजर्व बैंक वाले भी और दूसरे भ इसमें आते हैं और खाली हमारे हाथ की बात नहीं है।

हरियाणा भाण्डागार निगम के वर्ष 1967–68 तथा 1698–69 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा

Ch. Ram Lal Wadhawa (Karnal): Sir, I beg to move –

That the Annual Reports of the Haryana Warehousing Corporation for years 1967-68 and 1968-69, be taken into consideration. स्पीकर साहब वैसे तो यह बहुत छोटी–छोटी रिपोर्टस हैं और यह नया–नया अदारा बना है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो बहस तल्ब हो लेकिन मैं इसके बारे में एक दो सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। इस बारे में एक बात तो यह मैं सरकार के नोटिस में लेना चाहता हूं कि जो ऐलोकेशन वेयरहाउसिंग के लिये पांच साला प्लान में होती है, जहां तक मुझे मालूम है उसमें शार्ट फाल है जिसका मतलब है कि पूरे वेयर हाउसिज नहीं खोले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं आपकी विसातत से कहना चाहता हूं कि छोटे किसानों कोसबसे ज्यादा नुक्सान होता है। अगर जगह–जगह पर वेयर हाउसिज खोले जाएं तो किसान अपना अनाज सुरक्षित रख सकता है। आज हालत यह है कि किसान को मजबूरन अपना अनाज मंडियों में ले जाकर बेचना पड़ता है क्योंकि उसके पास स्टोर करने के लिए कोई साधन नहीं होता। इसलिए स्पीकर साहब, मैं आपकी विसातत से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें। जो प्राइवेट गोडाउन्ज हैं उनमें भी माल ठीक ढंग से रखा जाए इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। गैर–सरकारी वेयर हाउसिज में जो माल रखा जाए वह खराब न हो, साईटिफिक तरीके से इन्तजाम करे ताकि सारा माल महफूज रखा जा सके। अगर गोडाउन्ज की चैकिंग की जाए और अच्छे साधन अपनाये जाएं तो जो माल वेयर हाउसिंज में पड़ा हुआ है वह महफूज हो सकता है। किसी किस्म

का लौस नहीं होगा। एक बात जो मैंने इस रिपोर्ट में देखी है वह रिपोर्ट के अपैंडिक्स में दी हुई हैं जिस में वेयर हाउसिज के नाम दिए हुए हैं कि कहां–कहां बने हैं। जो लिस्ट दी हुई है इसमें करनाल का नाम नहीं है। हालांकि अनाज का ज्यादा हिस्सा करनाल में होता है। सबसे ज्यादा अनाज करनाल में होता है लेकिन मुझे देख कर हैरानी हुई कि करनाल में कोई वेयर हाउस नहीं बना हुआ। दूसरी छोटी–छोटी जगहों पर वेयर हाउसिज खोल दिए हैं लेकिन करनाल के अन्दर नहीं खोला गया। मैं आपके जरिए मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस ओर ध्यान दें। मैंने रिपोर्ट की बैलेंस शीट देखी है, इसके अन्दर एक दो आइटम्ज ऐसी हैं जिस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। पेज 10 पर आईटम है:–

Subscribed & Paid up:

From P.S.W.C. in terms of Division Scheme – 1607340

इस आइटम का प्रोवीजन लायबिलिटीज साईड पर है। ऐसेटस साईड में है:

Current Assets:

Due from PSWC in terms of Division Scheme – 523008-85.

यह जो अमाउंट है यह अभी तक वसूल नहीं किया गया। यह एक बहुत बड़ी रकम है इसलिए सरकार को और वेयर हाउसिंग

कारपोरेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी वसूली की जा सके। ऐसेटस साईड में कुछ आईटम्ज और हैं:

Storage charges Recoverable – unsecured good – 32232-98

Sundry Debators unsecured doubtful – 1272-94

जहां तक मैं समझ पाया हूं यह ऐसा अमाउंट है जो वसूल होने वाला नहीं है। कारपोरेशन के अफसरान ने प्रोफिट दिखाने के लिए इस हैड के नीचे यह अमाउंट दे दिया है। यह वसूल नहीं हो सकता। इनके इलावा कारपोरेशन ने जो रूपया खर्च किया है इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है, इस चीज को सरकार ध्यान से देखे। मैंने चन्द सुझाव सरकार के सामने रखे हैं, मैं आशा करता हूं इस ओर सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है –

कि हरियाणा भाण्डागार निगम के वर्ष 1967–68 तथा 1968–69 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार किया जाए।

चौ. चांद राम (बबैन एम.सी.): स्पीकर साहब, मैंने इस पर ज्यादा बातें नहीं करनी है क्योंकि श्री राम लाल जी ने काफी कुछ कह दिया है। मगर एक बात जरूर कहूंगा कि यह रिपोर्टस बहुत पुरानी हैं। ये तो 1967–68 ओर 1968–69 की हैं जब कि आजकल 1972 चल रहा है। यह रिपोर्टस पुरानी हैं, हाउस के सामने लेटैस्ट पोजीशन आनी चाहिए ताकि पता ल सके कि वेयर

हाउसिज कहां–कहां बनाये गये। यह तो मार्च, 1969 तक की रिपोर्ट है, लेटैस्ट, अप–टू–डेट अगर हामरे पास होती तो बहस भी करते। अप–टू–डेट होती तो हमें पता भी चलता कि गवर्नमैंट ने फलां गोदाम खोला है। इसमें एक बात दिखाई गई है और वह यह है कि सरकारी गोदामों को इस्तेमाल न करके प्राइवेट गोदामों को इस्तेमला करते हैं, यह बुरी बात है कि पहले तो गोदाम बनाये जाएं और बाद में खाली पड़े रहें। इस चीज की जांच की जाए कि अगर गोदाम बना हुआ है तो उसको प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? जब खर्च किया है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे सामेन लेटैस्ट रिपोर्ट आनी चाहिए ताकि इन बातों पर विचार हो सके।

श्री अमर सिंह (बवानीखेड़ा एस.पी.): स्पीकर साहब, हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की दो साल की रिपोर्टस, 1967–68 तथा 1968–69 हाउस के जेरेबहस हैं। मैं इस रिपोर्ट की बाबत इतना ही कहना चाहता हूं कि वेयर हाउसिंग स्कीम है यह किसान के हित की स्कीम है। 1967–68 से पहले जब वेयर हाउसिज नहीं थे तो प्राइवेट कारखानों में गो–डाउन्ज बना दिए जाते थे और उनसे लाभ उठाते थे। जनाब स्पीकर साहब, आप भी पब्लिक अकाउंटस कमेटी के मैम्बर रहे हैं। आपके नोटिस में बहुत सी बातें आई होंगी। कई केसिज ऐसे होते हैं जहां पर गवर्नमैंट के गोडाउन्ज होते हुए भी सरकार कर्मचारी सरकारी तौर पर अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्राईवेट गोडाउन में अनाज

ले जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर यह बात नोटिस में आई है कि महज अदला बदली .....

श्री अध्यक्ष: रिपोर्ट में जो कुछ प्रकाशित है उसके बारे में कहें।

श्री अमर सिंह: अच्छा जी। मैं कह रहा था कि मान लो गवर्नमैंट गोडाउन में 2 लाख टन गेहूं रखा हुआ है। उसी तरह प्राइवेट गोडाउन भी बना हुआ है। प्राइवेट गोडाउन और गवर्नमैंट के गोडाउन साथ–साथ बने हैं। जब फ्लड आ गया तो फ्लड से गेहूं चेंज हो गया। गवर्नमैंट का गेहूं खराब बता दिया गया और प्राईवेट का यूं का यूं बना रहा। बहुत सारे केसिज नोटिस में आये हैं जहां इस किस्म की चीजें हुई हैं। इसके इलावा 1967–68 की रिपोर्ट के अपैंडिक्स एक में वेयर हाउसिज की लिस्ट दी है लेकिन हांसी का नाम उस लिस्ट में नहीं है। 20 जगहों पर वेयर हाउसिज बने हैं लेकिन हांसी का नाम तक नहीं है। इसलिए स्पीकर साहब, आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हांसी का इलाका वाटर लागिंग एरिया है। वाटर लागिंग होने की वजह से किसी भी अमैनेटीज को किसानों द्वारा स्टोर करना मुश्किल है, इसलिए ऐसी जगहों पर वेयर हाउसिज बनाये जाएं जिससे किसानों की तकलीफ दूर हो सके। यह इलाका वीट–प्रोडयूसिंग एरिया है। इस कारपोरेशन का मनशा भी यही है कि जो कुछ सिकान प्रोडयूस करता है उसकी प्रोडक्शन को महफूज रखने के लिए वेयर हाउसिज बनाये जाएं। बहुत से प्राइवेट गोडाउन्ज

गवर्नमैंट ने लिए हैं लेकिन उन की प्रोटैक्शन नहीं होती। सरकार गोडाउन्ज की प्रौटेक्शन होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां पुरानी रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिए वहां लैटैस्ट 1970–71 और 1971–72 की भी आनी चाहिए क्योंकि नई में ज्यादा इन्फर्मेशन होती है और यह भी पता चलता है कि कितने वेयर हाउसिज बने हैं। 1967–68 में 18 बने थे। और 1968–69 में इनकी संख्या 20 तक पहुंची। एक साल में सिर्फ दो की बढ़ौतरी हुई हैं। अगर यही रफ्तार चलती रही तो काम नहीं चलेगा।

कृषि मंत्री (चौ. भजन लाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन पर चर्चा हो रही थी। इसके बारे में मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहूंगा कि जिस वक्त पंजाब से हरियाणा अलग हुआ उस वक्त वेयरहाउसिंग की पूंजी, शेयर कैपिटन 16 लाख रूपये थी और आज हमारी शेयर कैपिटल 2 करोड़ रूपये है। (तालियां) उस वक्त गोडाउन्ज की कैपेसिटी 7 हजार टन थी लेकिन अब हमारे गोडाउन्ज की कैपेसिटी मार्च तक 1 लाख पांच हजार टन की हो जाएगी। इसके अलावा सन् 67–68 और 68–69 में एक–एक लाख रूपये की हर साल इन्कम हुई लेकिन आज मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी महसूस होती है इस साल तीन लाख रूपए का प्रौफिट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को होगा। (तालियां)

स्पीकर साहब, चौ. राम लाल जी ने एक बात कही कि करनाल में वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का केन्द्र नहीं है। मैं सदन

को बताना चाहता हूं कि करनाल में सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन है। जहां सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेश्न हो वहां सरकार अपना केन्द्र खोल नहीं सकती। क्योंकि वहां आलरेडी गवर्नमैंट आफ इंडिया ने खोल रखा है। इसके अलावा मैं एक बात बहुत फख्र के साथ बताना चाहूंगा कि सारे देश के अन्दर हरियाणा प्रान्त एक ऐसा प्रान्त है जहां वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के द्वारा किसानों का माल रखा जाता है। इस साल भी वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन ने 12 हजार टन अनाज किसानों का रखा हुआ है ओर जिसके अगेन्सट बैंकों से कर्जा उन्हें दिलाया हुआ है।

स्पीकर साहब, यह जो 67–68 की रिपोर्ट है इससे हमारी सरकार का वास्ता नहीं है। यह तो चौ. चांद राम जी के वक्त की है। हम तो इनके पिछले कसूरों को ठीक करने पर लगे हुए हैं। (विघ्न)

चौ. चांद राम: इसमें मैं कहां आ गया? (विघ्न)

चौ. भजन लाल: वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन सारे हिन्दुस्तान में हैं.....

चौ. चांद राम: मैं एक सुझाव दूं कि हर ब्लाक हैडक्वार्टर पर इसका एक सैन्टर आप क्यों नहीं खोल देते?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, जब हरियाणा बना था तो 17 जगहों पर वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के केन्द्र थे लेकिन

आज 39 वेयरहाउसिंग केन्द्र हैं और 31 मार्च, 1973 तक इनकी संख्या 45 हो जाएगी।

चौधरी अमर सिंह ने, स्पीकर साहब, कहा कि हांसी में कोई केन्द्र नहीं है। मैम्बर साहब को या तो शायद जानकारी नहीं है या उन्होंने इस बात को जानने कोशिश नहीं की। मैं उन्हें बताना चाहता हं कि हांसी में भी एक केन्द्र खुला हुआ है।

सरकारी संकल्प

श्री अध्यक्ष: अब एक मिनिस्टर औफिशियल रैजोल्यूशन को मूव करेंगे।

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Mr. Speaker Sir, I beg to move –

That this House approves, under sub-section (3) of section 65 of the Electricty (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 to 1948), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of seventy five crores of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan sub-section (1) of that Section.

Mr. Speaker: Motion moved –

That this House approves, under sub-section (3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Cental Act 54 of 1948), the fiation by the State Government of a higher maximum amount of seventy five crores of rupees which the

Haryana State Electricity Board my at any time have on loan under sub-section (1) of that Section.

चौ. चांद राम: आज तो आपने भी इंगलिश बोल दी।

श्री अध्यक्ष: जिस भाषा में मोशन मूव किया गया वैसे मैंने पढ़ दिया।

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, इसके ऊपर कंसिड्रेशन कल शुरू हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि केवल पांच ही मिनट रह गए हैं।

श्री अध्यक्ष: शुरू करवा देते हैं, कल डिसकशन जारी रहेगी।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, फैसला यह हुआ था कि दोनों पर बहस इकट्ठी होगी।

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, बात यह है कि मेरे रैजोल्यूशन पर तो वोटिंग होनी है लेकिन इसके ऊपर खाली डिसकशन होनी है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा एक साथ हो जाए तो क्या हर्ज है?

चौ. बंसी लाल: प्रोसीजरल इर्र–रैगुलैरिटी न हो तो चर्चा बेशक हो जाए। अगर प्रौसीजरल इर्र–रैगुलैरिटी होती हो तो वह आप देख लें।

श्री अध्यक्ष: एक तो औफिशियल रैजोल्यूशन है .....।

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब यह तो हो सकता है कि कुछ मैम्बरों को इस मोशन पर बोलने का टाईम दे दें और कुछ को दूसरे प्रस्ताव पर बोलने का दे दें क्योंकि सबजैक्ट मैटर दोनों के बोलने का एक ही होगा। कुछ आदमियों को औफिशियल रैजोल्यूशन पर बोलने दें और कुछ को नौन औफिशियल प्रस्ताव पर। बात एक ही है।

बहुत से सदस्य: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक हैं पहले औफिशियल रैजोल्यूशन पर बहस हो जाएगी और वोटिंग हो जाएगी फिर चौ. राम लाल जी अपना प्रस्ताव पेश कर देंगे।

चौ. हरद्वारी लाल: अब तो दो मिनट रह गए हैं, कल ही शुरू करें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: आप शुरू कर दीजिए, कल आप कंटिन्यू करेंगे।

चौ. हरद्वारी लाल (बहादुरगढ़): स्पीकर साहब, मैं 1962 से मैम्बर रहा हूं और इस 10 साल के अर्से में तीन बड़े मसले रहे हैं। हरेक मैम्बर की कारगुजारी इस बात से नानी गई है कि कितने तो अपने हल्के में स्कूल बनवा दिए, कितने मोघे ठीक करवा दिए और अपने हल्के के कितने देहात में बिजली ले आए।

1967 तक मेरे लिऐ तो सबसे ज्यादा यह बिजली का सिलसिला परेशानी का रहा। मेरे हल्के का सबसे बड़ा गांव मांडोठी है। उस जिले का ही वह सबसे बड़ा गांव होगा क्योंकि उसकी आबादी करीब 10–12 हजार है। 1968 तक उसमें बिजली नहीं आई थी। 1967 के अन्दर यह जब चौ. चांद राम जी भी थे इन्होंने तीन महीने के अन्दर तो कुछ नहीं किया लेकिन मैंने स्कूलों का सिलसिला ठीक कर दिया। (हंसी) मैंने सारी ठीक बातें की थीं। (विघ्न) तो स्पीकर साहब, यह स्कूलों का सिलसिला तो ठीक हो गया लेकिन बिजली की फिर भी बहुत मुश्किल हो गई थी। सन् 1968 में मैं बड़ा घबराया क्योंकि चौ. बंसी लाल जी की गवर्नमैंट हुई। 1967 के अन्दर हमारी गवर्नमैंट जनसंध के रहम पर तो थी ही और चौ. बंसी लाल के हल्के में मेरे एक जनसंधी साथी ने सियासी दबाव से एक ऐसी गलती करवा दी जिसे मैं उस वक्त गलती मानता था और जानबूझकर कर मुझे करनी पड़ी। यह डैमोक्रेसी की लानत है स्पीकर साहब!

एक सदस्य: जराब ता खोल ही दो।

चौ. हरद्वारी लाल: मैं खोल यह दूं कि एक गांव में जहां बिल्डिंग नहीं थी उसका तो हाई स्कूल बन गया और जिसकी बिल्डिग थी उसका हाई स्कूल तोड़ दिया गया। शायद यही बात थी?

चौ. बंसी लाल: बिल्कुल यही बात थी।

चौ. हरद्वारी लाल: इससे बुरी बात हो नहीं सकती। मैं खुद मानता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब समय हो गया है।

चौ. हरद्वारी लाल: ठीक है जी। मैं कल सुबह जारी रखूंगा।

श्री अध्यक्ष: सदन कल प्रायः काल साढ़े नौ बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

1.30 मध्यान्पोरान्त

(इस समय सभा 23 अगस्त, 1972 के 9.30 बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हो गई)